खण्ड-222, अंक-5
शुक्रवार, 24 चैत्र, शक संवत् 1883
(14 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 222 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १४ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३१२

अक्षयवर सिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
छतरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
(मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
(गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह, राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेतीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री

भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री

लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १४ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर में तीसरी शिफ्ट बन्द करने का नोटिस

**१—श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर के मैनेजमेंट ने मिल की तीसरी शिफ्ट को बन्द कर देने के लिये नोटिस दे दी है ? यदि हां, तो इससे कितने मजदूर बेकार हो जायेंगे और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम उप मंत्री (श्री वसी नकवी)—सरकार के पास अब तक कोई ऐसी सूचना या नोटिस नहीं आई है ।

शेष प्रश्न के उत्तर का सवाल नहीं उठता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि स्वदेशी काटन मिल के मालिकों ने यह कहा था कि उनको कुछ कठिनाइयां हैं जिससे वह एक शिफ्ट बन्द करेंगे ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—लेबर कमिश्नर से भी बात-चीत हुई थी, सरकार को यह ज्ञान है । अगर कुछ हुआ होगा तो वहीं हुआ होगा, अभी कोई कांक्रीट शेप नहीं लिया है, अभी हमारे पास नहीं आया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तीसरी शिफ्ट के फलस्वरूप ही सोमवार और शनिवार को हड़ताल हो चुकी है और अब भी आन्दोलन जारी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हड़ताल तीसरी शिफ्ट के लिये नहीं है, घंटे के लिये है । उसके लिये सवाल पहले हो चुका है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चूंकि तीसरी शिफ्ट मिल मालिक की ओर से बन्द होने वाली है, इसीलिये वह काम के घंटों को बढ़ा रहे हैं ? पहली, दूसरी शिफ्ट में उधर के काम का जो घाटा होगा, उधर पूरा करने के लिये और वही तार-तम्य मिलाने के लिये, जो काम के घंटे बढ़ाये जा रहे हैं, उसके विरोध में हड़ताल हुई है ?

श्री वसी नकवी—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नही हैं ।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—क्या श्रम मंत्री जी इस बात की जानकारी करा लेंगे, जैसा उन्होंने जवाब दिया है कि कोई इत्तला नहीं है, तो श्रम विभाग, कानपुर के जरिये से मालूम करेंगे कि कोई ऐसा नोटिस मिल मालिकों ने दिया है ? क्योंकि संघर्ष हो जाने के बाद इत्तला मिलेगी तो एक नया प्रश्न उठेगा, इसलिए क्या पहले से जांच करा लेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मेरे पास रोजाना करीब-करीब सारी इनफार्मेशन आती है । हम वाकिफ हैं अच्छी तरह से ।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १–२ श्री गोविन्द सिंह बिष्ट ने पूछे ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

बन्दियों को कपड़ा धोने के लिये साबुन

*१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १९५५-५६ की उत्तर प्रदेश जेल उद्योग की जांच समिति ने तथा बन्दियों और मुक्त बन्दियों के सम्मेलन ने, जो १९५७ में हुआ था, कैदियों को कपड़ा धोने के लिये सज्जी मिट्टी देने के बजाय कपड़ा धोने का साबुन दिये जाने की सिफारिश की थी और सरकार ने इसे मान लिया था ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां ।

*२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त सिफारिश के अनुसार वित्तीय वष १९६०-६१ में प्रदश के किन-किन जिलों में कपड़ा धोने के लिये कैदियों को साबुन दिये जाने का निश्चय किया गया है तथा अगस्त, १९६० तक किन-किन जेलों में यह योजना कार्यान्वित हो चुकी है ?

डाक्टर सीताराम—वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में सरकार ने केवल प्रदेश के सभी केन्द्रीय कारागारों तथा सम्पूर्णानन्द शिविर, मंझौला के लिये जेल द्वारा उत्पादित साबुन दिये जाने का निश्चय किया था । चूंकि केन्द्रीय कारागार, आगरा में साबुन का उत्पादन मास सितम्बर, १९६० से आरम्भ हुआ, अतः अगस्त, १९६० तक किसी भी कारागार में योजना लागू न हो सकी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि साबुन उत्पादन शुरू होने के बाद से किन-किन जिलों में यह योजना लागू कर दी गई है ?

डाक्टर सीताराम—यह प्रश्नोत्तर में ही बतला दिया गया है कि केन्द्रीय कारागारों में यह योजना लागू की गई है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार इसको स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि इस योजना के कार्यान्वित किये जाने से सरकार को आर्थिक लाभ होने के अतिरिक्त क्या बन्दियों को भी किसी प्रकार का लाभ पहुंचा है ?

डाक्टर सीताराम—बन्दियों को यह लाभ पहुंचा है कि साबुन के धुले कपड़े अधिक अच्छे लगेंगे । केन्द्रीय कारागारों के लिये १९,७०० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बाकी कारागारों में यह योजना कब से लागू कर दी जायगी ?

डाक्टर सीताराम—१९६१-६२ में १३ फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट जेल्स में यह स्कीम लागू करने की योजना है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि केन्द्रीय कारागारों में जहां सज्जी की जगह साबुन दिया जा रहा है वहां सज्जी पर पहले कितना खर्चा होता था और अब साबुन पर कितना खर्चा होता है ?

डाक्टर सीताराम—सज्जी तो रेह को कहते हैं । उस पर कितना खर्चा होता था, इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी लेकिन जहां तक साबुन का संबंध है केन्द्रीय कारागारों में १९,७०० रुपये का खर्चा प्रत्येक वर्ष होगा ।

रोडवेज में आजाद हिन्द फौज के आदमी

*३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में आजाद हिन्द फौज के कितने भूतपूर्व सिपाही किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—इस प्रकार की कोई सूची नहीं रखी जाती है ।

*४—श्री उग्रसेन—क्या मंत्री परिवहन यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों पर दक्षता सम्बन्धी रोक लगी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे हटा कर उन्हें तरक्की देने पर भी विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—माननीय मंत्री जी ने बताया कि आजाद हिन्द फौज के जो लोग रोडवेज में हैं, उनकी सूची नहीं रखी जाती, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की सूची रखी जाय तो उसमें माननीय मंत्री जी को क्या एतराज है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस तरह तो तरह-तरह की सूची बनाये जाने का सजेशन आ सकता है, उसमें दिक्कत हो सकती है । इसलिये अलाहिदा-अलाहिदा इस तरह की कोई सूची नहीं रखी जाती है ।

नैपाल से लाई जाने वाली चरस की बरामदगी

*५—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६० से १ जनवरी, १९६१ तक नैपाल से उत्तर प्रदेश में आने वाली कितनी चरस कितने व्यक्तियों से बरामद की गयी ? उनमें कितनों पर कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*६—श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)—क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त अवधि में नैपाल बार्डर पर स्थित टनकपुर की चेकपोस्ट ने इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्रि हो जायगी ?

डाक्टर सीताराम—१७ जिलों से सूचना मंगाने में देर होगी, लेकिन आशा की जाती है कि वह जल्दी आ जायगी ।

गोंडा जिले में जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन रुकना

*७—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले के जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का माह अक्तूबर, १९६० तक लगभग पांच मास के वेतन का वितरण नहीं हुआ था ? यदि हां, तो क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५—६ श्री गोविन्दसिंह विष्ट ने पूछे ।

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)---इस सम्बन्ध में अभी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सीतापुर जिले में कक्षा ६ की फीस की रिइम्बर्समेंट ग्रांट न मिलना

*८---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सीतापुर जिले के मान्यता प्राप्त प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को कक्षा ६ की फीस की रिइम्बर्समेंट ग्रान्ट जनवरी, १९६० से आज तक नहीं मिली है ?

आचार्य जुगलकिशोर---पूर्ण सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*९---श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)---अगर हां, तो क्यों और सरकार इस ग्रान्ट को दिये जाने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---पूर्ण सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आवर्तक अनुदान न पाने वाले आजमगढ़ जिले में उच्चतर माध्यमिक स्कूल

*१०---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में ऐसे कितने उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं जिन्हें कई वर्षों से मान्यता प्राप्त है परन्तु अब तक आवर्तक अनुदान नहीं प्राप्त हो सका ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---केवल ७ ।

*११---श्री विश्रामराय---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को भवन इत्यादि के लिये अनुदान प्राप्त करने के लिये आवर्त्तक अनुदान प्राप्त कर लेना जरूरी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाने का विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

जी नहीं ।

श्री विश्रामराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन ७ मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अब तक क्यों सहायता नहीं मिली है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस अनुदान के देने के लिये नियम हैं जिनके अन्तर्गत विचार किया जाता है, जैसे छात्रों की संख्या, परीक्षा-फल, पर्याप्त मात्रा में नियमानुसार एनडाउमेंट फंड और सुरक्षा फंड का होना, सुयोग्य अध्यापकों का होना और अधीनस्थ अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर विचार किया जाता है ।

श्री विश्रामराय---इन ७ में से कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें यह शर्तें पूरी हैं और किनमें नहीं हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इनके मुकाबले में और विद्यालयों की शर्तें और परीक्षा फल अच्छा था जिनको अनुदान दिया गया । स्पष्ट है इन ७ से अच्छे थे । इस जिले में वैसे ३८ को अनुदान दिया जा चुका है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---जिन स्कूलों को आवर्त्तक अनुदान नहीं मिलता है उनको किसी प्रकार का अनुदान न देने का कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कारण स्पष्ट है कि अनुदान की फेहरिस्त पर आने के पहले यह जरूरी है कि जो शर्तें हैं उनको पूरा किया जाना चाहिये और विद्यालयों की तरह। साथ-साथ यह बात जरूर है कि इंस्टीट्यूशन्स और उनके कार्य के लिये जो विवेक धन कोष है, उसमें से भी विद्यालयों को दिया जा सकता है, जो बजट में शामिल नहीं होता है, उसमें से देने का विचार हो सकता है। लेकिन वह अनराशि थोड़ी ही है।

हरिद्वार तथा ऋषिकेश के निकट शराब की दूकानें

*१२---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नये वित्तीय वर्ष में हरिद्वार और ऋषीकेश के आस-पास कहां-कहां शराब की दूकानें खोली जा रही हैं और वे दूकानें इन दोनों तीर्थों से कितनी-कितनी दूरी पर रहेंगी ?

डाक्टर सीताराम---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१३---श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये दूकानें कितनी हैं और इनका वार्षिक ठेका क्या है ?

डाक्टर सीताराम---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री व्रजविहारीलाल मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन तीर्थ स्थानों पर शराब की दूकानें खोलने की क्यों जरूरत पड़ी ?

डाक्टर सीताराम---यह कहना कि तीर्थ स्थानों पर बिकवायी जा रही है, ठीक नहीं प्रतीत होता। इसीलिये वह वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एक जिले का सवाल है, हरिद्वार और ऋषिकेश का, तो जब कि यह प्रश्न मार्च में रखा गया था, क्यों इतनी देर लगायी गयी एक जिले से सूचना मंगाने में ?

डाक्टर सीताराम---एक ही जिला नहीं है,बल्कि कई जिले शामिल हैं, इसीलिये देरी हो रही है।

अन्तरिम जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*१४---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या अन्तरिम जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के अध्यापकों का कई माह का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो कितने माह का ?

आचार्य जुगल किशोर---जी नहीं।

नोट---तारांकित प्रश्न १२-१३ श्री रामदुलारे मिश्र ने पूछे।

जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालयों में क्लर्कों के स्थायित्व पर विचार

*१५—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अन्दर जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालयों में काम करने वाले ऐसे लिपिकों (clerks) की जिलेवार संख्या क्या है जिनको कार्य करते हुये १० साल या १० साल से अधिक हो चुके हैं पर जो अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं? उनके स्थायी करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—

१ फर्रुखाबाद
१ शाहजहांपुर
१ पौड़ी-गढ़वाल
१ टिहरी-गढ़वाल

दो का स्थायीकरण विचाराधीन है। शेष दो को अभी नियुक्ति सम्बन्धी परीक्षा पास करना है।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बतायेगी कि जो सूची दी हुई है उनमें से कौन से दो व्यक्तियों का मामला विचाराधीन है?

श्री रामस्वरूप यादव—सर्वश्री अविनाश चन्द्र सक्सेना और जगदीश प्रसाद अखौरी।

श्री होरीलाल यादव—मन्त्री जी बतायेंगे कि कब तक विचार हो जायगा और उनको स्थायी कर दिया जायगा?

श्री रामस्वरूप यादव—यह बताना सम्भव नहीं है. लेकिन विभाग जल्दी ही कोशिश कर रहा है।

प्रारम्भिक अनुदान न पाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

*१६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष तक प्रदेश में कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रारम्भिक अनुदान भी नहीं मिलता है?

श्री रामस्वरूप यादव—२१३।

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को कब तक प्रारम्भिक अनुदान प्राप्त हो जायंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक।

जे० टी० सी० तथा नार्मल ट्रेनिंग में हरिजन प्रशिक्षार्थियों को छात्र-वृत्ति

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०-६१ में कितने हरिजन छात्र जे० टी० सी० और नार्मल की ट्रेनिंग में सरकार द्वारा भेजे गये और उनमें से कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है?

श्री रामस्वरूप यादव—जे० टी० सी० ट्रेनिंग के लिये शासन द्वारा दस हरिजन अभ्यर्थी मनोनीत किये गये थे। इनमें से ७ को छात्रवृत्ति मिल रही है।

नार्मल ट्रेनिंग के लिये २८ हरिजन अभ्यर्थी मनोनीत किये गये थे, इनमें से प्रत्येक को छात्रवृत्ति मिल रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि तीन हरिजन छात्रों को, जो जे० टी० सी० में हैं, उनको छात्रवृत्ति न देने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कारण यह है कि इन छात्रों को प्रदेशीय सरकार ने छात्र-वृत्ति सहित नहीं मनोनीत किया था तथा कोई अन्य छात्रवृत्ति भी उपलब्ध न होने के कारण उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जे० टी० सी० और नार्मल में अलग-अलग कितने छात्रों की भरती हुई थी और तादाद में हरिजन छात्र क्यों नहीं लिये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—भरती होने वाली दूसरी बात है। यह प्रश्न तो मनोनीत करने से सम्बन्धित था जो सरकार ने नामजद किये थे। तो मैंने कहा है कि एच० टी० सी० में २८ थे जिनको छात्रवृत्ति मिलती है और इसमें १० आये थे जिनमें से ७ को छात्रवृत्ति मिल रही है।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छात्रवृति में कितना पैसा माहवार दिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा मुझे स्मरण है कि एच०टी०सी० को २० रुपया और जे० टी० सी० को ३० रुपया शायद मिलते हैं।

श्री अध्यक्ष—पक्का मालूम हो तो बतलाइये नहीं तो फिर संशोधन वक्तव्य देना होगा।

श्री रामस्वरूप यादव—'शायद' तो लगा दिया है।

श्री अध्यक्ष—आप सूचना मांग लीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना दे दी जाय।

तारांकित प्रश्न

*१-३—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—[११ अप्रैल, १९६१ को प्रश्न ६-८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानियों को पेन्शन तथा सहायता

*४—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—दिनांक २१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १८ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में १५,७४,००० रुपयें की धनराशि से अधिक धनराशि वितरित हुई ? तो कुल कितनी धनराशि स्वतंत्रता-संग्राम के सेनानियों को इकट्ठी पेंशनें तथा एकमुश्त सहायता देने में वितरित की गई है ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)—वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों की पेंशनों तथा एकमुश्त सहायता की मद में १५,९०,८१३ रुपये खर्च हुये।

*५—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक जिले में इस धनराशि का कितना-कितना अंश वितरित हुआ ?

श्री कृपा शंकर—वांछित सूचना इकट्ठा करने में जो श्रम तथा समय लगेगा वह इन प्रश्नों की उपयोगिता को देखते हुये लाभप्रद न होगा।

*६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि उक्त वितरित धनराशि में सबसे अधिक और सबसे कम धनराशि किनको दी गई और उनके निवास स्थान का पता क्या है ?

श्री कृपाशंकर—सन् १९५८-५९ में ज्यादा से ज्यादा ५०० रुपये व कम से कम ५० रुपये की एक मुश्त सहायता तथा ज्यादा से ज्यादा ७५ रुपये व कम से कम २० रुपये मासिक पेंशन मंजूर हुई । चूंकि ज्यादा से ज्यादा सहायता बहुत से लोगों को दी गई इसलिये किसी व्यक्ति विशेष का नाम व पता देने का प्रश्न नहीं उठता । कम से कम ५० रुपये की एक मुश्त सहायता श्रीमती दुर्गा देवी, १३६, दारागंज, इलाहाबाद को दी गई ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार को ज्ञात है कि ५ नम्बर प्रश्न का उत्तर स्पष्ट न मिलने के कारण लोगों में यह भावना बलवती होती जाती है कि पेंशनों के वितरण में न्याय नहीं किया गया है ? इसको ध्यान में रख कर क्या माननीय मंत्री स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । इस धारणा से कि न्याय होता है या नहीं होता है उससे ५वें प्रश्न के उत्तर से कोई संबंध नहीं है । इसमें यह पूछा गया है कि प्रत्येक जिले में इस धनराशि का कितना अंश वितरित हुआ है, किसी का नाम तो आपने पूछा नहीं है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—प्रत्येक जिले में जो भी अंश वितरित हुआ उसको बतलाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जिलेवार कोई फेहरिस्त रखी नहीं जाती ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पेंशन के सिलसिले में पिछले चार साल से जितने सवाल पूछे गये या जिले की फेहरिस्त मांगी गई तो जवाब यही मिला कि इकट्ठा करने में बड़ा समय लगेगा । तो फिर क्या उपाय है सरकार से जानने के लिये जिलों की फेहरिस्त के बारे में और रुपये के वितरण के बारे में ?

श्री अध्यक्ष—इसमें तो नाम पूछा नहीं गया है ।

श्री गौरीशंकर राय—इस पर मैं नहीं पूछ रहा हूं । जिले की बाबत भी पहले सवाल किया गया लेकिन उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—इस समय तो यह प्रश्न उठता नहीं। आप प्रश्न करके पूछे ।

श्री गौरीशंकर राय—कई बार प्रश्न भेज चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन इस समय तो यह सवाल नहीं उठता है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार किसी ऐसे जिले का नाम, बताने की कृपा करेगी जिसमें अधिक से अधिक सहायता प्राप्त लोग रहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—वह जिले का नाम बतला नहीं रहे हैं। फिर वह कैसे दे दें ? कल्पना से दे दें ?

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—पहले के कार्यक्रम स इस प्रश्न का संबंध है । मैंने पूछा था कि इकट्ठी धनराशि के लिये कितने रुपये की व्यवस्था की गई तो व्यवस्था बतला दी गई । लेकिन जब मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछे तो कहा नोटिस की आवश्यकता है । मैंने नोटिस दे दिया लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया जाता । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बतला देती कि वह प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहती और नहीं देना चाहती तो क्यों नहीं देना चाहती ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस विषय में सरकार को लिस्ट रखने का औचित्य जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, है जरूर। हर जिले के बारे में ऐसी फेहरिस्त तो होनी ही चाहिये और अगर नहीं है तो जब वह प्रश्न उपस्थित करें तो सरकार थोड़ी-सी मेहनत करा ले; क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से जवाब ८–८, १०–१० पेजेज के होते हैं और लिस्टें तैयार होती हैं। इस वक्त सरकार के पास सूचना नहीं है तो आयन्दा अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं इस विषय में जरूर मंत्री जी को लिखूंगा। इसी वजह से मैंने माननीय गौरीशंकर राय को कहा....

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, इस विभाग के जो मंत्री जी थे उन्होंने अपने जिले में बहुत ज्यादा बांट दिया है, जैसे वाराणसी में। इसीलिये सूचना देने में भंडा फूटता है।

श्री मुजफ्फर हसन—इस बारे में मैं थोड़ा-सा अर्ज कर दूं। दिक्कत यह है कि जिस सन् का सवाल पूछा जाता है वह आइसोलेटेड है नहीं, रेकरिंग ग्रांट है जो सन् १९४७ से बराबर दी जा रही है और वह उस सन् में भी शामिल हो जाती है। तो कोई फेहरिस्त सन् १९४७ से आजतक जिलेवार रखी नहीं गई। इसलिये यह एक बड़ा मुश्किल काम है।

श्री अध्यक्ष—अगर आपसे यह सवाल किया जाय कि इस साल हर जिले में आपके कितने पोलिटिकल पेन्शनर्स हैं तो वह आप बता सकेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—उसमें भी दिक्कत होगी लेकिन वह कुछ मुमकिन हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—मैं यह नहीं कहूंगा कि शुरू से आप नाम इकट्ठा करें।

श्री मुजफ्फर हसन—इसमें तो रेकरिंग ग्रांट है जो गुजिश्ता सालों में भी मन्जूर हो चुकी है और वह अदा की गई है।

श्री अध्यक्ष—वह यह जानना चाहते हैं कि कितने शख्स किस जिले में हैं जो पेन्शनर हैं और उनको माहवार या सालाना कितनी रकम दी जाती है, रेकरिंग चाहे वह दी गई हो या न दी गई हो। इसकी तो लिस्ट आपके पास होनी चाहिये नहीं तो आप देते कैसे हैं ?

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—सन् १९५८–५९ के वित्तीय वर्ष में जो पेन्शन दी गई है उसकी फेहरिस्त देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—आप सवाल पूछें तो वह देखेंगे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मेरे इस सवाल को ही नोटिस मान कर क्या माननीय मंत्री जी वह फेहरिस्त देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैंने कह दिया कि इसके बाद जब आप सवाल करेंगे तो देंगे।

अनन्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संतराव का अनुदान के लिये प्रार्थना–पत्र

*७—श्री उग्रसेन—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनन्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संतराव (देवरिया) की ओर से आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान के लिये उनके विभाग में कोई आवेदन-पत्र आया है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, किन्तु सरकार अनुदान प्रदान करने में असमर्थ थी।

*८—श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि अनन्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संतराव, जिला देवरिया ने लगातार ७ वर्षों से सरकार को आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान के लिये आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। इस प्रकार के अन्य आवेदन-पत्रों के साथ इस पर भी विचार किया गया किन्तु सरकार इस संस्था को अनुदान देने में असमर्थ थी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि इतना पुराना विद्यालय, संतरविद (देवरिया) का है और लगातार कई वर्षों से आवर्तक और अनावर्तक अनुदान के लिये आवेदन-पत्र देता रहा है और उप-विद्यालय निरीक्षक ने भी कई बार संस्तुति की है, फिर भी इस विद्यालय को अनुदान देने में सरकार की ओर से क्यों असमर्थता प्रकट की गई जब कि उसके बाद के, जो विद्यालय हैं, उनको दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, अभी दूसरे प्रश्न के संबंध में मैंने यह उत्तर दिया था कि अनुदान देने के समय इस बात पर विचार किया जाता है कि छात्र संख्या, परीक्षाफल, एन्डाउमेन्ट फंड, सुरक्षित फंड, अधीनस्थ अधिकारियों की संस्तुति, इस योजना का लाभ प्रत्येक जिले में तथा नियमानुसार सुयोग्य अध्यापकों की संख्या। इन सब बातों को देखा जाता है तब अनुदान दिया जाता है। इस विद्यालय का सुरक्षित कोष २ हजार रुपया था जब कि नियमानुसार कम से कम ३ हजार रुपया होना चाहिये। परीक्षाफल की स्थिति यह थी कि सन् १९५६ में २३ प्रतिशत, १९५७ में १८ प्रतिशत और १९५८ में १४ प्रतिशत। इस वजह से इस विद्यालय को अनुदान नहीं दिया जा सका।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि गत वर्ष परीक्षाफल अच्छा हुआ है उनको ग्रांट देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वर्ष विचार करेंगे। १२० विद्यालयों को अनुदान देने का हमारा विचार है, उसमें इस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उनको अनुदान नहीं दिया गया तो क्या उनको लिखा गया था कि इन कारणों से नहीं दे रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह लिखना आवश्यक नहीं है।

निःशुल्क शिक्षा अनुदान के वितरण में परिवर्तन पर विचार

*९—श्री मदन पांडेय तथा श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में कक्षा १ से ६ तक की निःशुल्क शिक्षा से हुई क्षति का भुगतान विद्यालयों को गत दो वर्षों की छात्रों की संख्या के आधार ही पर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या इस नियम में परिवर्तन करने की योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्नगत अनुदान छात्रों की उसी संख्या के आधार पर दिया जाता है जो उस समय थी जब कि अनुदान सर्वप्रथम निर्धारित किया गया था।

इस आधार में कुछ परिवर्तन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह अनुदान किस सन् में देना प्रारम्भ किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, कक्षा १ से ३ तक जुलाई, १९५६ से, कक्षा ४ से ५ तक जुलाई, १९५७ से पढ़ाई शुल्क न लिये जाने की योजना लागू की थी और कक्षा ६ में निःशुल्क योजना सितम्बर, १९५७ में लागू की गई है।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि दर्जा १ से ५ तक की फीस के नुकसान के भुगतान करने की जो राजाज्ञा सरकार की ओर से निकाली गई थी उसमें यह शर्त थी कि विद्यार्थियों की संख्या पर भुगतान किया जायगा ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उसी संख्या को बेसिक मान लिया गया और बढ़ी हुई संख्या के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, वह राजाज्ञा तो मेरे सामने नहीं है लेकिन मैंने उत्तर में कहा है कि उस आधार पर ही परिवर्तन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। श्रीमन्, कुछ तो स्थानीय संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है, उनकी एक कांट्रेक्ट ग्रांट हुआ करती है वह उनको मिलती है, जिसमें दर्जा १ से ६ तक की फीस भी शामिल होती है। दूसरे निजी पाठशालायें हैं, उनके लिये विचार किया जा रहा है। उनकी छात्र संख्या की बढ़ोत्तरी की समस्या पर विचार हो रहा है। इसमें कुछ देर लगेगी। उस पर विचार होने के पश्चात् निश्चित किया जायगा।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनको अधिक अनुदान दिया जाना चाहिये था उनको नहीं दिया गया तो उनको अधिक रकम खर्च करने के लिये कोई उपाय बताया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, न तो किसी ने उपाय पूछा था और न बताया गया।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लड़कों की फीस सरकार देती है उसके बाद बढ़े हुये विद्यार्थियों की फीस ली जाती है या उसकी क्या व्यवस्था है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जहां तक मैं समझा हूं उनका आशय है कि अनुदान किस हिसाब सें दिया जाता है।

श्री गौरीशंकर राय—मेरा आशय यह है कि मान लीजिये कि पहले साल १०० विद्यार्थी थे और अब १५० हो गये तो इन बढ़े हुये विद्यार्थियों से फीस ली जाती है या नहीं ? और कैसे इनको छांटा जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं यह समझता हूं कि फीस नहीं लेते होंगे लेकिन ग्रांट हम उसी हिसाब से दे रहे हैं जो पहले निश्चित की गई थी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि सरकार की ओर से डेफीनिट उत्तर दिया जाय कि जो विद्यार्थियों की बढ़ोत्तरी हुई है उनको सरकार फीस नहीं देती है और उनसे फीस ली जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि फीस ली जाती है। फीस नहीं ली जाती होगी (व्यवधान) मैंने पहले ही उत्तर दे दिया कि पहले से सरकार कितना देती थी और अब जो छात्र संख्या बढ़ गई है, उसके हिसाब से कितना देना चाहिये, यह विचाराधीन है।

श्री राजनारायण—अगर फीस ली जाती होगी, तो वह पैसा गवर्नमेंट देगी ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अगर कहीं फीस ली गई हो तो आप उतना रुपया उनको वापस दे देंगे, जब कि आप का विचार हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—वापस तो नहीं देंगे। हमारा तो आगे देने का विचार है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, १९५७ में जब दर्जा ६ की फीस माफ की गई तब यह भी वादा किया था सरकार ने कि १९५८-५९ में सातवें और आठवें की फीस भी माफ कर दी जायगी ? सरकार ने अपने उस वादे को अब तक पूरा क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था लेकिन हमारे पास रुपया नहीं था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो आधार परिवर्तन करने का है वह क्या है, और कब तक परिवर्तन हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---फीस माफी के सिलसिले में प्रथम वर्ष में जो निश्चित किया गया था उतना ही दिया जा रहा था लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि कितनी छात्र संख्या बढ़ गई है और कितना दिया जाना चाहिये, उसके आधार पर विचार किया जा रहा है।

नवीन डिग्री कालेज तथा विश्वविद्यालय खोलने की योजना

*१०---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में कितने डिग्री कालेज एवं कहां-कहां विश्वविद्यालय खोले जाने की योजना है ?

श्री रामस्वरूप यादव---केवल एक राजकीय डिग्री कालेज, श्रीनगर में खोलने का प्रस्ताव है। गैर-सरकारी डिग्री कालेज खोलने का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया है क्योंकि उनका खुलना सार्वजनिक साधनों पर निर्भर रहता है। मेरठ, कानपुर तथा नैनीताल में विश्व-विद्यालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो गैर-सरकारी डिग्री कालेज खोले जाते हैं, उनको सरकार किस आधार पर और कब से सहायता प्रदान करती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उनको प्रथम तीन वर्ष में कुछ नहीं दिया जाता है। तीन वर्ष के बाद जो उनके रिटर्न आते हैं, उनके आधार पर यदि शासन के पास धन उपलब्ध होता है, तो दिया जाता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जो यह देखते हुये कि नैनीताल में डिग्री कालेज है और नैनीताल जिले में रुद्रपुर विश्वविद्यालय भी है और गढ़वाल के क्षेत्र में एक डिग्री कालेज खोलने जा रहे हैं, तो क्या वह विचार करेंगे कि कुमायूं विश्वविद्यालय जो खुले वह अल्मोड़ा में हो ताकि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बाकी जिलों के काम आये ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी कुमायूं विश्वविद्यालय के खोलने ही पर विचार हो रहा है कि खोला जाय या न खोला जाय। अल्मोड़ा का प्रश्न कहां उठता है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब तीन वर्षों के बाद सरकारी सहायता देना निश्चित है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ धन इसके लिये सुरक्षित है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---धन तो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---मंत्री जी ने कहा कि नियम यह है कि तीन साल के बाद अनुदान शुरू कर देते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि धन उपलब्ध होने की शर्त क्यों लगाई जाती है ?

श्री अध्यक्ष---अगर धन उपलब्ध न हो तो अपने पास से थोड़े ही दे देंगे।

*११---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों व आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा

*१२—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों की शिक्षा निःशुल्क कर दिये जाने के विषय में ८ दिसम्बर, १९५८ को प्रश्नकर्त्ता के तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इस विषय में भारत सरकार का आखिरी जवाब अब प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उसके अनुसार क्या फैसला हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों और आश्रितों को निःशुल्क और अर्धशुल्क की सुविधा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक दिये जाने के आदेश १०-३-१९६१ को जारी हो चुके हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुछ विद्यार्थियों की आधी फीस माफ रहेगी और कुछ की पूरी माफ रहेगी तो इसका आधार क्या रखा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—स्थानीय संस्थाओं के जो आचार्य हैं वह यह देखेंगे कि किसकी जरूरत ज्यादा है और कौन योग्य लड़का है, उसके आधार पर ही वह आधी और पूरी फीस माफ करेंगे। यही आधार उनके सामने होना चाहिये।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से ऊपर के क्लासों में भी यह फीस माफ रहे ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनके बारे में तो अभी विचार नहीं है। उनको वजीफे दिये जाते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १० मार्च, १९६१ को आदेश जारी किये गये हैं वह क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने पहले भी बता दिया है कि पहले आठवें दर्जे तक की फीस को आधी और पूरी माफ करने की सुविधा देते थे, अब १२ वें दर्जे तक कर दिया गया है। अब यह रकम ३,७९,२८० रुपये हो गई है। पहले इसकी आधी ही थी। अब आधा केन्द्रीय सरकार ने दे दिया इसलिये उसको दूना कर दिया गया है और जो परिभाषा आश्रितों की है वह सीमित कर दी गई है, वह उन बच्चों पर या उन पौत्रों पर जिनके कि पिता जीवित न हों, इस तरह से कुछ तब्दीली उसमें कर दी गई है।

रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में क्लर्कों का रिवर्शन

*१३—**श्री उग्रसेन**—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि पंचांग वर्ष १९६० में राजकीय रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में कितने जनरल क्लर्क्स रिवर्ट किये गये और क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—पांच। यह सीधी भर्ती के कोटे के पदों पर अस्थायी रूप से काम कर रहे थे, और ज्यों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की गईं इनको रिवर्ट होना पड़ा।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब यह पांच व्यक्ति रिवर्ट किये गये उस समय कितनी सीटें सीधे भर्ती होने वालों की खाली थीं और कितनी विभागीय भर्ती की ?

श्री मुजफ्फर हसन—जब इनको पदोन्नत किया गया, उस वक्त तो कोई वेटिंग लिस्ट पर था नहीं। अब २३ आदमी काम कर रहे हैं। पदोन्नति से १२ और सीधे भर्ती से ११ का इस वक्त अनुपात है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो १० और ११ का परमानेंट पोस्ट का कोटा था यह लगातार दो-तीन वर्षों से चला आ रहा था ? यदि हां, तो उस समय जब खाली हुआ, जब परमानेंट पोस्टें आयीं तब क्यों नहीं विभागीय तरक्की और सीधे कोटे से भर्ती कर ली गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—सीधे कोटे के सेलेक्शन में देर हुई और जितनी देर हुई उस वक्त तक ये काम करते रहे ।

लखनऊ—फैजाबाद बस सर्विस पर विचार

*१४—**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ-फैजाबाद रोड पर लखनऊ से फैजाबाद तक रोडवेज की बसें चलती हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मुजफ्फर हसन—अभी नहीं । मामला विचाराधीन है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन-चार वर्षों से बराबर इस बारे में प्रश्न पूछा जाता रहा है और सरकार की तरफ से यही उत्तर मिलता रहा है जो कि आज मिला है, तो क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले पर अब अन्तिम निर्णय सरकार कब तक ले लेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे पिछले सवालों का तो इल्म नहीं है । लेकिन इस साल जो हम नये रूट्स लेने जा रहे हैं उनमें इस पर भी हम विचार कर रहे हैं ।

*१५—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६-१७—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

दोहरीघाट तथा घोसी में बस स्टेशन बनाने पर विचार

*१८—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह दोहरीघाट, घोसी तथा अमिला, जिला आजमगढ़ में रोडवेज स्टेशन का भवन बनवाने की योजना पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त भवन कब तक बन जायेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—सिर्फ दोहरीघाट और घोसी में बस स्टेशन बनाने का मामला विचाराधीन है । जमीन हासिल करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । उसके मिलने पर बस स्टेशन की इमारत बनाने का काम शुरू होगा ।

शिवजतन बन्दी की इटावा जेल से फरारी

*१९—**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या १ फरवरी, १९६१ को दोपहर में इटावा जेल से शिवजतन नामक कैदी भाग गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—इटावा जेल से १ फरवरी, १९६१ को कोई कैदी नहीं भागा । शिवजतन नामक कैदी ३१-१-१९६१ को भागा था ।

[*२०—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

स्वतंत्रता-संग्राम इतिहास समिति का निर्माण

*२१—श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में "स्वतंत्रता संग्राम इतिहास समिति" का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कब और कितनी अवधि के लिये ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । वर्तमान समिति का निर्माण जुलाई, १९५७ में हुआ था तथा इसकी अवधि ३१ जुलाई, १९६१ तक है ।

*२२—श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त समिति में कौन-कौन सदस्य गैर सरकारी व सरकारी हैं, और उसने अब तक क्या कार्य किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६२ पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो वृत्त अभी तक तैयार किये गये हैं वह प्रकाशित हो चुके हैं और क्या पुस्तकालय में पहुंच चुके हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—५ वाल्यूम "फ़्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश" के प्रकाशित हो चुके हैं। "स्वतंत्र दिल्ली" १० मई सन् १९५७ को प्रकाशित हो चुका है। "संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियां" भी प्रकाशित हो चुकी है। "कंसालिडेटेड इंडेक्स "फ़्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश" की १८५९ से १९४७ तक के इतिहास की सामग्री तैयार की जा रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या इन प्रकाशनों के मूल्य ऐसे रखे गये हैं कि वे साधारण व्यक्तियों को भी मिल सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—इस समिति में कितने सदस्य हैं और सरकारी सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—सब से पहले यह सन् ५३ में बनी। उसके स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी सचिव थे। उसके बाद ५५ में पंडित कमलापति त्रिपाठी इसके सचिव थे । इस समय इसमें सरकारी सदस्य श्री मुजफ्फर हसन, श्री आदित्यनाथ झा, आई० सी० एस०, श्री गोबिन्द नारायण, आई० सी० एस०, श्री केहरसिंह, आई०ए०एस० श्री भगवतीशरण सिंह, डाक्टर बी० एस० हैकरवाल, डा० एम० ए०ए० रिजवी, श्री मोहनलाल गौतम, डाक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी, डाक्टर बनारसीदास सक्सेना, पी० मुहम्मद हबीब, डाक्टर रामशंकर त्रिपाठी, तथा श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं ।

श्री राजनारायण—सन् १८५९ से १९४७ तक ही क्यों इतिहास लिखा है, सन् १८५७ से क्यों नहीं लिखा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री मदन पांडेय—उत्तर प्रदेश के इतिहास से यहां के लोगों को अधिक दिलचस्पी होगी तो "फ़्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश" अंग्रेजी में क्यों छपाई है और क्या हिन्दी में उसका उल्था हुआ है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २१–२२ श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछे ।

श्री रामस्वरूप यादव—इस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है।

श्री मदन पांडेय—जब हमारी राज्य भाषा हिन्दी है और हम हिन्दी की ओर निरन्तर बढ़ रहे हैं तो इस प्रथम इतिहास के अंग्रेजी में छापने की क्या आवश्यकता हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किया है "स्वतंत्र दिल्ली" और "संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियां" हिन्दी में हैं।

काशी विद्यापीठ तथा गुरुकुल कांगड़ी को विशेष अनुदान देने की जानकारी

*२३—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि काशी विद्यापीठ तथा गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) का स्वरूप परिवर्तित होने जा रहा है और सरकार इन दोनों महाविद्यालयों को इस निमित्त विशेष अनुदान देने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

एटा भोगांव बस सर्विस पर विचार

*२४—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा) (अनुपस्थित), श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित), श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर) तथा श्री गरीब दास (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सड़क कलां (ग्रांट ट्रंक रोड) दिल्ली से कलकत्ता को जाती है उसका कितना हिस्सा उत्तर प्रदेश में है जिस पर सरकारी बसें नहीं चल रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—केवल ३९ मील।

श्री गरीब दास—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ३९ मील सड़क कहां से कहां तक है और उस पर सरकारी बसें क्यों नहीं चल रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरा खयाल है यह सड़क मैनपुरी से भोंगांव तक है और इसके लिये जाने के लिये कानूनी कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष—मैनपुरी से भोगांव तक ३९ मील नहीं होंगे, कुछ गलत फहमी हो सकती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—वह भोगांव के नाम की वजह से गड़बड़ी हो गई। यह सड़क एटे से भोगांव तक ३९ मील है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि एटे से भोगांव तक सरकारी बसें कब तक आ जायेंगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—उस पर कानूनी कार्यवाही हो रही है और उम्मीद है जल्दी ही आ जायगी।

शिक्षा विभाग के सब-डिप्टी इन्सपेक्टरों को यात्रा भत्ता न मिलना

*२५—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पंचवर्षीय योजनाओं (नियोजन) के संबंध में नियुक्त किये गये शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टरों को गत प्रायः १० महीने से दौरे का भत्ता (T. A.) नहीं दिया गया है ?

श्री राम स्वरूप यादव—कुछ ही जिलों में ऐसी स्थिति धनाभाव के कारण हुई है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन जिले हैं जिनमें एस०डी०आई० को टी०ए० नहीं दिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सहारनपुर, मेरठ, आगरा, नैनीताल, अलमोड़ा, पोड़ी-गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल और बस्ती।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब ये राजकीय कर्मचारी हैं तो इनको टी०ए० क्यों नहीं दिया जाता जब कि इनके लिये यह आदेश है कि महीने में कम से कम २० दिन दौरे पर रहा करें ?

श्री रामस्वरूप यादव—योजनाकाल १९५८ में जिला विद्यालय उप निरीक्षक ११० बढ़ाये गये थे और उनके लिये टी०ए० की मद में १९६०-६१ में ७३,७५० रुपये का प्राविधान था लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वह रुपया थोड़ा होगा और उस रुपये का प्राविधान न होने की वजह से टी०ए० नहीं दे सकें। इस वजह से वह जल्द से जल्द प्राविधान किया जा रहा है। वह रुपया तो देना ही पड़ेगा लेकिन प्रिआडिट के लिये भेजना पड़ेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि कुछ जिलों में तो लोगों का सारा रोक लिया गया और बाकी जिले वालों ने पूरा रेमेंट किया, इसका क्या कारण है ? ऐसा होता तो अच्छा था कि कुछ उनको भी मिल जाता ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह जिले जिनको हम पूरा रुपया देते हैं उसमें से वह टी०ए० का देते हैं। कुछ जिलों ने अपनी बचत करके वह रुपया दे दिया। कुछ जिले अपने पास से नहीं दे पाये। यह मैंने स्वीकार किया है कि रुपये की कमी की वजह से ऐसा हुआ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि जिलों में लोगों ने कैसे यह व्यवस्था कर ली कि कहीं-कहीं तो वह पूरा हो गया और कहीं-कहीं वह पूरा नहीं हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक जिले में निर्धारित धन जाता है और वह कई मदों में जाता है जिला निरीक्षकों के पास। उसमें इसका भी खाता होता है। तो उनको अपने यहां यह अधिकार है कि उसको कम कर लें और उसमें वह रुपया बचा लें लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि किसी तरह से व्यवस्था नहीं हुई और वह नहीं दे सके।

*२६-२७—**श्री माता प्रसाद** (जिला जौनपुर)—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये।]

माडेल स्कूलों के असिस्टेंट टीचर्स का ग्रेड

*२८—**श्री महेश सिंह** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के माडेल स्कूलों में एक ही ग्रेड के असिस्टेंट टीचर्स में दो प्रकार के पे स्केल हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां।

महिला प्रौढ़ शिक्षा विद्यालय, गोंडा का अनुदान बन्द होना

*२९—**श्री मलिखान सिंह** (जिला मैनपुरी) तथा **श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या बलरामपुर, जिला गोंडा में कोई अल्पकालीन महिला प्रौढ़ शिक्षा विद्यालय, समाज कल्याण सलाहकार समिति की देख-रेख में चलता है और क्या इसकी ग्रांट-इन-एड बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

श्री राम स्वरूप यादव—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये परिशिष्ट 'ख' आगे पृष्ठ ४६३ पर)

*३०—श्री मलिखान सिंह तथा श्री मन्नालाल—क्या इस स्कूल की ग्रांट के उपयोग के सबंध मे कोई जांच कराई गई है? अगर, हां तो किसके द्वारा तथा जांच की रिपोर्ट क्या है? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री रामस्वरूप यादव—बांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६३ पर)

श्री मलिखान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह नई कार्यकारिणी बनी या नहीं।

श्री रामस्वरूप यादव—यह सूचना मिली है कि उन्होंने नयी कार्य समिति बना ली है लिहाजा जो ग्रांट रोक ली गई थी उसे ग्रांट देने की सूचना जो सहकार बोर्ड राज्य का है, उसने दे दी है।

श्री मलिखान सिंह—वह ग्रांट नयी कार्य समिति को कबतक मिल जायगी?

श्री रामस्वरूप यादव—केन्द्र को सूचना कर दी गयी है। यह तो अब उस पर है कि वह उसको कबतक मंजूरी दे।

शिक्षा प्रसार निदेशक

*३१—श्री अभय राम यादव (जिला इटावा)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत किन-किन जिलों में और कितने-कितने प्रसार निर्देशक (गाइड्स) काम कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रत्येक जिले में कार्य करने वाले प्रसार निर्देशकों की संख्या संलग्न परिशिष्ठ 'अ' के द्वारा प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६४ पर)

*३२—श्री अभयराम यादव—क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रसार अध्यापकों को अन्य जिलों में भी कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है और प्रसार निर्देशक (गाइड्स) जिले के अन्तर्गत ही काम करते हैं।

श्री राम स्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री अभयराम यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह २०६ प्रसार निर्देशक जो हैं उनको सरकार कितनी तनख्वाह देती है?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, प्रसार अध्यापकों के वेतन-क्रम के दो ग्रेड हैं। एक तो ग्रेजुयेट्स को दिया जाता है और दूसरा उस से कम योग्यता वालों को। उसी हिसाब से उनको वेतन मिलता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये प्रसार अध्यापक शिक्षा के प्रसार के लिये क्या-क्या काम करते हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—यह कृषि शिक्षा के विषय में विशेष शिक्षा देते हैं, अपने विद्यालयों में और जो इसमें प्रश्न है, जो गाइड्स कहलाते हैं प्रसार निर्देशक, वे जिम्मेदार रहते हैं। लेकिन सरकार के सामने यह एक विचार है कि उनको भी पढ़ाने का काम ही दिया जाय और जल्दी ही इस बारे में निर्णय किया जायगा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि विशेष शिक्षा देते हैं उस से उसका क्या तात्पर्य है? उस विशेष शिक्षा का प्रकार क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव—यह कृषि संबंधी विशेष शिक्षा ६ वर्ष से चल रही है। जूनियर हाई स्कूलों में कृषि संबंधी सुविधायें हैं और बेसिक शिक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसके अनुरूप ही उसे रखा जाय और वे इस ओर भी अपना ध्यान रखें इसलिये यह किया गया है। माननीय राजनारायण जी ने शायद उसको पढ़ा नहीं है क्योंकि वह बाद में शुरू हुई थी।

श्री भजन लाल (जिला इटावा)—क्या शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी में ७ प्रसार निर्देशक काम कर रहे हैं और वे जिले के एक ही कार्यालय में काम कर रहे हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों है?

श्री रामस्वरूप यादव—वहां ७ तो काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी निवेदन किया कि यह इस विषय में काफी आगे बढ़ चुके हैं और सरकार का विचार है कि उनको प्रसार निदेशक के बजाय विद्यालयों में पढ़ाने के उपयोग में ही लिया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह प्रसार निदेशक जो जूनियर हाई स्कूलों में कृषि शिक्षा के लिये रखे गये हैं—यह स्कूल तो बहुत बड़ी संख्या में हैं—ये किस प्रकार वहां जा कर कृषि शिक्षा में मदद करते हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—उनके लिये १० विद्यालयों का एक क्षेत्र होता है और उनका यह कार्य है कि उनमें जो कृषि के अध्यापक का कार्य है उसे देखें ताकि दूसरे विद्यालयों में और उनमें फर्क न पड़ने पावे और एक कोआर्डिनेशन हो सके। इसके लिये इनको रखा गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रसार निर्देशक हैं उनको जिले से हटा कर स्कूलों में भेजने का क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव—शुरुआत में तो विचार था कि उनका संबंध जिले से भी रहे और जो इस विभाग से शिक्षा के संबंध में आदेश जायें उन के अनुसार पढ़ाई भी हो और जो नये अध्यापक आये थे उन से ठीक कार्य का संचालन कराया जा सके इसलिये उनको रखा गया था। अब ये ७,८ हो गये हैं और सरकार यह समझती है कि हर अध्यापक अपनी जगह पर काफी कुछ समझ गया है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को कुछ यह आभास हो रहा है कि यह योजना सफल नहीं हुई? यदि हां, तो क्या वे इस पर पुनर्विचार करेंगे और इसमें आमूल परिवर्तन करने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—आमूल परिवर्तन का विचार नहीं है, लेकिन सरकार के सामने यह प्रश्न आते हैं और उन पर विचार होता रहा है कि किस शिक्षा से क्या प्रगति होती रही है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूलों में कोई कृषि योग्य भूमि पहले से नहीं चली आ रही है, तो अब वहां कोई विशेष कृषि योग्य भूमि नहीं है तो यह प्रसार अध्यापक वहां पर क्या काम करेंगे, इसे स्पष्ट करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो श्रीमन्, ठीक ही है कि कृषि योग्य भूमि बहुत से विद्यालयों में नहीं है, लेकिन जहां है वहां पर तो यह शिक्षा देते ही हैं, जहां नहीं है वहां वे किसानों की भूमि पर भी उन छात्रों को ले जाकर उनका कार्य बताते हैं और साथ-साथ कृषि की शिक्षा तो दी ही जाती है।

*३३—श्री रामस्वरूप वर्मा—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

एटा–मैनपुरी बस सर्विस पर विचार

*३४—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा-मैनपुरी लाइन पर सरकारी बसें चलाने के लिये सरकार ने १९६० में गजट किया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर सरकारी बसें क्यों नहीं आ सकी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

*३५–३६—श्री विश्रामराय—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

कालपी–उरई बस सर्विस पर विचार

*३७—राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कानपुर से कालपी जिला जालौन तक जाने वाली Government Roadways Bus को कालपी से उरई तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कालपी से उरई तक बस कब तक चलने लगेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस साल जो रास्ते लिये जाने वाले हैं उनमें यह भी है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कानपुर-कालपी-उरई बस चला करेगी, यह १५ जून के बाद जब कि पुल टूट जाता है, उस समय कैसे चलेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरे पास इसकी सूचना नहीं है, मैं मालूम कर लूंगा।

श्री गरीबदास—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष कालपी से उरई तथा अन्य मार्गों पर बस चलाने के लिये सरकारी तौर पर कोई जांच-पड़ताल हुई थी कि कहां-कहां बस चलेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जरूर हुई होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार को पता है कि कालपी से उरई और झांसी मार्ग पर बसें चलाने का निर्णय जब माननीय विचित्र नारायण शर्मा मंत्री थे, तभी ले लिया गया था जो बाद को स्थगित कर दिया गया, तो क्या उस पर पुनः विचार कर इस रूट पर शीघ्र बसें चलाने के आदेश देंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—पहले की बात तो मुझे मालूम नहीं, इस वक्त तो उसको देखा जा रहा है।

*३८–४०—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४१—श्री लक्ष्मणराव कदम [२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

आदर्श कारागार, लखनऊ में महिला बन्दी का स्टोव से जल जाना

*४२—श्री गौरीशंकर राय—क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या आदर्श कारागार, लखनऊ के महिला बन्दी निकेतन की किसी महिला बन्दी का मुंह फरवरी, १९६१ में स्टोव गैस से जल गया है, जिसके फलस्वरूप उक्त महिला की एक आंख बैठ गई है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, परन्तु उक्त महिला की आंख को कोई हानि नहीं पहुंची।

*४३—श्री गौरीशंकर राय—क्या आबकारी मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जेल के भीतर स्टोव जलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

डाक्टर सीताराम—नारी निकेतन की नर्स अपने विश्राम गृह में जो जेल के भीतर भाग में होते हुये भी बन्दियों के निवास-स्थान से पृथक है, अपना खाना अथवा चाय गरम करने के लिये स्टोव स्वयं जलाया करती थी परन्तु दुर्घटना के दिन एक महिला बन्दी आ गई और उसने स्टोव जलाया। दैव योग से स्प्रिट में आग लगने के कारण उसका मुंह जल गया।

द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन*

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति १९६०-६१ का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं । क्षय रोग चिकित्सालय कानपुर का। इस सम्बन्ध में मैं एक सूचना देना आवश्यक समझता हूं। १४ वां प्रतिवेदन पावर के सम्बन्ध में जो था वह अभी प्रेस से प्राप्त नहीं हुआ है। २, ३, ४ दिन में प्राप्त हो जायगा तब वह सदन में प्रस्तुत कर दिया जायगा।

१० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न ३५-३६ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक १० मार्च, १९६१ को श्री उग्रसेन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५-३६ के सम्बन्ध में श्री उग्रसेन ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि १,५१० रुपये २५ नये पैसे जो आनरेरियम दिया गया है वह कितने कर्मचारियों को दिया गया है । उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि ९ कर्मचारियों को। उक्त उत्तर ठीक नहीं था । सही उत्तर इस प्रकार है—२४३ कर्मचारियों को।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४६५ पर)

प्रतिनिहित विधान समिति के लिये विधायन परिषद् के ४ सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव

श्री मदनमोहन वर्मा (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति महोदय से अनुरोध करता है कि वे इस सदन द्वारा १९६१-६२ के लिये निर्मित प्रतिनिहित विधायन समिति में कार्य करने के हेतु परिषद् के चार सदस्यों को मनोनीत करें ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति महोदय से अनुरोध करता है कि वह इस सदन द्वारा १९६१-६२ के लिये निर्मित प्रतिनिहित विधायन समिति में कार्य करने के हेतु परिषद् के चार सदस्यों को मनोनीत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जे० के० रेयन मिल्स, कानपुर की हड़ताल के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जे० के० रेयन मिल्स, कानपुर में कई दिन से हड़ताल चल रही है, उसका हमने नोटिस दिया.....

---

*छापा नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज न कोई काम-रोको प्रस्ताव आया है और न नियम ५२ का नोटिस।

श्री उग्रसेन---हमने कल भी दिया था और आज भी.....

श्री अध्यक्ष---आज नहीं आया।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४४---योजना और एकीकरण

*श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ४४---योजना और एकीकरण के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ९,५२,६६,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

इस वक्त जो प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रही हूं उसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसपर भी मैं प्रकाश डालूंगी। यह साल खास महत्व का है जबकि हम द्वितीय योजना खत्म करके तृतीय योजना में जा रहे हैं। हमारी तीसरी योजना के लिये प्लानिंग कमीशन ने ४९७ करोड़ रुपये की मन्जूरी दी है। इसमें ५·२५ करोड़ चकबन्दी के लिये खर्च होगा, वह भी शामिल है। यह ५.२५ करोड़ नेट आउट ले, डिफरेन्स बिट्वीन दि ग्रास आउटले १०.५० करोड़ और जो रिसीट हमें मिलेगी, इसीलिये हमने अपने प्लान में ५ करोड़ की और गुंजाइश रखी है। हमारा प्लान ५०२ करोड़ का होगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है कि इस प्रान्त की आर्थिक स्थिति सुधरे और प्रांत की प्रगति हो। इसीलिये आपके सामने बहुत बड़ी रकम रखी जा रही है। पिछली योजना में हर साल करीब-करीब ५० करोड़ रुपया खर्च किया गया लेकिन इस तृतीय योजना में हमने हर साल उससे ज्यादा रकम रखी है, जैसे १९६१-६२ में ७१ करोड़, १९६२-६३ में ८९ करोड़, १९६३-६४ में १०३ करोड़, १९६४-६५ में ११५ करोड़ और १९६५-६६ में १२४ करोड़। आपने देखा कि हर साल रकम बढ़ती जायगी। हम उम्मीद करते हैं कि पहले साल हम जो आउट ले करेंगे, जो रिसोर्सेज डालेंगे और उन रिसोर्सेज के साथ जो एफर्टस करेंगे उससे डेवलपमेंट होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अगले साल रिसोर्सेज का पोजीशन भी बेहतर होगा। इसलिये हमने हर साल थोड़ा-थोड़ा करके रकम को बढ़ाया है। पिछले सालों के लिये हमने कुछ ज्यादा रखा है और पहले सालों के लिये कुछ कम रखा है क्योंकि पहले के सालों में हम उतना नहीं कर पायेंगे। क्योंकि मैं समझती हूं कि पिछले सालों में इतना ज्यादा प्रयत्न नहीं कर पायेंगे। मगर दो साल के प्रयत्न के पश्चात् हमारी क्षमता में वृद्धि होने के कारण हम पिछले तीन सालों में ज्यादा प्रयत्न कर सकेंगे और पांच साला लक्ष्य पूरा कर पायेंगे।

आप देखेंगे कि आप के सामने जो स्कीम रखी जा रही है वह बड़ी एम्बिशस है। आप यह भी सवाल पूछ सकते हैं कि इतना ज्यादा खर्च करने की क्या जरूरत है। एक तो सारे देश में जो पैटर्न है उसमें हम भी शामिल हैं और उसके अलावा एकोनामिस्ट्स और दूसरे जो समझदार लोग हैं वह बतलाते हैं कि हमारे जैसे बैकवर्ड कन्ट्री के लिये यह आवश्यक है कि उसको पहले एक ऐसी एकोनामिक लेविल पर ले जांय जिसपर आगे डेवलपमेन्ट कर सकें जिसको लिफ्ट दि कन्ट्री फ्राम दि पावर्टी लाइन (Lift the Country from the poverty line) कहते हैं। तो इसके लिये शुरू में आपको बड़ी जोर की कोशिश करनी होगी। इसके पश्चात् आहिस्ता-आहिस्ता आप मुल्क को आगे बढ़ा पायेंगे। इसी कारण आपके सामने इतनी बड़ी योजना रखी गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्लान में कामयाबी तभी होगी जबकि रिसोर्सेज के साथ इम्पलीमेन्टेशन और एची-वमेंन्ट्स भी वैसे ही हों। सिर्फ रिसोर्सेज से ही काम नहीं हो सकता। इसके लिये हमें पूरी चेष्टा करनी होगी और वह चेष्टा तभी आ सकती है जब पब्लिक और सरकार का पूरा सम्मिलन हो, दोनों मिल कर काम करें। हमने यह जो इतनी बड़ी योजना रखी है यह अफसर और मुहकमे के मातहत पूरी नहीं हो सकती। अफसर मुहकमा तो आप के सामने पूरी रूप-रेखा रख सकते हैं और काम करने का रास्ता बता सकते हैं। लेकिन जब तक पब्लिक की तरफ से ठोस तरीके पर कोआपरेशन नहीं मिलेगा और प्रैक्टिकल तरीके से काम नहीं होगा तबतक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं।

एक बात मैं आपको और बता दूं कि यह पांच साल का जो प्रोग्राम है यह इन्टरलिंक्ड है। अगर एक साल हम पिछड़ गये तो आगे साल हम जितनी चेष्टा करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे। इसलिये पूरे पांच साल हमें मुस्तैदी और तेजी से सरकार को भी और पब्लिक को भी काम करना होगा तभी इतनी बड़ी योजना जो आपके सामने है उसमें कामयाबी हासिल हो सकेगी। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें ३८५ करोड़ से ३० प्रतिशत ज्यादा खर्च करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब यह है कि जितना खर्च और जितना काम हमने १० साल में किया है उससे ज्यादा खर्च और उसके अनुपात से ही काम हम अगले ५ सालों में करने का प्रयास कर रहे हैं।

जैसा कि फाइनेन्शल टार्गेट्स में हमने एक बड़ा कदम उठाया है उसके अनुसार फिजिकल टारगेट्स में भी बहुत ऊंचे लक्ष्य रखे हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर में हम चाहते हैं कि १८.७ मिलियन टन फूड ग्रेन का उत्पादन करें। आयल सीड्स के उत्पादन में हम ११.८ लाख टन तक पहुंचे हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर में १५.७५ लाख टन करना चाहते हैं। काटन में २४ हजार बेल आज हैं उसको १ लाख ५० हजार करना चाहते हैं। जूट में १ लाख ४० हजार बेल आज हैं और थर्ड प्लान के आखिर में १ लाख ७० हजार तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में ४ लाख ३८ हजार किलोवाट सेकिंड प्लान का टार्गेट था और थर्ड प्लान के आखिर तक ११ लाख ८० हजार किलोवाट पर पहुंचेंगे। ६ से ११ साल के बच्चों की पढ़ाई के सम्बन्ध में लड़कों का सेकेन्ड प्लान में टार्गेट था ३२ लाख और थर्ड प्लान में हमने ४५ लाख रखा है। लड़कियों के लिये ८.३ लाख था और २१.५ लाख थर्ड प्लान में करना चाहते हैं। मैं सारे आंकड़े तो नहीं देना चाहती हूं लेकिन कुछ खास-खास बता रही हूं। जैसे इन्जीनियर्स डिग्री होल्डर्स २४७ थे, अब थर्ड प्लान में ६७३ करना चाहते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स ५७६ थे, अब १,१७० करना चाहते हैं।

तो यह जो बड़े भारी टार्गेट्स हैं इनको अगर एचीव करना चाहते हैं तो जब सब लोग मिलकर करेंगे और पब्लिक की तरफ से पूरी कोशिश होगी तब पूरा कर सकते हैं। पब्लिक का सहयोग लेने के लिये सब से अहम बात यह है कि पब्लिक महसूस करे कि हम भी इस प्लान में कहीं हैं, हमारी भी कोई आवाज है प्लान बनाने में। पब्लिक से राय लेने के लिये इस बार तृतीय पंचवर्षीय योजना जब बनाई गई है तो अलग-अलग स्तर पर उनसे राय ली गई है। जैसे गांव, ब्लाक, डिस्ट्रिक्ट हर जगह जो समितियां हैं उनसे राय लेकर प्लान बनाया गया है ताकि वह समझें कि उनके इलाके के लिये प्लान क्या चीज ला रही है और जिससे उनमें उत्साह पैदा हो और फुर्ती आए। बड़े-बड़े जो प्लान्स हैं उनको छोड़ कर गांव में जो दूसरे प्लान चलेंगे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिये गांव, ब्लाक और डिस्ट्रिक्ट लेविल पर सारे प्रोग्राम इन लोगों के हाथ में दिये गये हैं। यह जो प्रोग्राम बना है, सरकार की तरफ से एक ढांचा उनके सामने रखा गया था मगर उसके अन्दर वह तब्दीली कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। गांव सभाओं और पंचायतों की तरफ से हमारे पास सुझाव आए, जैसे हार्टीकल्चर, कोआपरेशन, पोल्ट्री, फिशरी, लघु सिंचाई, गांव की सफाई इत्यादि कामों के प्रोग्राम गांव स्तर से बन कर आये

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

हैं। गांव सभा और गांव पंचायतों से बन कर आने के बाद ब्लाक में उनका समन्वय किया गया है, ब्लाक के बाद अन्तरिम जिला परिषद् में समन्वय होकर जिले से स्टेट लेविल पर आये हैं और अब उनकी छान-बीन की जा रही है। उसके बाद उनको बता दिया जायगा कि फाइनल स्टेज में यह चीज तुम्हारे लिये आ रही है। यह सब प्रबन्ध इसलिये किया है कि नीचे के लोगों को पता लगे कि उनके इलाके में क्या होगा और काम की योजना उनसे राय लेकर बनाई गई है। हम आशा करते हैं कि इस नये तरीके से ज्यादा कोआपरेशन लोगों की तरफ से मिलेगा और लोग दिलचस्पी से काम कर सकेंगे।

जो योजना बने उसको अमल में लाने के लिये हम लोग चाहते हैं कि गांव स्तर पर उसको इम्प्लीमेन्ट करने की जिम्मेदारी जिला परिषद्, क्षेत्र समिति और गांव पंचायत, इन तीनों के ऊपर रहे। जो कानून पेश है उसके पास होने के बाद जिला परिषद् और क्षेत्र समितियां स्टेटुटरी बाडी बन जायेंगी और उनके हाथ में यह काम सौंप दिया जायगा। आप लोग जानते हैं कि पंचायत के चुनाव अभी हो चुके हैं। इनमें जगह-जगह काफी हद तक अच्छी लीडरशिप सामने आई है। जब हम इनको जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि लीडरशिप को अच्छी तरह से ट्रेन किया जाय। उनकी ट्रेनिंग के लिये, ग्राम प्रधानों की ट्रेनिंग के लिये, आप लोगों को मालूम है, सारे जिले में कैम्प हुये हैं, ५१० ब्लाक हेडक्वार्टर्स में ३० हजार प्रधानों को ७ दिन तक शिक्षा कैम्पस में दी गई है। मुझे मालूम है कि कल माननीय सदस्यों ने यह जिक्र किया था कि प्रधानों की ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई है। हो सकता है कि जहां ३० हजार प्रधानों को ट्रेनिंग दी गई हो वहां कहीं-कहीं कुछ खराबियां हों, क्योंकि यह बड़ा भारी काम है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन में छोटी से छोटी Administrative यूनिट से वहां हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें और इसलिये उनकी कुछ न कुछ ट्रेनिंग हो रही है। मैंने खुद दो तीन जगह ऐसे ट्रेनिंग स्थानों पर जाकर देखा है कि हम जो उनके सामने आउटलुक रख रहे हैं वह एक बड़ी कम्प्रेहेंसिव चीज है लेकिन एक बड़े आउटलुक को लेकर हम कुछ चीजों में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो कुछ मैंने देखा है उससे मुझे आशा है कि वह हमारी स्कीम कामयाब होगी।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक यह योजना चलाने का विचार किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूशन्स बनेंगे जहां गांव के लीडरों को ट्रेनिंग दी जायगी। हमारी सरकार भी अब डिसेंट्रलाइजेशन का काम शुरू करने जा रही है। डिसेंट्रलाइजेशन के मानें हैं जो छोटी से छोटी यूनिट्स हैं उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों का अधिकार देकर तथा फायनेंशल पावर्स को भी देकर उनको उत्तर-दायी बनाना। यह अधिकार हम देने जा रहे हैं। जो रूरल एरियाज में हमारा प्रोग्राम चलेगा उसमें इन तमाम अधिकारों में छोटी से छोटी यूनिटस को पूरी आजादी रहेगी। फिलहाल ड्राइंग एन्ड डिस्बर्सिन्ग अथारिटी हमने बी० डी० ओ० को दे रखी है लेकिन जब यह क्षेत्रीय समितियां बन जायेंगी तो उनको यह अधिकार मिल जायगा। फिर यह आशा की जाती है कि कमेटियों को पैसा खर्च करने का और योजनाओं को अमल में लाने का पूरा अधिकार रहेगा और इस तरह से जनता का जो जागरण हम चाहते हैं वह हमें दिखाई पड़ेगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आखिर तक ६१० ब्लाक्स बन चुके हैं। ६७.५ परसेन्ट एरिया और ५१ परसेन्ट टोटल पापुलेशन का इन ब्लाक्स के मातहत आ गया है। रूरल पापुलेशन का ६६ परसेन्ट आज ब्लाक्स के मातहत आ गया है। हम आशा करते हैं कि अक्तूबर सन् १९६२ तक हमारे सारे शैडो ब्लाक्स ऐक्टिव ब्लाक्स बन जायेंगे और सारे यू० पी० का देहाती इलाका इससे कवर हो जायगा। १९६१-६२ के आखिर में ७२२ ब्लाक्स यू० पी० में तैयार हो जायेंगे। यह ब्लाक्स जो खोले जा रहे हैं उनके खोलने में दो कन्सीडरेशन्स हैं। पहला कन्सीडरेशन तो यह है कि हमारा ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े। उसके

लिये सिंचाई का प्रबन्ध जहां आसानी से मिलता है उसको हम पहले ब्लाक में लेते हैं ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की तरक्की पूरी तरह से हो सके। हम चाहते हैं कि हमारा जो डिमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिये हम अधिक से अधिक कार्यक्षमता शासन की छोटी से छोटी इकाई को दें। यह अधिकार देने के पहले यह आवश्यक है कि गांव प्रधान और समिति के मेम्बरों को शिक्षा दी जाय। मैं कई प्रशिक्षण क्षेत्रों में गई हूं और वहां मैंने देखा है कि जो ७ दिन में शिक्षा उन्हें दी जाती है वह कोई बहुत ज्यादा हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम कम से कम उनके सामने एक दृष्टिकोण रख रहे हैं और एक सामूहिक विकास का चित्र उनके सामने रख पा रहे हैं। जो शिक्षा वे हासिल कर रहे हैं उस से भविष्य में उनकी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में मदद मिल सकेगी।

अन्तरिम जिला परिषद् और ब्लाक समितियों को ब्लाकों के फेंजिंग में अपनी राय देने का पूरा अधिकार है। वे अपनी सिफारिशें प्रदेशीय सरकार के पास भेजती हैं जो इस फेंजिंग के सम्बन्ध में निर्णय क्षेत्रीय समितियों की राय को ध्यान में रखते हुए लेती हैं। इस निर्णय के बाद सरकार इस स्कीम को क्षेत्रीय समितियों के पास उसे कार्यान्वित करने के लिये भेज देती है। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि क्षेत्रीय समितियां अधिक कुशलता से कार्य कर सकेंगी और अन्तिम कार्यक्रम बनाने में उनका अधिकाधिक योग होगा।

कम्युनिटी डेवलपमेन्ट एक बड़ी भारी योजना है। उसमें ६५ करोड़ रुपये की जरूरत है, मगर हमारे पास साधन केवल ५१ करोड़ रुपयों के हैं। इसलिये कहीं न कहीं खर्च घटाने की जरूरत है। खर्च में कटौती करने के उद्देश्य से हमने यह प्रस्ताव रखे हैं कि ए० डी० ओ० पंचायत और ए० डी० ओ० सोशल एजूकेशन का समन्वय कर दिया जाय। इन दोनों जगहों का काम एक ही ए० डी० ओ० करेगा। इसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि और भी उपाय निकालें जिससे खर्च में कमी हो सके।

दूसरी ओर हमने अपनी नीति में कुछ तब्दीली की है। उसमें पहली तब्दीली यह है कि ब्लाक्स को हर साल जो रकम दी जाती है उसके बारे में हमने यह फैसला किया है कि ब्लाक्स को उसी अनुपात में पैसा दिया जायगा जिस अनुपात से वह काम करके दिखायेंगे। उनके काम को देखने के लिये यह भी देखा जायगा कि उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन कितना हुआ है और उनका एचीवमेंट क्या है उसी अनुपात में उनको रुपया दिया जायगा। उस की जांच करने के लिये एक डिस्ट्रिक्ट इवेल्यूएशन कमेटी बनाई जायगी जो वहां जाकर देखेगी। वे सब ब्लाक्स को ए० बी० और सी० कैटेगरीज में बांटेंगे। जिन ब्लाक्स का परफारमेन्स सबसे अच्छा होगा उनको ए० केटेगरी में रखा जायगा और उनको पूरी रकम खर्च करने के लिये दी जायगी। बी० और सी० केटेगरीज में वे ब्लाक रखे जायेंगे जो पहले प्रकार के ब्लाक्स से कम अच्छा काम करेंगे और उनको अगले साल में पैसा कम दिया जायगा। लेकिन इस बात का जरूर खयाल किया जायगा कि अगर वह ब्लाक बैकवर्ड एरिया में है जिसकी वजह से वहां काम करने में दिक्कत होती है तो वहां का असेसमेन्ट उन दिक्कतों का खयाल रख कर किया जायगा।

हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सबसे महत्वपूर्ण तीन चीजें हैं—१—कृषि, २—लघु सिंचाई और ३—कोआपरेशन। इस सिलसिले में खरीफ और रबी के जो अभियान चलाये गये उनमें हमें खासी कामयाबी हासिल हुई। आपको जैसा मैंने बताया हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम १३.५ मिलियन् टन फूडग्रेन्स के टारगेट पर पहुंच जायेंगे बल्कि हम यह भी आशा करते हैं कि हम उससे ज्यादा आगे भी पहुंच जायेंगे। यह एचीवमेंट कोई छोटा एचीवमेंट नहीं है। जब गृह मंत्री जी अपने कृषि के अनुदान पर बोल रहे थे तो उन्होंने बाहरी गांव सभा बांदा और अहरौरा गांव सभा आगरा का जिक्र किया था कि उन्होंने प्रोडक्शन में बहुत उन्नति करके दिखायी हैं। इस तरह की एक दो गांव सभायें ही नहीं हैं कई जगह ३० मन प्रति एकड़ तक

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

प्रोड्यूस हुई है, यही नहीं ३० से भी बढ़ कर ४० मन प्रति एकड़ तक पहुंच गये हैं। ऐसा काम किसी एक जगह ही हुआ हो ऐसा नहीं है, जगह जगह ऐसा काम हुआ है। कहीं-कहीं बहुत उत्साह है और हम उसको और बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस विषय में जो हमारी पुरस्कार की योजना थी उसमें हम अब व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार नहीं दे रहे हैं बल्कि कम्युनिटी को देते हैं। इससे लोगों में कम्युनिटी वर्किंग का आउटलुक पैदा हो रहा है जिसका असर गांव समाज में अच्छा ही होता जा रहा है। यू० पी० गवर्नमेंट ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार से वायदा किया है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के टारगेट से ४.७५ मिलियन टन हम और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। यह खुशी की बात है कि हमारा विलेज ऐन्ड ब्लाक लेविल का जो टारगेट हमारे पास आया वह ६.५ मिलियन टन था लेकिन यू० पी० सरकार ने जो आखिरी फिगर रखी वह ५.२ मिलियन टन है। अगर हम यह कर सके तो इसका असर प्रान्त की एकोनामी पर बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमारा प्रान्त ग्राम प्रधान प्रांत है और इस प्रान्त में हमारा सबसे बड़ा उद्योग खेती का ही उद्योग है। इसका असर पर कैपिटा इनकम पर बहुत अच्छा पड़ेगा। अतः मैं आप सबसे यह मिन्नत करती हूं कि हमने अपने हाथ में एक बहुत बड़ी योजना को लिया है और हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से और सारे भारत से यह वायदा कर लिया है कि इतना फूडग्रेन्स हम पैदा करने वाले हैं और यह करना संभव है, असंभव नहीं है। जो कुछ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने हासिल किया है उससे हमें आशा होती है कि हम ऐसा कर पायेंगे। अगर सब लोग मिल कर कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है कि हम अपने टारगेट पर पहुंच जायं। यह देश के लिये भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसकी प्रगति हमको करनी है और इसी के आधार पर हमारे उद्योग भी उन्नत होंगे। हमको अपने यहां ऐग्रीकल्चरल सरप्लस तैयार करना है, यही बुनियादी चीज है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं होंगी। इसलिये उस रास्ते पर चलने के लिये बड़ी भारी कोशिश तृतीय पंचवर्षीय योजना में करने वाले हैं।

पिछले दिनों में कोआपरेटिव के काम में भी काफी प्रगति हुई है। १५ हजार सर्विस कोआपरेटिव्ज हैं जो फरटीलाइजर्स के बटवारे का काम अच्छी तरह से कर रही हैं और अभी हाल में मार्केटिंग आफ ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का काम भी शुरू किया है जो अच्छी तरह हो रहा है। ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के साथ-साथ एनीमल हस्बेंडरी, पोल्ट्री, फिशरीज आदि का काम भी चालू है। यह काम जितनी अच्छी तरह से होना चाहिये था शायद नहीं हो पाया। उसका एक कारण टेक्नीकल आसिस्टेंट्स की कमी है। मगर अब टेक्नीकल असिस्टेंटस हमारे पास ज्यादा है और हम आशा करते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह काम अच्छा चलेगा।

एक और पायलट प्रोजेक्ट यू० एन० आई० सी० ई०एफ० के मातहत बस्ती और गोरखपुर में ४०० गांव लेकर चल रहा है जिसमें लोकल न्यूट्रिशनल चीजों पर अन्वेषण हो रहा है, जैसे पोल्ट्री, वेजीटेबिल, फल आदि ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, अगर यह प्रोग्राम कामयाब हुआ तो दूसरी जगह भी इसको चलायेंगे।

इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट एरियाज में मेडिकल का जो काम हुआ है वह एलोपैथिक डिस्पेंसरीज और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोलना है। पिछले साल स्टेज १ ब्लाकों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोलने का आयोजन किया था, यह दो साल में पूरा होगा, यानी १९६२ तक ५३ ब्लाकों में खोल देंगे। अभी २५ एलोपैथिक डिस्पेंसरीज हैं जो अपग्रेड करके प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हो गये हैं और २८ में से २१ में मैटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर्स खुल रहे हैं। अस्पताल की इमारतों का अभाव है। २६ जगह इमारतें बन चुकी हैं। इसके अलावा मेडिकल विभाग साफ पानी का इंतजाम, कुओं को पक्का करना और बनाना, खड़ंजे बनाना, चूल्हे और वाटर सील्ड लैट्रिन्स का प्रबन्ध अच्छी तरह से कर रहा है और यह काम अच्छे ढंग से प्रगति कर रहा है।

कम्युनिटी डेवलपमेंट एरियाज में जो काम हो रहा है बहनों का, मैं जानती हूं उसमें बहुत कमजोरियां और दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। बहनों को गांवों से लाकर उनको कामों में लगाने में काफी साहस की जरूरत है। हमारी बहनें जो काम कर रही है, उनको बहुत बातों में व्यक्तिगत दिक्कतें हैं। मसलन जब छोटी छोटी लड़कियों को गांवों में काम करने के लिये भेजते हैं तो उनके लिये मकान चाहिये जो हर जगह हम नहीं कर पा रहेहैं। जब वह काम करती हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो ऐडवान्टेज लेने की कोशिश करते हैं। इन सारी दिक्कतों के बावजूद जो काम हमारी बहनों, गृह-लक्ष्मियों ने किया है वह प्रशंसनीय है। वे यही काम नहीं कर रही है कि देहात की औरतों को दस्तकारी, शिशुपालन तथा गृहस्थी का काम सिखायें, बल्कि मैंने कई जगह देखा कि जहां बहनें खेती के काम में लगी हुई हैं, उनकी भी मदद कर रही हैं। उनको नये-नये तरीके सिखाये जा रहे हैं जिससे उत्पादन बढ़े। मैं आशा करती हूं बहनों के काम में और ज्यादा तरक्की तीसरी योजना में हो सकेगी।

इसके अलावा यूथ वेलफेयर का काम भी चल रहा है। हमारे यहां १२,५०० युवक मंगल दल सारे देहाती एरिया में बने हुए हैं। इस युवक मंगल दल का काम रेलीज इत्यादि करना नहीं है बल्कि यह दल खेती के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के काम में भी मदद कर रहा है। मैं अभी ४-५ दिन पहले एक देहाती एरिया में गई थी। वहां दो-तीन दिन मैंने युवक मंगल दल का काम देखा। वह लोग छोटी-छोटी बागवानी कर रहे हैं। ऐसे छोटे-छोटे उद्योग और खेती के काम करके वे देहात की आमदनी बढ़ा रहे हैं। इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत अच्छा लोगों पर पड़ता है। मैंने कई जगह देखा। बच्चों ने खेल-खेल में उत्पादन कर लिया और उनसे बड़ों ने सीखा। इसको अच्छी तरह से डेवलप कर सकें तो बहुत से अच्छे और नये काम हम कर पावेंगे।

श्रमदान के काम में नया तरीका लाने की भी हम कोशिश कर रहेहैं। अभी तक तो ऐसा था कि कोई नया प्राजेक्ट ले लेते थे। एक एडहाक तरीके से वहां काम करवा लेते थे। लेकिन अब यह तय किया गया है कि हर गांव सभा को बतलाया जावे कि वह श्रमदान से कुछ न कुछ काम करती रहे। कुछ रकम इसके लिये रखी जावेगी और कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम वहां किया जावेगा। इससे जो फालतू लेबर बैठा है उससे काम लिया जाय और उसकी आमदनी का रास्ता भी निकल आवे।

उद्योग का काम जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के मातहत हुआ उसके मुतल्लिक अब मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगी। मुझे यह कहने में दुख है कि उद्योग का काम बहुत कम हुआ है और उसकी तवज्जह नहीं दी गई है। लोग इतने अच्छे जानकार नहीं थे कि इस काम को अच्छी तरह से संगठित कर सकते। थोड़ा बहुत काम ट्रेनिंग का हुआ है। गांवों में ४-५ उद्योगों में ट्रेनिंग दी गई। फिर गांव कोआपरटिव्ज में उनको काम में लगा लिया गया। लेकिन मैं समझती हूं कि यह काम जिस ढंग से हुआ है वह तसल्लीबख्श नहीं है। इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना में अच्छी तरह से सुधार करने की जरूरत है। जहां एक तरफ कृषि में उन्नति करनी है दूसरी तरफ छोटे-छोटे उद्योग भी चलाने हैं ताकि बेरोजगार लोग उसमें लग जावें और गांव की आर्थिक स्थिति सुधर सके। इसके लिये हर दो ब्लाकों में एक ए० डी० ओ० इन्डस्ट्रीज रहेगा जो उद्योग में तजुर्बेकार होगा। ब्लाक को कुछ अधिकार दिये जावेंगे ताकि इन्डस्ट्रियल प्रोग्राम को वे आगे बढ़ा सकें। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जो हाल ही में स्टेटुअरी बोर्ड बना है, के द्वारा ग्रामीण उद्योगों में उन्नति होगी। अगर खादी ग्रामोद्योग के काम में और विकास के काम में कोआर्डिनेशन किया जावे तो मैं आशा करता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में बहुत से ग्रामोद्योग गांवों में खुल सकेंगे।

दो चार शब्द मैं प्लानिंग, रिसर्च एवं एक्शन इन्स्टीट्यूट के बारे में कहूंगी। यह संस्था अच्छा काम कर रही है। मैं इसका काम गांव में जाकर देख आई हूं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

बारे में यह संस्था अनुसंधान करती है और अनुसंधान के कुछ रास्ता हमें बतलाती है । बहुत सी चीजों पर यह अनुसंधान कर रही है । जैसे ग्रामोद्योग, सहकारिता, युवक कल्याण, महिला कल्याण तथा स्वाइल कन्जरवेशन आदि आदि ।

लघु उद्योगों में इस संस्था ने जो काम किया है उसमें से एक है स्माल प्रोजेक्ट फार शुगर इन्डस्ट्री । इसके कुल लागत १ लाख २५ हजार रुपया है । इसकी तरफ बाहर के देश भी आकर्षित हुये हैं और पाकिस्तान तो सामान खरीद रहा है अपने मुल्क में इसे चलाने के लिये और दूसरे देशों से पूछताछ हुई है कि यह स्कीम कैसी है । रूरल सैनीटेशन के बारे में काफी अनुसंधान किया गया है । वाटर सील्ड लैट्रिन्स का गांव-गांव में काफी प्रचार हो रहा है । चमड़े का उद्योग तथा और दूसरे छोटे-छोटे कामों में भी अनुसंधान किया जा रहा है । गैस प्लान्ट के बारे में घरेलू आवश्यकताओं के लिये रोशनी इत्यादि के लिये अनुसंधान किया गया है और उस पर सफलता प्राप्त की जा रही है ।

अब गैस का उपयोग इस उद्योग में कैसे किया जाय इस पर अनुसंधान किया जा रहा है । उन्होंने जो थोड़ा बहुत अनुसंधान किया है उसमें थोड़ी कामियाबी मिली है लेकिन अभी यकीनी तौर पर हम नहीं कह सकते हैं कि कितनी कामियाबी उसमें मिल सकेगी । अजीतमल में एक नया गैस प्लान्ट लगाकर वे अनुसंधान कर रहे हैं ।

तृतीय पंच वर्षीय योजना में एक नई योजना "फार्म फारेस्टरी" आरम्भ करने का विचार किया जा रहा है । गांवों में ईंधन की बहुत कमी है जिसकी वजह से सारा गोबर ईंधन में ही इस्तेमाल हो जाता है । इसलिये पेड़ लगाने की एक योजना शुरू की जा रही है जिनसे ईंधन के लिये लकड़ी मिल सके और गोबर बच सके । १९६१-६२ में इसके लिये १२०० गांवों में योजना चलाई जावेगी और हर ग्राम में ८ एकड़ जमीन में एक्सपेरीमेंट करके देखा जावेगा । इसके लिये जहां जमीन और पानी वगैरह मिलेगा वहां ५० फीसदी खर्चा सरकार की तरफ से दिया जावेगा और ५० फीसदी आशा की जाती है कि वहां के लोग मदद करेंगे । इसके लिये २.५२ लाख रुपया रखा गया है ।

कृषि एवं उत्पादन समिति और कल्याण समिति जो ब्लाकों में बनाई गई थीं उनसे समाज कल्याण और उत्पादन के काम सुचारु रूप से चलने की आशा की जाती थी । अब उनके अधिकार और काम दोनों बढ़ा दिये गये हैं । अब उनको कुछ ज्यादा पैसा भी दिया जा रहा है । जो काम उनको दिय गये हैं उनमें से एक मुख्य काम हरिजनों की उन्नति है और यह काम अच्छी तरह से चलने के लिये उनसे कहा गया है अपनी कमेटी में कम से कम दो हरिजनों को चुनें और एक ऐसे हरिजन मेम्बर को कोआप्ट करें जो हरिजनोद्धार के काम में दिलचस्पी रखता हो । उनको जो हरिजनों के लिये पैसा है केवल वही नहीं बल्कि जनरल बजट से पैसा निकाल कर खर्च करने की हिदायत दी गई है । मैं आशा करती हूं कि जब हमारा यह कानून पास हो जावेगा, स्टेटुअरी जिला परिषद् और क्षेत्र समिति बन जावेगी और उसके बाद गांव सभा, जिला परिषद्, क्षेत्र समिति के हाथ में ज्यादा अधिकार और पैसा हम देंगे तो एक नये सिरे से काम यहां शुरू होगा और एक नई जान काम में आवेगी । जैसा मैंने कहा, जितनी बड़ी योजना हम बनायें, उसकी सफलता निर्भर करती है जनता के सहयोग पर । हमने गांव-गांव में एक जबरदस्त किस्म का सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम जनता के सामने रखा है । यह ऐसा नहीं है कि इसे एक बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० या एक आध अफसर कर लेंगे । इस काम में हमें कामियाबी तभी मिल सकेगी जब कि हमारे देहात के लोग और जो जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हुये हैं वे यह समझेंगे कि यह जिम्मेदारी हमारी है, तब काम में एक नयी जान आयेगी और जो भी टारगेट हम रखेंगे मैं आशा करती हूं कि वह टारगेट हम हासिल कर सकेंगे । आपको मालूम होगा कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ इलाका है । वहां जब से एक नया डिमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया है उसके बाद से वहां काम में एक नयी शक्ल आयी है, एक नयी जान आयी है । पार्लियामेंट के जो मम्बर वहां गये थे उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, मैं जानती नहीं कि आप लोगों ने उसे

देखा है या नहीं, लेकिन वे बताते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से लोगों ने अच्छा काम करके दिखाया है। मैं समझती हूं कि हमारे जो देहात के लोग हैं वे समझदार लोग हैं और अपनी भलाई को समझते हैं। मैं आशा करती हूं कि नये ढंग से जो काम तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखेंगे उसमें आप सबके सहयोग और सहानुभूति से हम लोग कामयाब होंगे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—योजना और एकीकरण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, इस प्रकार का प्रस्ताव करते हुये और खास तौर से विकास की नीति में किसी समझदार आदमी को तकलीफ हो सकती है कि हम ९करोड़ कुछ लाख रुपये के अनुदान को केवल एक रुपये का करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा एक पैसे देने का भी इरादा नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह बात ऐसी है जिसके संबंध में हम सदस्यों की सेवा में और आपकी सेवा में निवेदन करना चाहते हैं कि हम क्यों ऐसी बातें कहते हैं? मैं इस बात को बहुत जोर और सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि प्लानिंग का काम, प्लानिंग की योजना और एकीकरण या जो कुछ भी नियोजन का काम हमारे यहां हुआ है और जब से इस ओर प्रयास किया गया है तब से ही हमारा आर्थिक ह्रास होता जा रहा है।

मैं यह कह सकता हूं कि हमारी इकोनामी प्लानिंग फेल हो गई है और इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिये। लेकिन कैसे फेल हो गई है इस बात के जानने की आवश्यकता है। श्रीमन्, मैं इसको तफसील में निवेदन करना चाहता हूं। हम प्लानिंग क्यों करते हैं जब तक हम इस बात को नजर के सामने नहीं रखेंगे तब तक इस प्लानिंग की ठीक कसौटी हमारे सामने नहीं रह सकती है। हम क्यों प्लानिंग करते हैं इसको मैं और तरह से नहीं कहना चाहता हूं, अपनी भाषा में नहीं कहना चाहता हूं। हमारी भाषा कुछ और है जिसको सरकार मंजूर नहीं कर सकती है। मैं उस भाषा में कहना चाहता हूं जो प्लानिंग कमीशन कहता है, जो प्लानिंग करने वाले कहते हैं। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से द्वितीय पंच वर्षीय योजना का वह हिस्सा जरूर निवेदन करना चाहता हूं। यह अंग्रेजी में है। हम मजबूर हैं कि इसकी प्रति हमको हिन्दी में नहीं मिल सकी। इसके पृष्ठ २४ पर इस प्रकार है कि—

"The accent of the socialist pattern is on the attainment of positive goals, the raising of living standards, the enlargement of opportunities for all, the promotion of enterprise among the disadvantaged classes and the creation of a sense of partnership among all sections of the community. These positive goals provide the criteria for basic decisions. The directive principles of state policy in the constitution had indicated the approach in broad terms; the socialist pattern of society is a more concretised expresssion of this approach. Economic policy and institutional changes have to be planned in a manner that would secure economic advance along democratic and egalitarian lines. Democracy, it has been said, is a way of life rather than a particular set of institutional arrangements. The same would well be said of the socialistic pattern."

(*a*) a sizeable increase in national income so as to raise the level of living in the country.

(*b*) rapid industrialisation with particular emphasis on the development of basic and heavy industries.

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

(*c*) a large expansion of employment opportunities; and

(*d*) reduction of inequalities in income and wealth and a more even distribution of economic power."

श्रीमन्, मैं इसकी हिन्दी करने में मजबूर हूं ।

श्री अध्यक्ष—आखिरी हिस्से की कर दीजिये जो आपने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो परिणाम निकलना चाहिये, उसकी हिन्दी कर दीजिये ।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, जहां तक इसका भावार्थ है और जहां सोशलिस्टिक पैटर्न की परिभाषा की गई है उसमें यह बताया गया है कि दो तीन चीजों के ऊपर हमारी इकोनामी की प्लानिंग होगी और उसका परिणाम यह होगा कि नेशनल इनकम में साइजेबिल वृद्धि होगी । साइजेबिल वृद्धि के अर्थ यह है कि काफी मात्रा में जिससे स्टैंडर्ड आफ लिविंग लोगों का बढ़ जाय ।

दूसरा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ हेवी इंडस्ट्रीज । बड़ी इंडस्ट्री का बड़ी तेजी के साथ औद्योगीकरण । तीसरा जनरल एक्सपैंसन आफ इम्पलायमेंट । लोगों को बड़ा भारी अवसर रोजगार मिलने का होगा । चौथा यह कि जो विषमता इकोनोमिक पावर और दौलत की, उसमें कमी होगी ।

श्रीमन्, इन चारों उद्देश्यों के ऊपर हमको देखना होगा कि हमको कहां तक सफलता मिली है? मेरी शिकायत जरूर होगी कि मैंने इस पोथी को ठीक से पढ़ा नहीं जो माननीय मंत्री जी ने सुनाई और मैं उसकी तफसील में नहीं गया कि फलां मद में इतना रुपया कम होना चाहिये और फलां मद में इतना रुपया ज्यादा होना चाहिये । मेरी यह शिकायत जरूर होगी कि मैंने बजेटिंग के तरीके पर आलोचना नहीं की । लेकिन मैं उसमें अपने श्रम को अकारथ नहीं करना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि उस रुपये पैसे के झगड़े में मैं अपनी भावना, बल्कि समूचे देश की भावना को व्यक्त नहीं कर पाऊंगा । इस लिये मैं इस हिस्से पर ज्यादा जोर दूंगा । मैंने बड़ी सख्त बात कही है कि चाहे हिन्दुस्तान में नियोजन में सफलता हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश फेल कर गया । फेल करने में मैं सबसे पहले वर्तमान मुख्य मंत्री जी को अपनी गवाही में पेश करना चाहता हूं । कुछ दिन पहले नैशनल हेरल्ड' में उन्होंने एक लेख लिखा था—बरबाद दस वर्ष दस वर्ष कैसे बरबाद ये हैं, मैं उसकी बहुत थोड़ी सी बातों की तरफ, जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, उन की तरफ ले जाना चाहूंगा ।

यह युग दो मुख्य मंत्रियों का युग रहा है—वर्तमान मुख्य मंत्री और इससे पहले जो मुख्य मंत्री जी थे । उनका भी भाषण श्रीमन्, आपने सुना होगा जो उन्होंने पार्लियामेन्ट के सदस्यों के सामने दिया था । उन्होंने कहा था कि सारे भारत में हम सबसे पीछे चले गये । हमारी पर कैपिटा और नैशनल इनकम घट गई । उन्होंने यह कहा कि हमारी वजह से नहीं घटी । इसका कारण दूसरे लोग हैं । उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की । जहां दूसरे सूबों में ६० रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने का फैसला किया हमको केवल ३७ रुपये प्रति व्यक्ति दिया । इस लिये हम पीछे रह गये । लेकिन यह इस सरकार की जादूगरी कही जायगी कि ३७ रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने के बाद भी इतनी छलांग मारी है । जो तरक्की पिछले दस वर्षों में हुई, ६० रुपये जिसने खर्च किये और उसके मुकाबले में ३७ रुपये जिसने खर्च किये और उसने जितनी तरक्की की, उसको देख कर सिवाय सरकार को बधाई देने के और क्या किया जा सकता है ?

अब उन उद्देश्यों को देखना चाहिये जिनकी तरफ जाना चाहिये था कि उनकी तरफ हम जा सकते हैं या नहीं । मैं सबसे पहले साइजेबिल इनक्रीज इन नैशनल इनकम को लेना चाहता हूं । यह जो हमारे सामने आंकड़े हैं, उनको भी श्रीमन्, देख लिया जाय, तो अच्छा है । १९४६–४७ में हमारी नैशनल इनकम क्या थी, जब कि कोई प्रयत्न नहीं हो रहा था कि नैशनल इनकम

बढ़ाई जाय ? १९४५ में लड़ाई खत्म हुई और कोई जिम्मेदार सरकार उस समय नहीं थी । १९४६-४७ में हमारी नेशनल इनकम थी १० अरब ६२ करोड़ और इस वक्त जो हमारी इनकम है ५९-६० में वह १६ अरब ६४ करोड़ है । तो इस पर जरा आप ध्यान दें-४६-४७ और ५०-५१ के बीच में आप जरा देखें, हमारी आंख उससे खुल जाती है ४६-४७ में जो इनकम थी वह १० अरब ६२ करोड़ थी । ५०-५१ में वह १६ अरब २५ करोड़ हो गई जब कि कोई प्रयत्न हम नहीं कर रहे थे, अपने आप हमारी इनकम जो कुछ जिस तरफ जा रही थी, उस तरफ जा रही थी। लेकिन जब से हमने प्रयत्न करना शुरू किया, जब से हमने यह साइजेबिल इनकम बढ़ाने का प्रयत्न शुरू किया, उस वक्त से क्या नतीजा है वह भी जरा आप देखें ५१-५२ से यह प्रयत्न शुरू हुआ तो ५०-५१ में जहां यह साइजेबिल इनकम १६ अरब १५ करोड़ थी, ५१-५२ से प्लान शुरू हुआ, ५५-५६ में १७ अरब ६७ करोड़ पर पहुंची । १ अरब से कुछ थोड़ी सी रकम ज्यादा हो गई । फिर ५५-५६ के बाद दूसरा प्लान आया जिसमें इंडस्ट्रिलाइजेशन की तरफ बड़ा ध्यान था । पहले में ऐग्रीकल्चर पर जोर था और दूसरे में इंडस्ट्रिलाइजेशन पर जोर दिया गया, बड़ी कोशिश की हम लोगों ने और उस कोशिश का नतीजा यह हुआ कि ५९-६० में हमारी नेशनल इनकम १६ अरब ६४ करोड़ हो गई ।

श्रीमन्, अब इस बात को देखते हुये और फिर कोई सरकार यहां आकर के कहे इस बात को कि पीठ ठोको तो जरा हमारी अपने हाथ से तो पीठ सरकार ठोंक ही रही है, लेकिन वह हमसे भी कहती है कि हम भी उसकी पीठ ठोकें, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का काम करने वाली सरकार जिसने कि अरबों रुपया इस गरीब स्टेट की जनता से उसकी चमड़ी से खींच खींच करके, उसकी चमड़ी से निकाल निकाल कर के खर्च किया और उसको खर्च करने के बाद उसका नतीजा इस प्रकार का आवे, और उसके बाद फिर वह इस हाउस में आकर के शेखी के साथ कहे कि अभी जो हमने किया है वह तो किया है, अब जरा देखो तीसरी योजना में हम क्या करते हैं, उससे भी ज्यादा करेंगे । सुचेता जी की बात को सुन करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने यह कहा कि आगे हम और करेंगे, तो क्या यही करेंगी आगे आप? अगर यही करना है तो मैं कहता हूं कि भगवान बचाये आपकी इस तीसरी योजना से । अगर यही करना है तो कृपा करके बन्द कीजिये इस काम को और छोड़ दीजिये भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर हम जिन्दा रहेंगे, भगवान के नाम पर हम मरेंगे, भगवान के नाम पर हमें रोटी मिलेगी । (व्यवधान) मैं आपसे कहता हूं कि कुछ अपने पास से यह कागज मैं नहीं लाता हूं । मैं आपके ही इस कागज को आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं और इसको पेश करते हुये जानना चाहता हूं, आप कृपा करके हमको कन्विन्सिंग वे में जवाब दें, उस तरह का जवाब न दें जिस तरह का कि जवाब आता है क्योंकि बहुमत तो आपका है ही और जवाब आपके पास होगा ही ।

श्रीमन्, यह तो हुआ साइजेबिल इनकम का । इसमें भी यह तो एक जगह हो गया । अगर इसकी भी तफसील में जायं तो उसमें आप देखेंगे कि इसका जो बटवारा हुआ है घर में, वह भी एक अजीब बटवारा हुआ है । वह घर के अन्दर का बटवारा किस तरह से है ? वह इस तरह से है कि मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू। इनइक्वैलिटी आबजेक्टिव का जो चौथा आइटम है उसको ले लिया जाय जिसमें यह है कि इनइक्वैलिटी, विषमता को दूर करना हमारा काम है, वह विषमता किस तरह से बढ़ी है ? नीयत हमारी नहीं थी, लेकिन हुआ यही । मैं खास तौर से श्रम मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह सुनें हमारी बात को और गौर करें कि उनको उस कुर्सी पर बैठना चाहिये या नहीं बैठना चाहिये । जो गलती उन्होंने की है उसको वह महसूस करेंगे अब ।

श्रीमन्, हमारी आमदनी थी-ग्रामीण आमदनी, वह सन् १९५०-५१ में २१०.६ रुपये थी १०५९-६० में यह १९१.६ पर-कंपिटा हो गई। इसमें सन्देह नहीं है कि जो यह आमदनी हुई वह बड़ी तेजी के साथ घटी । जो अरबन इन्कम कही जाती है उसके लिये यह कहा जाता है कि वह बढ़ी । वह जरूर बढ़ी क्योंकि वह इस तरह हो गई कि जब दोनों को मिलाकर अरबन और

[श्री गेंदासिंह]

करल की इनकम पर कैपिटा १९५०-५१ में २५६.७ रुपया थी तो वह १९५९-६० में २५५.३ रुपया रही है । अब मैं इसको छोड़ देता हूं । मुझे कोई दुश्मनी शहर के लोगों से नहीं है । यह निश्चय है कि उनकी आमदनी बढ़ी, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जो बढ़ी उसका हिसाब किस तरह से है ।

शहरों के भीतर जो लोग फुटपाथ पर पड़े रहते हैं और रात में फुटपाथ पर सोते हैं उनका नाम भी मर्दुमशुमारी में है जो दो वक्त रोटी नहीं पाते हैं । तो ये सब भी तो अरबन में ही गिने जाते हैं । अब हमारे पास वह डाटा नहीं है । मैं समझता हूं सरकार को वह डाटा पेश करना चाहिये कि शहर वालों में उन लोगों की क्या आमदनी हुई । उन शहर के लोगों में सारे सूबे में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है ? उन सारे के सारे लोगों का खून चूस कर जो आपने नतीजा निकाला है उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । इसलिये ऐसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिये कि शहर में जो फुट पाथ पर सोने वाले हैं, उनकी आमदनी शहर में बढ़ी है । उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है । वह तो बेचारे रिक्शा चलाते हैं । यह हमारी शहरी आमदनी की हालत है ।

अब यह सोचा जाय कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किस प्रकार से हुआ । बड़ी तेजी के साथ औद्योगीकरण जो किया गया, उसमें हम कहां गये । इसमें मैं हैवी इंडस्ट्री की बात कहता हूं और हैवी इंडस्ट्री में भी दूसरों की बात नहीं कह सकता हूं । प्राइवेट सैक्टर की बात मैं नहीं करता । यह तो श्रम मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि प्राइवेट सैक्टर में कितना काम हुआ । जो कुछ पब्लिक सैक्टर में हुआ उसकी बात मैं करता हूं । उसको आप सुन लें वह भी हैरत पैदा करने वाली बात है । यहां पर प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय के तीन वर्ष के फिगर्स हमारे पास मौजूद है । गवर्नमेंट आफ इंन्डिया से जो इन्फारमेशन नाम का सूचना पत्र निकलता है उसके पेज २० पर पहली पंचवर्षीय योजना में यह दिया हुआ है कि पब्लिक सैक्टर में उद्योग के लिये ५२ करोड़ २० लाख रुपया खर्च हुआ.....

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह किस महीने का है ?

श्री गेंदासिंह—यह मार्च, सन् १९६१ का है। इसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है कि ५२ करोड़ बीस लाख में उत्तर प्रदेश में कितना व्यय हुआ। दूसरे प्लान में इस विषय पर ४१४ करोड़ १९ लाख व्यय हुआ, खर्च हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश का नाम जरूर है कि उत्तर प्रदेश में ६९ लाख खर्च हुआ। अब इस कुल धनराशि ४६६ करोड़ कुछ लाख में उत्तर प्रदेश का जो भाग है वह ६९ करोड़ है। यह सब इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ हैवी इंडस्ट्री की हमारे यहां की हालत है। यह बड़ा काम हमने अपने यहां किया। कितनी इंडस्ट्री हमने यहां बढ़ाई ? क्या जितनी इंडस्ट्री बड़ी-बड़ी हमने यहां जो बढ़ा सकते थे, उनको बढ़ाया ? जितनी छोटी-छोटी इंडस्ट्री थी उनको हमने बढ़ाया ? खांडसारी, कोल्हू, करघा जैसे छोटे-छोटे उद्योगों को हमने बढ़ाया, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थीं उनको भी तो बढ़ाना चाहिये। और मार पड़ी इस तरह से कि आज, श्रीमान्, यह हालत है कि जिस कोल्हू से कोआपरेटिव का जन्म होता है, कोआपरेटिव में ही जिसका जीवन है, क्योंकि एक आदमी कोल्हू चला नहीं सकता, १० मिलेंगे तभी कोल्हू चलेगा, उसके लिये क्या किया गया है ? मैं सुचेता जी से खासतौर से कहना चाहूंगा कि खादी कमीशन का जो उन्होंने जो नाम लिया वह भी आज शुगर मिल आनर्स के पद—चिन्हों पर चल रहा है। वह भी बहुत इमानदार कमीशन है, लेकिन उसकी ईमानदारी में मेरे जैसे एक गवांर आदमी को शक होता है। आखिर क्यों कोल्हू के साथ, खंडसारी के साथ ऐसी ज्यादती हो ?

बड़ी इंडस्ट्री की हालत क्या है ? उसके लिये मुख्य मंत्री जी का बनाया हुआ जो कमीशन या कमेटी है श्री अजमोहन बिरला के सभापतित्व में, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उसकी रिपोर्ट ही देख लें। अगर वह उसकी ही रिपोर्ट देखेंगे तो पायेंगे कि हम कहां है। स्मास स्केल और काटेज इंडस्ट्री के साथ जो सौतेला व्यवहार सरकार ने किया है, तो उसे मानने

को चेष्टा की है प्लान पीरियड में, उसके लिये सरकार को प्रायश्चित करना पड़ेगा और प्रायश्चित के बिना काम नहीं चलेगा। मैं नहीं जानता कि वह आगे सुधरेगें या नहीं, लेकिन प्रायश्चित करना पड़ेगा, रा मैटिरियल के बिना तो कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती ।

आज श्रीमन्, देखें कि कपास, जूट, और गन्ने की हालत क्या है। अगर रा मैटिरियल ज्यादा और अच्छा पैदा कर देते हैं तो हम सजा पाते हैं कि तुमने क्यों इतना पैदा कर दिया, तुम बेवकूफ हो । तुम तो यह पैदा करते चले जा रहे हो और हम को उसकी उपज बढ़ानी है, कंज्यूमर की जरूरत को भी देखना है, लेकिन अगर हम उसके लिये प्रयत्न करते हैं तो हम को मार पड़ती है । तो सरकार को सोचना चाहिये कि छोटे उद्योग धंधों जिनसे लोगों को इम्प्लायमेंट मिलता, जिनसे लोगों में सहकारिता की भावना का संचार होता, सहकारिता का जिनसे आन्दोलन चलता, उनको मारने की तरफ सरकार की सारी ताकत लग रही है। तो क्या यह सरकार इंडस्ट्री चला सकती है ? मैं अगर उसकी लेबर वाली बात न कहूं तो ही ज्यादा अच्छा होगा । इसलिये लेबर का पार्टिसिपेशन क्या हो, उस सब में मैं नहीं जाता, लेकिन मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल पालिसी आपकी क्या हो उसे आप देखिये । उसमें मैं समझता हूं कि यह बहुत स्पष्ट है कि पब्लिक सेक्टर को अगुआ होना चाहिये और पब्लिक सेक्टर का धर्म है कि वह अगुआ बने ।

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद, पीठासीन हुए ।)

उसे कच्चा माल पैदा करने वालों और दूसरे लोगों के लिये आदर्श बनना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां हुआ ? कल बहुत बहस हुई और उसे मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी फार्मों पर जो मुलाजिम हैं, पी० डब्ल्यू० डी० के मुलाजिम हैं, रोडवेज में जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये आपने क्या किया है। मैं जानना चाहता हूं कि यहां के व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किया है। सरकार जो अल्लामियां के बाद दूसरा दर्जा प्रदेश के लोगों के लिये रखती है उसने क्या किया है ?

अधिष्ठाता महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में ४६ लाख ३९ हजार परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास केवल २४ लाख ३९ हजार एकड़ जमीन है, कुल आधे एकड़ का औसत पड़ता है, और अगर ५ व्यक्तियों का एक परिवार मानें तो ·५ एकड़ एक परिवार पर पड़ता है, ढाई कट्ठा जमीन के लिये हम कहते हैं कि उसकी आमदनी उससे बढ़ रही है और उसको सिंचाई के लिये जो हमने तीन आने को छूट दी थी उसे भी वापस कर लिया है । हम समझते हैं कि किसी भी समझदार आदमी को न तो इस प्लानिंग की ओर कभी झुकना चाहिये और न ही उसको स्वीकार करना चाहिये । वह कौन से आंकड़े हैं इस सरकार के पास जिनसे वह यह बता सके कि १० डिस्मल से एक गरीब आदमी किस तरह खायगा, किस तरह पहनेगा, क्या करेगा, सरकार जरा इसे बताये तो, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, श्रम मंत्री जी भी बैठी हैं, वे इसे समझायें तो ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मुझे थोड़ा सा समय और दे दिया जाय, मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं ।

श्रीमन्, एग्रीकल्चरल लेबर की बात पर मैं कुछ जरूर कहूंगा, बिना कुछ कहे रहा नहीं जाता । इस सरकार ने मिनिमम वेज कमेटी एक बनाई थी और मैं भी उसका मेम्बर था । उस कमेटी की सर्वसम्मति से एक रिपोर्ट सरकार के पास आई जिसमें इम्प्लायर और इम्प्लाई दोनों की राय एक थी, उसमें सबसे छोटी रकम के जो सुझाव थे उनको तो इस सरकार ने मान लिया किन्तु जो कुछ बड़ी रकम के सुझाव थे उनको मंजूर नहीं किया । बड़ी रकम के बारे में यह जवाब दे दिया गया कि उसके बारे में लेबर डिपार्टमेंट कहता है कि वह कानूनन गलत है । उस छोटी रकम को जो कि २५-३० की थी, उसको तो आपने मान लिया, मगर जहां हमने ४ पैसे ज्यादा देने की बात कही उसको आपने कह दिया कि हम नहीं कर सकते । मैं समझता हूं कि यह गलती हुई है, इसे सुधारना चाहिये ।

[श्री गेंदासिंह]

टैक्स लगाने के लिये तो आप सब से छोटे आदमी पर भी लगा सकते हैं मगर जहां उसको कुछ सुविधा देने की बात होती है, उसको आप करते नहीं । यहां पर माननीय मुख्य मंत्री बैठे हैं, श्रम मंत्री भी हैं, वे बतायें और इस सदन को यह समझा दें कि आपने इन १०–१२ वर्षों में उस गरीब आदमी को क्या दिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने उस भीख मांगने वाले को क्या दिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने उस रिक्शा चलाने वाले को क्या दिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने उस एक एकड़ वाले किसान को और उससे नीचे के किसान को क्या दिया । आज जो बेरोजगारी की फौज हमारे सामने है उसको आपने क्या दिया ? हां, आपने दिया जरूर है, मगर वह बड़े लोगों को, छोटे को नहीं । हमारी नीयत रही हो या न रही हो, मगर बड़े आदमियों की तिजोरियां जरूर भरी हैं ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि बैकुंठ नाथ मेहता की इस एकोनामिक रिव्यू को ही पढ़ लें और इसको पढ़ने के बाद भी वह यही देखेंगे कि गरीब और गरीब हुआ है, धनी और धनी हुआ है । तो ऐसी प्लान को हम किस तरह से सपोर्ट करें ।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । वह यह कि प्लानिंग के नाम से हम बड़ा घबराते हैं । फैमिली प्लानिंग का नाम भी सुन कर घबराहट होती है । अब यह प्लानिंग माननीया सुचेता कृपलानी जी के पास आई है इसलिये मैं समझता हूं कि कुछ सफलता मिल सकती है। जहां तक गुप्ता जी, मुख्य मंत्री, का सवाल है वह तो मजबूरी से ही इसके कायल हैं, कुछ लोग संयम से ही कायल हैं, लेकिन क्या आबादी कम हुई है ? (लाल बत्ती बुझने पर) तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप प्लानिंग को सफल बनाना चाहते हैं तो आप उसके तरीकों को बदलिये, दूसरा ढंग अपनाइये, वरना देश का कल्याण होने वाला नहीं है ।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मने माननीय मित्र गेंदासिंह की तकरीरों को बड़े गौर से सुना गेंदासिंह जी की जबान से एक बात सुनकर मुझे हैरत–ताज्जुब हुआ कि वह चाहते हैं कि प्लानिंग को एक साथ स्क्रैप कर दिया जाय, हटा दिया जाय । मैं जानता नहीं कि उनके कहने का वाकई मकसद यह है, कि वाकई बिलीव नहीं करते या उनको इतनी शिकायत है प्लानिंग के काम से जिसकी बिना पर फ्रस्टेट हो कर उन्होंने यह बात कही । इसमें कोई शक नहीं कि जो प्लानिंग का काम १० साल में हुआ, उसमें बहुत सी कमियां और खामियां रहीं और ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिये थीं लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि १० साल के अन्दर प्लानिंग से कुछ कामयाबी नहीं हुई प्लानिंग से मुल्क और सूबे की बेहतरी नहीं हुई या कहीं की कंडीशंस अच्छी नहीं बनीं यह सूरज को चिराग दिखाना होगा ।

यह सही है कि प्लानिंग के १० साल के काम में कठिनाई रही लेकिन और दिल को टटोलें तो मानना पड़ेगा कि एक शख्स की ही वजह से नहीं हो सकता । न उसकी जिम्मेदारी सब गवर्नमेंट की हो सकती है और न केन्द्रीय सरकार की ही हो सकती है और न अपोजीशन की बेंचेज की, बल्कि इन तमाम हालात में एक माहौल ऐसा बना जिसमें सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया लेकिन उतनी कामयाबी से काम नहीं चल सका जितनी कामयाबी से चलने की जरूरत है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि हमारे सूबे के अन्दर बावजूद इसके कि हमारी आमदनी और प्रोडक्शन बढ़ा हमारी पर कैपिटा इनकम कुछ बढ़ने नहीं पायी मुझे अफसोस है कि मुझ से पहले जब माननीय मंत्री जी ने तकरीर की और गेंदा सिंह जी ने तकरीर की तो उन्होंने मुख्य कारण को दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की । मैं इस बात को कहता हूं और बिला खोफ तरदीद कह सकता हूं कि हमारी परकैपिटा इनकम न बढ़ने की जो सब से बड़ी वजह हो सकती है वह यह है कि हमारे सूबे और मुल्क की आबादी बड़ी तेजी से आगे बढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

रही है लेकिन जब मैंने यह बात देखी कि न तो गवर्नमेन्ट की बेंचेज की तरफ से और न अपोजीशन के जिम्मेदार लोगों की तरफ से इस मसले को डिस्कस करने की कोशिश की गयी और न इस मसले पर कोई रोशनी फेंकी गयी तो मुझे बड़ा ताज्जुब और अफसोस हुआ। यह सही है कि हमारा सूबा पिछड़ा हुआ सूबा है, हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, हमारे पास पावर की कमी है, इंडस्ट्री में हम पीछे हैं, हम एग्रिकल्चर में बहुत ज्यादा आगे नहीं है, हम रोडस में पीछे हैं, बहुत सी चीजों में पीछे हैं, इस बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती। लेकिन इसका सब से बड़ी वजह हमारी बढ़ती हुई आबादी है। उसके अलावा हमको इस बात की भी शिकायत रही कि पिछले सालों में हमारे साथ सेंटर की तरफ से ऐसा व्यवहार नहीं किया गया जैसा कि होना चाहिये था। पिछली एम० पीज० की कानफरेन्स में पार्लियामेन्ट के सदस्य के सामने सब हालात रखे गये और उन्होंने अच्छी तरह से सब बातों पर गौर किया था। यह सही है कि हमारा सूबा इंडस्ट्री में बहुत पीछे है और जैसा–कि खुद इस रिपोर्ट से जाहिर है हमारे यहां ३७.२७ पर-कैपिटा आउटले है, हालांकि पापुलेशन के लिहाज से ६.७९ है।

तो सवाल यह है कि अगर हमको तरक्की करना है तो इनवेस्टमेंट करना होगा। इनवेस्ट हम करेंगे तो उससे हमारी इनकम बढ़ेगी। यह एक साइकिल है माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिसके मातहत हमारी तरक्की हो सकती है। चाहे वह प्राईवेट सेक्टर का सवाल हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का सवाल हो, अगर हम काफी इनवेस्टमेंट करने के लिये तैयार नहीं होंगे तो उस वक्त तक हमारी पर-कैपिटा इनकम कभी भी बढ़ नहीं सकती। इसकी तरफ गवर्नमेन्ट ने गौर नहीं किया और सेंटर की तरफ से हमारी उतनी मदद नहीं की जा सकी जितनी की जाना चाहिये थी।

अब जो कुछ भी इस दस साल में सामने आया, हमें मौका है कि हम उसका रिव्यू करें और उसकी रोशनी में हम अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो हमारी खामियां थीं इस अर्से में, उनको दूर करने की कोशिश करें और तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में में या आज जिस समय हमें बात करने का मौका मिला है, हम तमाम कमियों को दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश करें।

अधिष्ठाता महोदय, अब हमें यह बात मालूम हो गई कि हमको ४९७ करोड़ का प्लान मिला है और अगर्चे नेशनल डेवलपमेंट कांउसिल ने अभी इस प्लान को शामिल नहीं किया है, लेकिन यह करीब-करीब तय है कि ४९७ का हमारा प्लान होगा जिसमें से १४७ करोड़ रुपये हमको रेज करने पड़ेंगे, इसी शर्त पर प्लान मिला है। हम जानते हैं और महसूस करते हैं कि हमारा सूबा गरीब है और हमारे रिसोर्सेज भी बहुत पीछे हैं लेकिन फिर भी हमको इस तरफ तवज्जह करनी पड़ेगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो शुरूआत होने वाली है उसको जब हम देखते हैं चिन्ता पैदा होती है। आज हमारे सामने १९६१–६२ का प्लान आया है और इसके बाद चार प्लान्स और आने वाले है।तीसरी योजना के लिये हमें १४७ करोड़ देने होंगे। मुझे यह खुशी भी है कि गवर्नमेन्ट ने इस साल कोई ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं समझी। थोड़ा टैक्सेशन हुआ है। लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि अगर वाकई प्लान को चलाना है, मुल्क के पिछड़ेपने को दूर करके उसे डेवलप करना है तो और डेक्सेशन करने पड़ेंगे यह दूसरी बात हो सकती है और इसमें दो रायें भी हो सकती है कि टैक्सेशन के क्या एवेन्यूज हों। अच्छा यही है कि हम सब लोग मिलकर सोंचें कि टैक्सेशन के क्या एवेन्यूज हों।

इस साल जो इर्रीगशन की दो करोड़ की रिबेट खत्म की गई उसके मुताल्लिक इस सदन के अन्दर दो रायें हैं। मैं समझता हूं कि यह सही होता अगर वह रिबेट न खत्म किया जाता। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इस बात को भी मानता हूं कि १४७ करोड़ रुपये का हमें पांच साल में बन्दोबस्त भी करना है। इस साल हमने सिर्फ ५ साढ़े ५ करोड़ की रेवेन्यू ही रेंज की है। इसका नतीजा यह होगा कि आइन्दा चार सालों में जहां हमें तीस तीस करोड़ रेवेन्यू

[श्री सुल्तान आलम खां]

रेज करना था वहां ४०करोड़ रेज करना पड़ेगा। तो जब उसका भार लोगों पर ही पड़ता है तो फिर उसको ईविनली और स्क्वायरली हर साल क्यों न डाला जाय। यह मुनासिब नहीं होगा कि वह भार किसी साल में कम हो और किसी साल में ज्यादा हो जाय।

अधिष्ठाता महोदय, प्लानिंग का सब्जेक्ट वैसे तो बहुत बड़ा है और इसके मुताल्लिक बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं दो बातें ही खास तौर पर गवर्नमेन्ट की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एक चीज खास तौर पर प्रान्तीय रक्षक दल के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। यह दल हमारे प्रान्त में सन् १९४८ से कायम हुआ। हममें से सभी जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि इस दल ने हमारे यहां बहुत अच्छा काम किया है सोशल ला ऐन्ड आर्डर के मेनटेन करने में और उसके बाद सोशल वेलफेयर के काम में। इस दल ने प्लानिंग के रबी और खरीफ के अभियान में भी बहुत अच्छा काम किया है। पी० आर० डी० के कमान्डेन्ट डाइरेक्टर यूथ वेलफेयर भी हैं और महिला मंगल योजना का काम भी उनके सुपुर्द है जिसे वह बहुत तेजी से कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि आइन्दा क्या होने वाला है लेकिन मैंने सुना है कि कुछ एकोनामी मेजर्स लिये जा रहे हैं उसके मातहत कुछ चीजें अमलगमेट की जायंगी।

जहां तक एकोनामी की बात है वह एक अच्छी चीज है, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एकोनामी ऐसी नहीं होनी चाहिये जिसका असर एफीशिएन्सी पर पड़े। काश, एकोनामी के जो मेजर्स लिये जाने वाले हैं वह बजट के पहले ले लिये जाते क्योंकि इस वक्त हमको अपनी राय देने का मौका मिलता है और उससे गवर्नमेन्ट फायदा उठा सकती है लेकिन बजट पास होने के बाद साल के दौरान में अगर कोई एकोनामी के मेजर्स लिये गये तो फिर उस पर हमें अपनी राय देने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मैंने सुना है कि शायद सोशल वेलफेयर और हरिजन वेलफेयर को मिला दिया जाय और प्रान्तीय रक्षक दल में भी कुछ तब्दीली होने वाली है। मैं अपनी राय का सफाई से इजहार कर देना चाहता हूं कि प्रान्तीय रक्षक दल जैसा एक यूनीक आर्गेनाइजेशन हमारे सूबे में है वह किसी और सूबे में नहीं है, उसको हमें मेनटेन करना चाहिये। अगर इस प्रान्त के इस आर्गेनाइजेशन को डिसबैन्ड किया गया तो इसका बुरा असर पब्लिक पर पड़ेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं एक पाइंट आफ़ आर्डर उठाना चाहता हूं। माननीय वक्ता जी बहुत सी ऐसी बाते कह रहे हैं कि या तो वह कोई सीक्रेट खोल रहे हैं या उनको कोई इन्टरनल जानकारी है, तो क्या वह ऐसा कोई रहस्य खोलना चाहते हैं? यदि हां, तो उनके पास क्या आथारिटी है?

श्री अधिष्ठाता—यह तो उनको आजादी है। इसमें रहस्य खोलने की बात नहीं है।

श्री सुल्तान आलम खां—अवस्थी जी को अभी मौका मिलेगा तब वह अपनी तकरीर कर लें मेरे एक-दो मिनट जो उन्होंने लिये हैं वह मुझे दे दिये जाएंगे, यह मुझे उम्मीद है।

मैं यह कह रहा था कि इस सूरत में कोई इकानामी नहीं होनी चाहिए कि जिससे एफीसियेंशी पर असर पड़े। एक बात मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि प्रान्तीय रक्षक दल में पिछले कई सालों से जो फोर्स है उसके कुछ हिस्से को परमानेन्ट किया जाता है। पिछले साल भी २०७ जगह मुस्तकिल की गई थीं। मुझे मालूम नहीं कि इस दफा की गई या नहीं। मेरे नोटिस में नहीं आई। वह जो एक प्रोग्राम बना लिया है कि रफ्ता-रफ्ता सब जगहों को मुस्तकिल कर दिया जाय तो वह होना चाहिए क्योंकि यह एक इतना उम्दा आर्गेनाइजेशन है कि इसने न सिर्फ सूबे में बल्कि तमाम देश में अपनी एक जगह पैदा की है और यह अफसोस की बात होगी अगर वह किसी तरह से डिस्बैन्ड हुआ या उसका ऐसा रूप बदला कि वह जो अच्छा काम कर रहा है वह न कर सका।

अधिष्ठाता महोदय, प्लानिंग के सिलसिले में जहां तक रिसोर्सेज का ताल्लुक है, एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमको १४७ करोड़ रुपया लाना है और वह लाना है

टैक्सेशन से या किसी और सूरत से। तो जहां तक स्माल सेविंग्ज के ड्राइव का ताल्लुक है, इसकी तरफ खास ध्यान होना चाहिए। इसमें जो खामी है वह यह है कि लोग रुपया जमा करते हैं जब चाहें निकाल लेते हैं। उसमें अगर सेन्टर की इमदाद की जरूरत हो तो वह भी ली जाय और यह किया जाय कि जो रुपया आता है वह एक निश्चित मुद्दत तक रहे और उससे पहले न लिया जा सके। यह चीज बड़ी अच्छी होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पोजीशन को जरूर एक्जामिन कराया जायगा।

एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि हमने एक बहुत बड़े पैमाने पर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रेलाइजेशन का काम शुरू किया है। मैं चाहता तो यह था कि उसकी पिछले साल की एक तफसील भी हमारे सामने आती लेकिन हमारी मिनिस्टर साहिबा ने जो इस सिलसिले में फरमाया वह यह कहा कि जहां तक पब्लिक वर्क का ताल्लुक है जो फंक्शनल कमेटी के तरीके से कराया है, हमने पहले रुपया पापुलेशन बेसिस पर दिया और अब आयंदा एचीवमेंट के बेसिस पर दिया जायगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो काम साल में हुआ और जिसकी रिपोर्ट यकीनन गवर्नमेंट के पास आ गई होगी उसमें हमारा क्या तजुर्बा है। जो रुपया हमने फंक्शनल कमेटी के जरिये से पब्लिक वर्क में खर्च किया है उससे हम ज्यादा एचीवमेंट कर सकें बजाय उसके जो पहले आफीशियल हैंड से कर सकते थे? श्रीमन्, ५ मिनट और दे दें तो अच्छा है।

इसी सिलसिले में मिनिस्टर साहिबा ने यह भी कहा कि राजस्थान में सबसे पहले इसका तजुर्बा किया गया था और आन्ध्र में भी किया गया और सुनते हैं कि काम वहां अच्छा हुआ। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने वहां इवेलुएशन भी कराया है और उनके पास रिपोर्ट भी आई है। मगर मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं होगा कि इस हाउस के कुछ मेम्बर्स, खासतौर से जो प्लानिंग की स्टैंडिंग कमेटी से ताल्लुक रखते हैं, उनका एक डेपुटेशन आन्ध्र और राजस्थान को भेजा जाय और उनके साथ हमारे कुछ आफीशियल्स भी जांय और वह आन दि स्पाट स्टडी करें कि वहां कहां तक कामयाबी हुई है और हम कहां तक अपने आप को बेहतर कर सके हैं?

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो प्लानिंग की बहुत सी एक्टीविटीज हैं। प्लानिंग रिसर्च ऐन्ड ऐक्शन इंस्टीट्यूट में बहुत सी योजनायें भी हैं और खासतौर पर चिनहट में जो एवेलुयेशन आफ एन्यू मैन की योजना चलाने की स्कीम है वह बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा होता अगर उसका यहां पर तजकिरा आ जाता। काम सब हो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ मैं यह समझता हूं कि अगर हमें प्लानिंग के काम को तरक्की देना है तो मानना पड़ेगा कि हमारी कोशिशों के बावजूद भी हम लोगों में उतना एन्थूजियास्म पैदा नहीं कर सके हैं जितना होना चाहिये था और इसके लिये जरूरत है कि वक्तन-फवक्तन उसका इवेलुयेशन होता रहे और तरमीमें वगैरह जरूरी हों वह होती रहें। यह काम इतना बड़ा है कि एक स्ट्रेट लाइन पर तो नहीं हो सकता, उसमें रोज तरमीमें करनी पड़ेंगी और करनी पड़ रही हैं। बगैर इन तरमीमों के किये हुए हम आगे बढ़ नहीं सकते। यह एक्सपेरीमेंटल स्टेज है अगर इसका मुस्तकिल तौर से एवेलुयेशन होता रहे और काम को आगे बढ़ाते जांय तो बेहतर होगा।

गोविन्द सहाय कमेटी की रिपोर्ट पर अब दफ्तर में मैं समझता हूं कि एक्जामिनेशन खत्म हो चुका होगा और उसकी सिफारिशों का इम्लीमेंटेशन होने वाला होगा। मुझे एक बात ख्याल आती है और मैं नोटिस में लाना चाहता हूं और उसका जिक्र गोविन्द सहाय कमेटी में भी है कि इरीगेशन के साथ साथ अभी तक कोई पूलिंग का तरीका डिस्ट्रिक्ट लेविल पर नहीं है और उससे मैं समझता हूं कि इरीगेशन में दुश्वारियां और दिक्कत आबपाशी में होती है और जो डिसेंट्रलेशन का जो मकसद है वह पूरा नहीं होता। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरफ तवज्जह दी जाय। मैं जानता हूं कि दुश्वारियां हैं, लेकिन ह्वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे (Where there is a will there is a way) अगर कुछ सूरत इस किस्म की निकल सके तो जरूर कामयाबी होगी।

[श्री सुल्तान आलम खां]

मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे ज्यादा वक्त दे दिया। कहना तो बहुत ज्यादा था लेकिन अफसोस है कि वक्त उतना नहीं है और साथ ही डर भी है कि अवस्थी जी को शिकायत होने लगेगी कि ज्यादा वक्त मैंने ले लिया।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य गेंदासिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। आज नियोजन के सम्बन्ध में बहस हो रही है और ९ करोड़ ५२ लाख ६६,००० रुपये का अनुदान माननीय मंत्री जी ने मांगा है। मैं उस योजना को आपके सामने रख देना चाहता हूं। वह योजना क्या है योजना का मतलब क्या होता है? किसी भी राष्ट्र या देश का आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण करना। लेकिन आज तो हम रूस और अमेरिका में जो औद्योगीकरण हो रहा है उससे होड़ करना चाहते हैं। हम ख्रुश्चेव से पीछे नहीं रहना चाहते। मैं बतलाना चाहता हूं कि अमेरिका और रूस में फी धंधे पीछे २० हजार और हमारे हिन्दुस्तान में फी धंधे पीछे केवल २५० रुपया खर्च होता है। तो सवाल यह है कि २५० रुपये की लागत को २० हजार की लागत में कैसे परिवर्तित किया जाय। सारी योजना का आधार इसी नींव पर मुनहसिर है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हमारा देश इतना गरीब है, जब तबाही रोज बढ़ती जा रही है उस समय हम मुल्क को ख्रु चेव की नकल करने पर तुले रहें तो यह बड़े दुख की बात है।

आज हिन्दुस्तान की आबादी करीब ४४ करोड़ के पहुंच गयी है। अगर २/५ को भी उद्योग धंधे चाहिये तो करीब २० करोड़ जनता के लिये २० करोड़ धंधों की आवश्यकता है। २० करोड़ को २० हजार से फिर गुणा कर दिया तो खरब दस खरब से भी ज्यादा संख्या रकम की पहुंचती है। एक सौ अरब रुपये जो हम तृतीय पंचवर्षीय योजना पर खर्च करने जा रहे हैं अगर हिसाब लगाया जाय तो उससे तो दो ढाई सौ वर्ष तक हमारे देश की योजना पूरी नहीं हो सकती है फिर कहा जाता है कि इस योजना को लागू करने से कुछ रुपये सरकार को मिलते भी हैं। अगर यह भी लगा लिये जायं तो ७० और ८० वर्ष से कम समय नहीं लगेगा। अब सोचने का प्रश्न यह है कि इस वैज्ञानिक युग में जब हिन्दुस्तान ७०,८० वर्ष का इन्तजाम करेगा आज जिस स्थान पर रूस और अमेरिका पहुंच गये हैं उसकी बराबरी करने के लिये तो माननीय मंत्राणी जी बतायेंगी कि ८० वर्ष तक क्या रूस और अमेरिका घोड़े की तरह टापते खड़े रहेंगे और क्या वे तब तक और आगे विकास के रास्ते पर अग्रसर नहीं होंगे।

आज हिन्दुस्तान की जो खेती की दशा है वह यह है कि अगर सौ एकड़ भूमि पर खेती की जाती है तो उसमें ४ हजार या ५ हजार रुपया व्यय किया जाता है, लेकिन अगर वही सौ एकड़ भूमि पर खेती रूस और अमेरिका में की जाती है तो शायद उसमें ४ या ५ लाख रुपये खर्च होते हैं। आज हिन्दुस्तान में धोबी के धंधे के लिये १०० रुपये की आवश्यकता है। १०० की पूंजी लगाकर वह धोबी का धंधा खोल सकता है लेकिन अमेरिका में हजारों रुपये की पूंजी की आवश्यकता होगी। अब बताइये इस विषमता की खाई को किस प्रकार पाटा जा सकता है। लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार चाहती है कि एक सीढ़ी नीचे पैर रखे और लम्बी छलांग मारकर ख्रुश्चेव के पीछे अपनी घोड़ी दौड़ाये।

आज हमारे हिन्दुस्तान के अध्यापकवर्ग को ले लीजिये। रूस और अमेरिका में निम्न श्रेणी का अध्यापक वर्ग १३ सौ रुपया माहवार पाता है और यूनिवर्सिटी का उपकुलपति ८-१० हजार रुपया माहवार पाता है। हिन्दुस्तान में ही हमारे उपकुलपति को ५-६ हजार रुपया माहवार मिलते हैं लेकिन अध्यापकवर्ग जो निम्नश्रेणी का है उसको ४५ या ६० रुपया माहवार दिया जाता है। अगर आप उनकी नकल कर रहे हैं तो इस तरफ बराबरी क्यों नहीं हुई। सिर्फ इसलिये कि यह योजना जो बनायी गयी है वह चार या पांच लाख चुने हुए व्यक्तियों के लिये ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनायी गयी है। उन व्यक्तियों के लिये ही यह योजना नहीं बनायी गयी जो साधारण आदमी यहां का है। यह तो पंकनिधि में खिले हुए चन्द फूलों को और विकसित करने के लिये ही यह योजना बनायी जा रही है। यह है हमारे देश की नयी योजना।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने गल्ला पैदा करने में प्रगति की है लेकिन हमारे सामने जो उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की यह पुस्तिका है १९५७-५८ के आंकड़ों को अगर देखा जाय तो उससे उसकी उल्टी बात ही मालूम होती है। कृषि उत्पादन में भी घाटा है तो फिर यह प्रगति कैसी ? हर मामले में पहले की बनिस्बत उत्पादन कम हुआ है। फिर भी हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम प्रगति करते जा रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आया।

देश के अन्दर अगर खेती की उपज को बढ़ाना है तो सोशलिस्ट पार्टी द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करना चाहिये। माननीय मंत्री जी इटावा दौरे पर गये थे, उन्होंने वहां देख भी था। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर लाखों एकड़ जमीन ऊसर और बंजर जंगलों में पड़ी हुई है। जिसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। उसके लिये सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यह सुझाव दिया गया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर एक भूमि सेना बनायी जाय और केवल उनके तथा उनके परिवार के भरण-पोषण के लिये उनको भत्ता दिया जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो हिन्दुस्तान के अन्दर, उत्तर प्रदेश के अन्दर लाखों नौजवान भूमि सेना में भर्ती हो जायेंगे और लाखों एकड़ ऊसर, बंजर जमीन को कृषि योग्य बना डालेंगे। जब वह जमीन इस काबिल बन जाय कि उसमें पैदावार होने लगे तो उन्हीं भूमिहीनों को मौरूसी हक देकर वह जमीन दे दी जाय। इससे जो उनके पेट में सदियों से धधकती हुई भूमि की ज्वाला जल रही है वह बुझ जायगी और देश का उत्पादन भी बढ़ जायगा। लेकिन हमारी सरकार इसको मान कहां रही है ?

दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि देश के अन्दर बड़ी भारी विषमता की खाई है। किसानों और मजदूरों का वर्ग रात दिन जुटा रहता है लेकिन न खाने के लिये अनाज, न पहनने के लिये कपड़ा और न उसके बच्चों के पढ़ने के लिये सुविधायें ही उसको मिल पाती हैं। अगर माननीय मंत्री जी कानपुर में जो मिलाजुला दाम बांटो सम्मेलन हो रहा है २२-२३ तारीख को उसमें तशरीफ ले जायें तो उनको हिन्दुस्तान के बहुत से विद्वानों के भाषण सुनने को मिलेंगे और हो सकता है मनन करने पर उनकी दाम बांटो नीति का असर उन पर पड़े और उससे हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को काफी लाभ हो। हमारे प्रदेश की जनता को कुछ फायदा पहुंचे लेकिन मुझे मालूम है ऐसा नहीं होगा।

अब मैं अलाभकर जोतों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जमींदारी उन्मूलन रिपोर्ट में साढ़े ६ एकड़ से कम की जोत को अलाभकर माना गया है। तो फिर उन पर लगान क्यों लिया जाता है ? अगर देश में अन्न के उत्पादन को बढ़ाना है तो अलाभ की जोतों का लगान माफ होना चाहिये। लेकिन मैं जानता हूं सरकार ऐसा नहीं करेगी।

आज शिक्षा की स्थिति क्या है ? मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर बाहर के आंकड़ों से मिलान किया जाय तो भारत बहुत पीछे है और हमारा प्रदेश तो बहुत से प्रदेशों से भी पीछे है। सोशलिस्ट पार्टी ने सुझाव दिया है कि शिक्षा के लिये साक्षरता सेना बनायी जाय जो साक्षरता फैलाने का काम करेगी। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करने जा रही है। अगर आपको निरक्षरता का विनाश प्रदेश से करना है तो साक्षरता सेना बनाये जिसके द्वारा अनिवार्य शिक्षा लागू करके देश से निरक्षरता का नाश किया जा सकता है।

तृतीय योजना में प्रगति का बड़ा राग अलापा जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। जिस समय अंग्रेजी शासन था उस समय अंग्रेजों ने ७ अरब रुपये में ३३ हजार मील रेल की लाइन बिछायी। लेकिन हमारी सरकार, मेरा मतलब कांग्रेस सरकार से है ? एक अरब रुपये में कुल ७०० मील रेल की पटरियां ही बिछा पायी। अंग्रेजों के शासन काल में एक दिन में १ मील लम्बी पटरी बिछायी गई, २, ३ दिन के बाद एक स्टेशन बनाया गया और ६ महीने में

[श्री भजन लाल]

एक कारखाना खोला गया। उनके जमाने में प्रदेश में ६६ चीनी की मिलें थीं, लेकिन १४ साल के अन्दर हमारी सरकार केवल ४, ५ चीनी की मिलें ही खोल पायी हैं। यह प्रगति का नमूना है।

जो योजना चल रही है, अमरीका और रूस की नकल करके मुल्क को तबाह करना है। आप अलकतरे और सीमेंट की सड़क शहर में न बनायें। कंकड़ की सड़क देहात में बनायें जिससे लाभ भी हो। अगर ऐसा हो जाय तो काफी सुधार अपने आप हो सकता है। अलकतरे की १ मील लम्बी सड़क बनाने में २,३ लाख रुपया खर्च होता है, सीमन्ट की १ मील लम्बी सड़क बनाने में ४, ५ लाख रुपया खर्च होता है और कंकड़ की एक मील लम्बी सड़क बनाने में ८, १० हजार रुपया ही खर्च होता है। इसलिये कंकड़ की सड़कें बनायें और शुद्ध जल की व्यवस्था के लिये पक्के कुएं बनवायें, अगर यही दो बातें कर दी जायं तो १३, १४ अरब रुपये में देश में काफी प्रगति लायी जा सकती है। आज तो होता यह है कि गरीब किसान, मजदूर को शुद्ध जल भी पीने के लिये नहीं दे पाये हैं, कपड़े और रहने की व्यवस्था तो दूर रहा तो मैं देखता हूं कि अगर इस प्रकार से योजना चलाई जाय तो अच्छा है शुद्ध जल के लिये और कच्ची कंकड़ की सड़कें बनवाने के लिये। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आज हमारे हिन्दुस्तान में प्रगति के नाम पर बाहर के मुल्कों से आंचल पसार कर कर्ज मांगा जा रहा है और आज हिन्दुस्तान ६० अरब रुपये के कर्ज में दबा हुआ है और उस पर दो तीन अरब रुपया ब्याज में चला जाता है। हिन्दुस्तान जब हमारा आजाद हुआ था उस समय इंगलैण्ड पर १८ अरब पौण्ड का कर्ज था और ६ करोड़ का भारत पर था। आज वह १८ अरब पौन्ड खत्म हो गया और ७ अरब उलटे हम पर कर्ज हो गया। यह है हमारा नियोजन। भगवान बचाये ऐसे नियोजन से। अंग्रेजी शासन काल में नियोजन नहीं था लेकिन तरक्की होती थी लेकिन इस नियोजन के नाम पर, विकास के नाम पर, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के नाम पर हिन्दुस्तान को गुमराह किया जा रहा है, लूटा जा रहा है।

मैं अब अपने जिले की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय अभी लौटे हैं। ४, ५ दिन का असी हुआ मेरे जिले में दौरा करने गये थे। उन्होंने देखा कि औरैय्या नगर जमुना नदी के किनारे टिका हुआ है। अगर पीपों का पुल तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बना दिया जाय तो औरैय्या जो गल्ले की बहुत भारी मंडी है और उत्तर प्रदेश को काफी गल्ला प्रदान करती है वह काफी प्रगति के मार्ग पर जा सकती है और पुखरायां से उसे बिजली दे दी जाय तो उद्योग धन्धों की काफी तरक्की हो सकती है। सेंगर नदी के किनारे शैरपुर सरैया के पुल के वास्ते २५ हजार रुपया किसानों से जमा किया गया लेकिन आज तक वह पुल नहीं बनाया गया। मैं चाहता हूं कि इन बातों की तरफ माननीय मंत्री ध्यान दें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्राणी का भी आभारी हूं और उन्हें बधाई देता हूं। बधाई इसलिये देता हूं कि इस प्लानिंग विभाग को जो उन्होंने संभाला है उनके आ जाने से एक नया मोड़ उसमें आयगा।

श्रीमन्, यह प्लानिंग का कंसेप्ट सोवियट ब्लाक से या सोशलिस्टिक समाज से आया और हमने डेमोक्रेसी में इस प्लानिंग को रखने की चेष्टा की। इसके लिये पंचवर्षीय योजनायें बनीं और हमने कुछ उद्देश्य निर्धारित किये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब बनीं तो हमारे, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, तीन या चार प्रमुख उद्देश्य थे। सब से प्रथम उद्देश्य यह था कि हमारी मूलभूत आवश्यकतायें जो हैं वे हमें प्राप्त हो जायं। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और ऐसी वृद्धि हो जिससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो,

दूसरे उद्योगीकरण हो और हेवी इंडस्ट्रीज तथा गृह उद्योग धन्धों में काफी वृद्धि हो, तीसरे रोजगार बढ़े, चौथे असमानता दूर हो और इकोनामिक पावर का डिस्ट्रिब्यूशन हो।

इसी सदन में यह आशा की गयी थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक हम इतनी शक्ति पैदा कर लेंगे जिससे हम बहुत से गांवों में बिजली देंगे, हम फूड में सेल्फ अफिशियेंट हो जायंगे। हमने इसी सदन में वादा किया था कि पर्याप्त मात्रा में हम रोजगार दे देंगे। श्रीमन्, आप जानते हैं कि आज एम्प्लायमेन्ट का क्या हाल है? जो एम्प्लायमेन्ट आफिसेज हैं उनके फीगर्स को छोड़ दीजिये। पब्लिक सर्विस कमीशन से पता चला है कि बी० डी० ओ० की ६० पोस्ट्स के लिये १४, १५ हजार प्रार्थना-पत्र आये। मामूली से मामूली नौकरियों के लिये इतनी एप्लिकेशंस आती हैं। यह रिपोर्ट आप उठा कर देख लें कि कहां हम ८५ लाख को रोजगार देने वाले थे और करीब ६०-६५ लाख को हम दे पाये।

अभी हमारे प्लानिंग के भूतपूर्व डिप्टी मिनिस्टर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी पर-कैपिटा इन्कम इसलिये घट गई क्योंकि हमारी पापुलेशन बढ़ गयी। प्लानिंग में इन सब चीजों का हिसाब लगाना होता है, कितनी हमारी पापुलेशन बढ़ेगी, क्या हमारे रिसोर्सेज हैं क्या हमें करना है यही तो प्लानिंग है। हमने पापुलेशन का अन्दाज लगाया था कि इतनी बढ़ेगी और उस पापुलेशन का अन्दाज करके ही प्लान बना कर हमारे भूतपूर्व उप मंत्री जी ने जो यह दलील दी मैं उसको बिलकुल नहीं मानता। वास्तविक बात यह है कि हमने प्लानिंग करते समय जो वादे किये थे वह पूरे नहीं कर पाये। रुपया हमने कर्ज से लिया, बहुत-सा लोन हमारे ऊपर है लेकिन बहुत-सा रुपया अनयूज्ड पड़ा रहा। प्लानिंग में यह होता है कि जिस चीज के लिये रुपया लिया जाय उसका रिटर्न सही हो। क्या सही प्लानिंग हुई? जो वायदे हमने किये थे वह पूरे कर पाये? माननीया मंत्राणी किसी ब्लाक में गयीं, वहां दो-तीन चीज देख आयीं। अगर किसी गांव में जातीं तो आज भी देखतीं कि ६० फीसदी बच्चों के तन पर न कपड़े हैं न जूते हैं, न हम लोगों को कपड़ा दे पाये, न खाना दे पाये, न जितनी शिक्षा देनी चाहिये थी उतनी शिक्षा दे पाये, न रोजगार दे पाये, क्या यही हमारी प्लानिंग है? हमारे प्रदेश को देखते हुए देश में तथा अन्य प्रदेशों में तरक्की हुई है, प्लाट्स लगे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन हमारे प्रदेश को केवल चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी और प्रेसीजन इंस्ट्मेन्टस फैक्टरी यही दो इंडस्ट्रीज मिल पायी हैं। हर बजट भाषण में गवर्नर महोदय के भाषणों में इन्हीं दो फैक्टरियों का नारा लगाया जाता है। क्या इन दस सालों में हमने यही तरक्की की है? और कब तक इनकी प्रशंसा और गुण हम गाते रहेंगे?

माननीया मंत्राणी ने ब्लाकों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ब्लाकों के तीन फंक्शन्स हैं, पहला फूड प्रोडक्शन, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और तीसरा सर्विस कोआपरेटिज्ज। श्रीमन्, कल ही सदन में बताया गया कि चीनी का ओवर प्रोडक्शन हो गया। क्या यह हमारी प्लानिंग है कि रुपया लेते हैं मगर वह इस्तेमाल नहीं हो पाता। ब्लाकों में तीन-तीन साल से ट्यूबवेल बने पड़े हैं, बिजली नहीं मिल रही है और अगर बिजली मिल गयी तो चल नहीं रहे हैं। यह है हमारी प्लानिंग।

श्रीमन्, फूड प्रोडक्शन की बात भी कही गयी। तकावी के लिये रुपया दिया जाता है। ६० गुना मिलेगा भूमिधर को और २० गुना मिलेगा सीरदार को और सीरदार को पटवारी की सिफारिश, कानूनगो की सिफारिश, २ जमानतदार, एक रुपये का टिकट और ६ बार दौड़ने पर मिलेगी। तकावी यही नहीं, जब आप तहसील में पहुंचेंगे तो तहसीलदार साहब के क्लर्क को हक देना पड़ेगा। श्रीमन्, १०० रुपये की तकावी में ४०-४० रुपये रिश्वत ले ली जाती है।

श्रीमन्, अन्न उत्पादन की बात कही जाती है। बीज रखा रहता है मगर पानी नहीं मिलता और इरीगेशन मिनिस्टर महोदय कहते हैं कि हमने सिंचाई का रकबा बढ़ा

[श्री नकराम शर्मा]

बढ़ा दिया है। अधिष्ठाता महोदय, आप तो गांव के रहने वाले हैं, गेहूं के लिये चार पानी चाहिये और एक पानी आपने दिया तो क्या फसल ठीक होगी ? सिंचाई का रकबा तो बढ़ जायगा लेकिन फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। हमने सन् ५१ में कहा था कि सन् ५३ में हम फूड के मामले में सेल्फ सफिशियेन्ट हो जायंगे, लेकिन यह सन् १९६१ है और आज तक सेल्फ सफिशियेन्ट नहीं हो पाये, बाहर से गल्ला मंगाना पड़ रहा है। श्रीमन्, मैं स्वीडन गया, वहां के हर किसान सरकार को अपनी उपज, अपनी जमीन जानवर का हिसाब भेजता है। अतः सरकार को किसान की सही हालत और पैदावार का पता चल जाता है। एक एक पर्चा मौजूद है कि इस किसान के पास कितने जानवर हैं, कितना अनाज पैदा हुआ सब कुछ है। हमारे यहां आंकड़े कैसे आते हैं सिम्पल सर्वे द्वारा। अब सही उपज की हालत सरकार को नहीं मिल पाती है।

श्रीमन्, प्लानिंग की बात कही गई कि यह जनता का प्लान है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसी गांव में जाइये और गांव सभा से उस गांव का प्लान मांगिये कि तुम्हारे पास तुम्हारे गांव के बारे में कोई प्लान है? यह बात शुरू से कही जा रही है। श्रीमन् मैं भी एक इवेल्यूयेशन कमेटी का मेम्बर था। मैंने भी गांव सभा से प्लान मांगा। लेकिन किसी गांव का नहीं मिला। गांव सभाओं से इसके संबंध में नहीं पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकतायें हैं ? श्रीमन्, ब्लाक खोले गये और यह आदरणीय सदन जानता है कि २४ कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स खोले गये जिनमें १८ कंम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स बन्द हो गये। उनमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया। इटावा कम्युनिटी प्रोजेक्ट मिसेज रूजवेल्ट और अन्य कई विदेशी उनको देखने भी गये। लेकिन आज उनकी क्या हालत है? इसको देखने की जरूरत है। आज उनकी जांच होनी चाहिये और इतना रुपया खर्च होने पर भी क्या रिटर्न हमको मिला और जो दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिये कि करोड़ों रुपये कहां चले गये। इन गांवों में जहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स थे वहां क्या उन्नति हुई ?

श्रीमन्, ब्लाक खुले हैं और शैडो ब्लाक भी खुले हैं और दस साल बाद वह नारमेलाइज हो जायंगे। इन ब्लाक्स पर जितना इन्वेस्टमेन्ट किया था उसका रिटर्न कितना मिला इसके संबंध में भी सर्वे होनी चाहिये। श्रीमन्, तहसीलदार के पास जो आज जीप नहीं है लेकिन बी० डी० ओ० के पास जीप है। इनकी बिल्डिंग्स पर जहां ५० हजार रुपया खर्च किया जाता है। वहां पर इसके स्टाफ के ऊपर ४०–५० हजार रुपया साल में खर्च किया जाता है। हमने मांग की है कि बी० डी० ओज० के पास से जीप वापस ली जानी चाहिये लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। वे लोग जीप पर जाते हैं और वापस चले आते हैं और झूठे हाल्ट दिखाते हैं। बी० डी ओ० और ए० डी० ओ० में आपस में जीप के ऊपर बड़ी कशमकश रहती है। इनको काफी सामान दे दिया गया है और ५० हजार रुपये की ग्रांट डेवलपमेन्ट के काम के लिये दी जाती है। यह लोग दिन रात इन्हीं झगड़ों में लगे रहते हैं और विकास की तरफ कम ध्यान जाता है।

श्रीमन्, सर्विस कोआपरेटिव्ज की बात कही गई तो इस तरह से साधन समितियां नहीं चल सकती हैं। श्रीमन्, सर्विस कोआपरेटिव का मैंने स्वीडन, इजरायल, नार्वे और यूरोप में जाकर अध्ययन किया है और मैंने देखा है कि वहां क्या होता है ? अगर आप इनको ठीक से चलाना चाहते हैं, गांव की यूनिट्स को मानकर डिसेन्ट्रेलाइजेशन करना चाहते हैं तो इन ब्लाक्स को तोड़िये और उसका धन गांव सभाओं को दीजिये वे ही जान सकती हैं कि उनके गांव में कितने कुओं की जरूरत है, कितनी गायों की जरूरत है, कितने पेड़ों की जरूरत है और कितने बीज की जरूरत है, श्रीमन्, तभी यह प्लानिंग भी लाभप्रद होगा।

श्रीमन्, फूड-प्रोडक्शन की बात कही गई और होता क्या है कि ५० रुपये की खाद मिलेगी और मेरे पास २०० बीघे खेत हैं या कम बेशी, तो कैसे काम चल सकता है। अगर आपको फूड-प्रोडक्शन बढ़ाना है तो तकावी के नियमों में परिवर्तन कीजिये। इजराइल में नकद रुपये नहीं देते

हैं बल्कि कूपन देते हैं खेती के लिये, औजारों के लिये, खाद ट्रैक्टर के लिये और बीज के लिये और गांव वाले जाकर कूपन देकर दुकान से सामान ले आते हैं और गवर्नमेन्ट उनका पेमेन्ट कर देती है। यहां तकावी लेने पर रिश्वत देनी पड़ती है और किसान उस रुपये को उस काम में खर्च नहीं करते हैं जिसके लिये वे तकावी देते हैं इस की रोक होनी चाहिये। अगर आप सर्विस कोआपरेटिव को जिन्दा रखना चाहते हैं तो गांव सभाओं को शक्ति दीजिये, धन दीजिये। मंत्राणी जी का गांधी आश्रम से बहुत संबंध रहा है। गांधी आश्रम के ग्राम सेवक ज्यादा ईमानदारी और सेवा की भावना से काम करते हैं जो० बी० एल० डब्लू० कभी नहीं कर सकता। छोड़ दीजिये इस प्लानिंग की ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको तोड़ दीजिये। गांधी आश्रम के जो ट्रेनिंग केन्द्र हैं, सर्वोदय के विचार को लेकर ट्रेनिंग दीजिये। उनको साहब न बनाइये, सच्चे ग्राम सेवक बनाइये, तब कामयाबी होगी।

श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि कितने अफसर है बी० एल० डब्लू०, पंचायत सेक्रेटरी, कोआपरेटिव सेक्रेटरी, कोआपरेटिव सुपरवाइज़र लेखपाल, पतरौल, स्टाकमैन, केन सुपरवाइजर कामदार, मलेरिया सेवक, सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर और कोआपरेटिव सुपरवाइजर, हेल्थ विजिस्टर, मिड वाइफ, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ए० डी० ओ०, वैक्सिनेटर, वगैरह गांव स्तर पर दुनिया भर के अफसर हैं। किसान कहता है कि यह क्या बला है? कहते हैं कि डेवलपमेंटी आये थे। इन नामों को वह बोल भी नहीं पाते। इन छोटे-छोटे कर्मचारियों को ग्राम सभा के अन्तर्गत रखिये और उनके काम की जिम्मेदारी उन ग्राम समाजों के प्रधान लें। अपने विभाग के कोआर्डिनेशन और प्लानिंग में सचेत होइये। (इस समय श्री नेकराम शर्मा कुछ क्षणों के लिये चुप हो गये।) माननीय मंत्राणी जी बात कर रही थीं, मैंने सोचा कि वह बात कर लें तब मैं कहूं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आप घबड़ाते क्यों हैं? आप बोलिये, मैं सुन रही हूं। आप बहुत ज्यादा घमंड में हैं।

श्री नेकराम शर्मा—मंत्राणी जी ने रिमार्क किया—"तुमको बहुत घमण्ड है" और जो यह घमण्ड शब्द का प्रयोग कर रही हैं अगर आप नाराज हो रही हैं, तो मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं आपके इन शब्दों के विरोध में।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय गेंदासिंह जी ने रखा है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय गेंदासिंह ने जो विचार अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुए व्यक्त किये थे मैं उनसे सहमत हूं और मैं समझता हूं कि देहाती क्षेत्र से आने वाले सभी माननीय सदस्य उनसे सहमत होंगे।

दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकी हैं, और जिस तरह से हम आगे चल रहे हैं, और जो खर्च हो रहा है वह बिलकुल फिजूल है। अभी जो माननीय सदस्य भाषण कर रहे थ उससे भी सभी को यह मालूम हो गया होगा कि लोगों की क्या भावनाएं हैं। एक माननीय सदस्य जो पहले प्लानिंग के डिप्टी-मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने भी अपने विचार प्रगट किये। मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि यह प्लानिंग का युग है लेकिन लोगों की आंखों में बहुत धूल झोंकी गयी, अब कितनी और धूल झोंकी जायगी? हर काम में कह दिया जाता है कि प्लानिंग के लिये रुपया ले रहे हैं, उद्योगों का विकास करने के लिये ले रहे हैं। लेकिन उसका भार वहन करने की क्षमता हम कहां तक रखें? हम देखते हैं १४ साल स्वतन्त्रता के हो गये। हमारे देहात को जा कर देखिये। जहां नाला बह रहा था, वहीं अब भी बह रहा है। जो सड़क कच्ची थी वह अब भी कच्ची है। अंतरिम जिला परिषद् की स्थापना के बाद

---

* वक्ता ने भाषण कर का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

अब कच्ची सड़क का बनना भी बन्द हो गया। जितना काम स्वशासन में होता था वह भी सब चौपट है। जब तक गांव के लोगों को उत्साह नहीं मिलेगा तब तक प्लानिंग सफल नहीं होगी और उनको इस तरह से उत्साह नहीं मिलेगा। उत्साह मिलेगा तब जब उस क्षेत्र में आप कोई ऐसी चीज खोलें जो उनके फायदे की हो।

अभी हमारे क्षेत्र में एक विकास खंड खुला। जिस तरह से नहर विभाग में पहले यह कायदा था कि नहर बनने का तय हुआ तो पहले इंजीनियर साहब के लिये एक इंसपेक्शन हाउस वहां बनता था, वैसे ही ब्लाक खुलना है तो पहले बी० डी० ओ० के लिये पक्का मकान बनेगा। १ लाख १८ हजार रुपया अभी हमारे यहां रामपुरा ब्लाक में उसके लिये मंजूर हुआ है। मैं कहता हूं कि इसकी क्या जरूरत है? आपको ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, उसकी तरफ पहले ध्यान देना चाहिये कि पहले बी० डी० ओ० के लिये पक्का मकान बनवाना जरूरी है? जिस क्षेत्र में सड़क न होने की वजह से छः-छः महीने हम अपने घर से निकल नहीं सकते हैं उस क्षेत्र में अगर आप इस १ लाख १८ हजार रुपये से सड़क बनवा देते तो उससे उनको उत्साह होगा या बी० डी० ओ० के रहने के लिये मकान बनवाने से उनको उत्साह होगा? अभी कल ही अस्पतालों की ग्रान्ट पास हुई है। हमारे यहां विकास क्षेत्र में जो अस्पताल खुले हैं उनमें कोई डाक्टर ही नहीं है। ४२-४२ मील दूर तक जनता बिना किसी डाक्टर के रहती है। विकास करना चाहते हैं लेकिन उनके लिये डाक्टर का इन्तजाम नहीं कर सकते। शहरों के लिये सब इन्तजाम है। तो यह चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जहां आप विकास करना चाहते हैं वहां उसके लिये कुछ उत्साह दिखलाइए।

श्रमदान से सड़कें बनीं। वह केवल इसलिये कामयाब नहीं हुई कि उनको पक्का नहीं किया जा सका। मेरे जिले में चार-चार, छः-छः सड़कें हैं। "५३ हजार रुपया हमारे कट्टी-ब्यूशन का अब तक जमा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई--राम बंगरा से रामपुर की सड़क आज तक पी० डब्ल्यू० डी० ने नहीं बनायी। श्रमदान से उसे बनाया गया था और उसके पी० डब्लू डी० द्वारा बनाये जाने का नतीजा यह हुआ कि वह सारा श्रमदान बेकार गया। ५३ हजार रुपया हमारे कट्टीब्यूशन का अब भी जमा है, लेकिन सरकार ने सड़क नहीं बनायी। तो इसे हम क्या समझें कि यह प्लानिंग हो रही है? आपने बजट में तमाम रुपया रखा है। पी० डब्ल्यू० डी० में रोलर्स की कमी है मैं तो यह कहता हूं कि इन्हीं को मंगवा दीजिये जिनसे कि सड़कें कूटी जाती हैं और प्रत्येक जिले में एक-एक बंटवा दीजिये, फिर देखिये कि कितना काम श्रमदान से होता है? कितनी सड़कें बनती हैं? अभी क्या होता है कि पी० डब्ल्यू० डी० देता नहीं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी नहीं देता, हमारी श्रमदान से बनायी हुई सड़कें बेकार चली जाती हैं। तो हम इस तरह अपना लेबर बेकार नहीं फेंकना चाहते। आप अगर यह कहें कि हम अपना लेबर इस तरह से बरबाद करें तो यह हम अब नहीं करेंगे। दो दफा बरबाद करके देख लिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा आश्वासन देने के बाद भी उसकी कोई परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं कि इस तरहसे काम नहीं चलेगा। यह भी होता है कि वहां से सड़क कोई पास हुई और यहां पर यह हो गया कि दूसरी सड़क ले ली गई। तो आपको किसी प्लान के हिसाब से चलना चाहिये।

हमें बड़ी खुशी हुई, मंत्री जी ने यह कहा कि अबकी बार यह प्लान गांव के स्तर से ब्लाक में आया और ब्लाक से और ऊपर आया लेकिन हमें यह कहना है कि गांव वाले भी अभी प्लान बनाना जानते नहीं थे, लेकिन उनके लिये यही बहुत हुआ कि उनसे पूछा तो गया, हमें इसी की खुशी है। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्लान बनकर आया है उसमें यह गुंजायश जरूर रखी जाय कि जो तब्दीली वह करना चाहें वह कर सकें। आप रुपया यहां से मंजूर कर दीजिये और उसके बाद सड़क वह जहां बनाना चाहें बनायें। अगर हर चीज का नियंत्रण ऊपर से करेंगे तो प्लान आपका कभी भी कामयाब नहीं हो सकता।

दूसरी चीज यह देखिए कि इकोनामी की बात कही गई कि कमी करनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बी० एल० डब्लू० और पंचायत सेक्रेटरी इन दोनों का

काम एक ही है। आपने इन दोनों को क्यों रखा है? हमारे यहां बी० एल० डब्लू० जो भेजे गये हैं वह पूर्व की तरफ के रहने वाले हैं। जालौन जिले में चावल पैदा नहीं होता है। वहां पर गेहूं और चना पैदा होता है। वह चावल खाते हैं। उनको गेहूं खाने में तकलीफ होती है। जब उनका स्वास्थ्य खराब रहता है तो वे बेचारे काम क्या करेंगे। ऐसे लोग हमारे यहां प्लानिंग का काम करने के लिये भेजे गये हैं। हमारे यहां के और पच्छिम के लोग पूर्व में भेजे गये हैं। वह भी वहां पर बीमार हैं। वहां चावल वह खा नहीं सकते हैं। वहां पर गेहूं उनको खाने के लिये नहीं मिलता है। दोनों ही बीमार हैं। अब आप यह बताइये कि वे अपना स्वास्थ्य ठीक करें या आपका प्लान चलायें? मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपकी प्लानिंग इस तरह से चलने वाली नहीं है कि पच्छिम वाले को पूर्व और दक्खिन वाले को उत्तर। इस तरह से काम नहीं चलेगा। मेरा सुझाव यह है कि जो आप कम से कम ब्लाक पर खर्च करते हैं उसमें सब से अधिक यातायात पर खर्च होना चाहिये। अगर आप यातायात के साधन बना दें तो ये सारी प्लानिंग आपकी एक तरफ और यह यातायात की सुविधा एक तरफ। अगर यातायात की सुविधा हो जाय तो हमारे देहातों की सारी तरक्की जल्दी हो सकती है। हमारे यहां बुन्देलखंड में बहुत सी सड़कें ऐसी हैं कि जहां पर तीन तीन योजनाओं के आने के बाद भी १९१४ वाली सड़कें पड़ी हुई हैं। उनमें से २, ३ को लिया जा रहा है।

(इस समय २ बजकर ७ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि प्लान करना है वह उस तरह से हो कि जिससे वहां के लोगों का फायदा हो। जिससे लोगों में उत्साह पैदा हो। तभी आपको रुपया भी मिल सकता है और वे भी अपना रुपया लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि वहां पर अन्न पैदा हो लेकिन कहां से पैदा हो। आपने जो टैक्स में नहरी रेट के छूट दे रखी थी तीन आने की उसको आप वापस ले रहे हैं। जब इस तरह की रियायत गायब हो जाती है तो लोगों में उत्साह नहीं रहता। वहां पर ऐसी चीज की जरूरत है जिससे लोगों के अन्दर उत्साह पैदा हो और काश्तकार मन लगाकर पैदा करें। इस तरह कोई छूट वापस लेने पर तो काश्तकारों का उत्साह भंग हो जाता है।

किसान यह समझने लगते हैं कि हम तो पैदा करते हैं और मेहनत करते हैं फिर भी यह सरकार कोई सहूलियत देने के लिये तैयार नहीं है। हमारा जालौन जिला ऐसा है जो अन्न बहुत पैदा करता है। गेहूं और चना बहुत अधिक मात्रा में देता है। यदि इस तरह की सहूलियत वहां लोगों को मिल जाय तो उससे बहुत लाभ हो सकता है।

मैं उद्योग धंधों के बारे में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन आपने छोटे-छोटे उद्योग धंधों पर नियन्त्रण इतना कर दिया है कि हर एक आदमी उद्योगधंधों के बारे में सोच नहीं सकता। देहात के अन्दर जो कोल्हू या क्शर वगैरह हैं उन पर बड़ी ज्यादती होती है। उनकी शिकायतों को यहां लेकर आते हैं तो कोई सुनता नहीं है। उनसे ब्लैक के ७५, १०० और २०० रुपये तक लिये जाते हैं। अगर उद्योग धंधों को चलना है तो सरकार को ऊपर से ही कंट्रोल करना पड़ेगा और अगर सरकार इस तरह से कंट्रोल नहीं करती तो इनकी रक्षा नहीं हो सकती है। हम आपसे सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से सरकार को सहयोग मिलेगा नहीं।

श्री अतीकुल रहमान (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मान्यवर का आभारी हूं कि मान्यवर ने मुझे इस महत्वपूर्ण प्राब्लम पर बोलने के लिये वक्त प्रदान किया। जहां तक प्लानिंग के काम का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं कि प्लानिंग का काम शुरू होने से पहले वाली प्रदेश की देहाती जिन्दगी और उसके बाद की दशा को देखा जाय तो जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा। खासतौर कम्युनिटी प्रोजेक्ट स्कीम्स ने गांवों की हालत को बिलकुल बदल दिया है और एक नयी जागृति पैदा कर दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस साल भी जो बजट प्राविजन्स हैं उसमें स्टेज वन (stage one) के ९२ ब्लाक्स और स्टेज टू (stage two) के ७३ से ज्यादा ब्लाक्स रखे गये हैं और आगे आने वाली

[अतीकुल रहमान]

पंचवर्षीय योजना जो चार साल होंगे उसमें भी उनको लेने का इंतजाम है जिनकी तादाद ४०० से कुछ ही कम है। इससे यकीनन तीसरी पंचवर्षीय योजना में, उसकी समाप्ति तक गांवों की हालत में जो इंकलाब है वह यकीनन काबिलेदीद है। लेकिन प्लानिंग के काम में मान्यवर, इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता समझता हूं कि वह एक ऐसा काम है कि जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है।

पहली बात तो यह है कि प्लानिंग के काम में जिलों और कमिश्नरियों के टर्म्स में सोचना बेकार है क्योंकि वे एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू की सहूलियतों को देख कर बांटे गये हैं। वे डेवलपमेंट के नुक्तेनजर से नहीं बनाये गये। इसलिये प्लानिंग का काम इस सूरत में करना चाहिये कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनका पिछड़ा हुआ होना जिस स्टेज में है और जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनका तरक्कीयाफ्ता होना जिस स्टेज में है, उस के हिसाब से स्टेजेज कायम की जायं और इसके बाद डिपार्टमेंट को यह कोशिश करनी चाहिये कि वह ज्यादातर सुपरवाइजरी काम करे। वह सुपरवाइविजन करे। एक्जीक्यूशन का काम छोटे-छोटे इलाकों में, लोकल बाडीज के जरिये या ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज के जरिये करायें। आप कोई भी नक्शा इसके लिये बनायें, आपको एक्जीक्यूशन का काम छोटे दायरे में किसी बाडी के सुपुर्द करना चाहिये और उसके लिये कोई भी कमेटी हो या लोकल बाडी हो, उसे जिम्मेदार होना चाहिये। जब तक यह नक्शा सही तरीके से मुरत्तब न होगा तबतक मैं नहीं समझता कि प्लानिंग के काम में उतनी कामयाबी हो सकती है जितनी कि हम को तवक्का है या जितनी हम चाहते हैं।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करने वाला हूं कि बाज मुहकमों में कोआर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। इस वक्त मेरे जेहन में खास तौर से अपने प्रदेश के देहात हैं। देहात की जिन्दगी को ऊंचा उठाने के लिये, वहां का मयारे जिंदगी बुलन्द करने के लिये इस बात की सख्त जरूरत है कि एग्रीकल्चर, इरीगेशन, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और कोआपरेशन, इन चार मुहकमों का कोआर्डिनेशन खास तौर से अलग होना चाहिये। मान्यवर, हमने सीलिंग का बिल पास कर दिया। हदबन्दी का कानून नाफिज हो गया और उस के बाद देहात में एक नयी जिन्दगी शुरू होने वाली है। हदबन्दी के कानून में हमने मुस्तसना किया जमीन को ग्राम उद्योगों के लिये, बाग के लिये जमीन अलग मुस्तसना की और इस तरह से खास नुक्तेनजर से, एक खास जिंदगी का नक्शा अपने सामने रख कर हमने जमीन को मुस्तसना किया है यह सोच कर कि जमीन पर से बार कम हो और देश में उद्योग धंधे बढ़ें। यह सब करने के बाद हमको एक ऐसी स्कीम बनानी चाहिये कि जिस के जरिये से हर किसान खानदान के पास कम से कम एक बाग, एक उद्योग और जितनी उसकी जमीन है, वह हो। हदबन्दी के कानून के बाद इस बात का इमकान है और वह हालत पैदा होने वाली है कि जिसमें रफ्ता-रफ्ता जोतों का जो फर्क है वह कम हो और यह होता चला जायगा और इस नक्शे को नुक्तेनजर रख कर हम को एक लम्बी स्कीम बनानी चाहिये जिसमें कम से कम हर किसान खानदान के पास एक उद्योग हो, एक बाग हो, और खेती के लिये कुछ जमीन भी हो। इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिये एक लम्बे अर्से की स्कीम बनाने की जरूरत है। इसके लिये मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आपको ग्रामोद्योग के लिये एक अलहदा से डिपार्टमेंट भी खोलना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। उसको आप कायम कर दें और जिन विभागों के बारे में मैंने अभी बयान किया उनके साथ उसको जोड़ दीजिये। उनका कोआर्डिनेशन होना जरूरी है।

इसके अलावा जब तक कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का गहरा सम्बन्ध नहीं होगा, तब तक भी कोई तरक्की नहीं हो सकती। हमारे यहां छोटी छोटी जोतें हैं और उनके लिये हमको तमाम रिसोर्सेस को पूल करना होगा। जब तक हम उनको पूल नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे और उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा। अमेरिका में जहां इसकी जरूरत भी नहीं है, वहां पर ६० फी सदी जोतों में कोआपरेटिव प्रणाली देखने को मिली है।

अब एक बात मैं पानी की दिक्कत के बारे में और कहना चाहता हूं। वैसे, गवर्नमेंट तवज्जुह तो हर तरफ देती है, किन्तु फिर भी कहीं-कहीं ऐसा होता है कि जितनी तवज्जुह सरकार को देनी चाहिये उतनी वह नहीं देती है। मैं अपने इलाके के बारे में कहना चाहता हूं। वह काफी पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां उतनी तवज्जुह नहीं दी गयी है जितनी कि होनी चाहिये। मसलन, मेरे यहां नजीबाबाद तहसील में पानी का इंतजाम नहीं है। बमुश्किल तमाम, सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में वहां पर १५-१६ ट्यूबवेल्स बनाये गये हैं, उससे थोड़ा पानी मिलता है किन्तु उससे समस्या वहां की हल नहीं होती। वहां पर पानी काफी नीचे जाकर मिलता है और इस वजह से वहां मामूली कुएं नहीं खोदे जा सकते। ट्यूबवेल पर खर्चा ज्यादा आता है। चुनांचे वहां के लिये एक दूसरी स्कीम भी बनाई गयी है, लेकिन अभी तक उसको वहां लागू नहीं किया गया है। सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिये कि वहां किस चीज की जरूरत है और उसी जरूरत को पूरा करना चाहिये। इसके लिये मैं चाहता हूं इरीगेशन और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में भी कोआर्डिनेशन होना चाहिये।

एक बात की तरफ मैं और सरकार का ध्यान दिलाऊंगा। आपका रबी और खरीफ आन्दोलन चलता है। लोग इस कैम्पेन के लिये दिये जाते हैं। वे कहते हैं कि वहां किसान नहीं मिलते। किसान तो खेतों पर होते हैं। चुनांचे जब तक उनके लिये मेज कुर्सी न हो, जब तक लेक्चर देने के लिये वहीं कुछ लोग न हों, जब तक कलम और रजिस्टर न हो, तब तक वे रबी और खरीफ कैम्पेन को चला ही नहीं सकते। आपको उनके इस नजरिये को बदलना होगा और उनसे कहना होगा कि वे खेतों पर जायं और वहां कुछ किसानों को जमा करके उनको वहां पर ही समझायें कि यह क्या चीज है। जब वे खेतों पर जाकर इस तरह से काम करेंगे तभी आपको यह कैम्पेन सफल हो सकता है, वरना नहीं।

एक सब से अहम बात है एजूकेशन की, उसके मुताल्लिक भी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। एजूकेशन प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। मान्यवर, एजूकेशन एक ऐसी चीज है कि डेमोक्रेसी में जितनी भी उसके लिये कोशिश की जाय वह कम है। मुझे याद आता है जब टैगोर साहब ने रूस का दौरा किया तो जो उन्होंने अपने असरात लिखे थे, उसमें लिखा था कि यह मुल्क बहुत दिनों तक डिक्टेटरशिप के नीचे नहीं रह सकता, इसलिये कि इतनी बड़ा और ऐम्बीशस प्लान है एजूकेशन की और यह बात नामुमकिन है कि बहुत अर्से तक वह लोग ऐसे राज्य में रहें जिसको कि एक आइडियल चीज नहीं समझा जाता।

अब हमारे यहां अगर देखा जाय, जो एजूकेशन की हालत है, तो यह खतरा महसूस होता है कि यह डेमोक्रेसी कुछ दिन रहेगी भी या नहीं। यह हमारे यहां सूरत है एजूकेशन की। तो मेरा मतलब यह है कि सोशल एजूकेशन में ऐडल्ट एजूकेशन शामिल करनी चाहिये और नये टेक्नीक से काम लेना चाहिये। आजकल सिनेमा, रेडियो और नये नये सामान दिखाई पड़ते हैं जो एटींथ, नाइंटींथ और ट्वेंटीअथ सेंचुरी के शुरू में नहीं थे। आज तालीम देने के जो सामान हैं उनके जरिये हम सोशल एजूकेशन और ऐडल्ट एजूकेशन को शामिल करके देहात को तालीमयाफ्ता करना चाहें तो हमें काफी कामयाबी हासिल हो सकती है और वह भी थोड़े खर्च में। मैं देखता हूं कि सोशल एजूकेशन का काम उस पैमाने पर नहीं हो रहा है।

एक यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि एक स्कीम फार रि-ओरिएंटेशन आफ विलेज स्कूल टीचर्स (Scheme for reorientation of village school teachers) की थी। गवर्नमेंट आफ इंडिया उसमें मदद देती थी। अब नहीं देती, लेकिन आप उसे चलाइये तो अच्छा है। मैं नहीं समझता कि इस बजट में किस सबब से उसको नहीं रखा गया।

फील्ड वर्कर्स का सवाल है। आप बजाय इसके कि एफ डिपार्टमेंट की फौज इकट्ठी करें किसानों में से ही वर्कर्स को ट्रेंड करें तो आप देखेंगे कि इसमें पैसा भी काफी बचेगा और कितनी जागृति पैदा होती है और कितना पार्टिसिपेशन होता है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है।

[श्री अतीकुल रहमान]

आज किसान, अवाम और जो सरकारी वर्कर या अफसर कहिये, उसके दरमियान जो खलीज इस वक्त मौजूद है उसकी वजह यह बात भी है कि जो रुपया दिया जाता है, वह किस तरह से लैप्स हो जाता है इसका पता उन्हें नहीं चलता। किसान मजदूर को खबर भी नहीं होती कि कहीं रुपया है भी। वह इस वजह से खबर नहीं होती कि डिपार्टमेंट के और अवाम और किसानों का सम्बन्ध बहुत गहरा नहीं है जो होना चाहिये। इसलिये ऐसा इन्तजाम होना चाहिये कि रुपया लैप्स न हो, क्योंकि जाहिर है कि रुपयों की जरूरत तो है ही, रुपयों की जरूरत कम तो होगी नहीं।

अब मान्यवर, मैं फैमिली प्लानिंग के मुताल्लिक अर्ज किया चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग इस सूरत में तो कामयाबी हो ही नहीं सकती कि आप सेन्टर से पैसा दीजिये। जब तक कि सोशल एजूकेशन, ऐडल्ट एजूकेशन बड़े पैमाने पर न हो, जबतक हर खानदान का एक डाक्टर न हो जिसको कि वह खानदान का डाक्टर नहीं, बल्कि अपना मूनिस व मददगार और दोस्त समझे और वह डाक्टर उनकी जिन्दगी में, उनकी सामाजिक जिन्दगी में ऐसा दखील हो कि उनपर असर रखता हो, तब तक फैमिली प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती। इसे कामयाब बनाने के लिये सोशल एजूकेशन और ऐडल्ट एजूकेशन के जरिये से और ऐसे डाक्टर्स के जरिये से इस चीज को कार्यान्वित करें।

हेल्थ और सेनीटेशन के मुताल्लिक भी मुझे यह अर्ज करना है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं, मसलन मेरे जिले में मेरे इलाके के आस-पास का इलाका है, जिसमें हेल्थ और सेनीटेशन का कोई खास प्रबन्ध नहीं है, वहां यह प्रबन्ध होना चाहिये। जहां सेहत के लिये पानी बहुत खराब है ऐसे इलाकों की खासतौर से खबरगीरी होनी चाहिये।

इन अल्फाज के साथ में कटौती के प्रस्ताव की मुखालफत करता हूं और माननीय मन्त्री जी के प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ९,५२,६६,००० रुपये का अनुदान सदन में प्रस्तुत हुआ है और उसके ऊपर माननीय गेंदासिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अभी कुछ समय पहले माननीय नेकराम जी शर्मा ने प्लानिंग में क्या-क्या खामियां हैं, उन पर प्रकाश डाला। लेकिन माननीय मन्त्री जी की त्योरी चढ़ गई और उनसे कहा गया कि तुमको अधिक घमण्ड है। इससे स्पष्ट है कि इनकी पार्टी मीटिंगों में इनके सदस्यों के जज़बात कैसे दबाये जाते हैं। अपने पद के आधार पर मन्त्री लोग कैसे माननीय सदस्यों को बोलने से मना करते हैं जिससे वे सदन में अपने जजबात न रख सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं और गांव के क्षेत्र से आता हूं। मैंने देखा है कि विकास खंडों में काम करने वाले, चाहे बी० डी० ओ० हों या बी० एल० डब्लू हों, सरकार की तरफ से उनके पास एक योजना जाती है कि खरीफ आन्दोलन चलाना है चारों तरफ से पर्चे बंट जाते हैं। वे यह नहीं देखते कि भूड़ की जमीन है, वहां जापानी ढंग से धान बोया जा सकता है या नहीं। मैंने वहां पोस्टर लगे देखे कि जापानी ढंग से धान पैदा करो। किसानों से कहा गया कि यदि प्लानिंग के अफसर आवें तो तुम यह कहना कि जापानी ढंग से खेती करना हमको बताया गया है और हमारे यहां के ग्रामसाथी बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि केवल आंकड़ों के आधार पर चलने वाली यह सरकार कामयाब नहीं हो सकती। गेंदासिंह जी ने तो ठीक ही कहा कि प्लानिंग विभाग खत्म कर दिया जाय। इसका एक ही कारण है कि हमारे गरीब किसानों द्वारा टैक्स के रूप में दिया हुआ पैसा इस विभाग में बरबाद किया जा रहा है, वह पानी की तरह से बहाया जा रहा है। एक साथ कई योजनायें भेजी जाती हैं कि मछली पालो, मुर्गी पालो, और न जाने क्या—क्या पालो। पूर्वी जिलों में मछली पाली जाती हैं, लेकिन पश्चिमी जिलों को भी यह बतलाया जाता है। गांव के प्रधान और जनता योजनायें सुनते—सुनते परेशान हो जाते हैं कि अब यह सरकार आदमियों का पालन छोड़ कर मुर्गियों और मछलियों का पालन सिखाने चली है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा कि आज गांवों में हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट और ग्रेजुएट मारे-मारे फिरते हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य था कि बेकारी दूर करेंगे, उद्योग-धन्धे खोलेंगे, काटेज इन्डस्ट्री खोलेंगे, लेकिन वह कुछ नहीं हो रहा है। काटेज इंडस्ट्रीज के नाम पर शहरों में रुपया खपाया जा रहा है। जिस नाम से रुपया लिया जाता है, पता नहीं कि वह उद्योग वहां चलता भी है या नहीं। आज तक सरकार ने इसकी कोई जांच नहीं की। एस्टीमेट्स कमेटी में मैंने वहां कहा कि हरिजन सहायक के नाम पर बड़े-बड़े हरिजन पैसा ले लेते हैं जोकि वास्तव में नेतागीरी करते हैं और बड़े आदमी हैं, लेकिन गरीबों को पैसा नहीं मिल रहा है। तकावी के बारे में अभी एक माननीय सदस्य सदन को अगवत करा चुके हैं। साधन सहकारी समितियों को मैंने देखा कि गांवों में २४ घंटे में प्रस्ताव पास कराकर हजारों फर्जी समितियां बन गईं। मैं जिला कोआपरेटिव बैंक का डाइरेक्टर हूं और बैंक से भी सम्बन्ध रखता हूं। मने देखा कि हर साधन सहकारी समिति में २५ रुपया का एकाउन्टेंट बढ़ा दिया लेकिन काम कुछ नहीं बढ़ा। उसमें गांव की इकोनामी को अध्ययन करके कोई योजना रखनी चाहिये जिससे वहां के लिये कोई अच्छा प्लान बन सके। लेकिन इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

कहा जाता है कि सरकार ने गांवों को अधिकार बहुत दे दिये हैं। मैं नेकराम जी की इस बात से सहमत नहीं हूं जैसा कि उन्होंने कहा कि ब्लाक को खत्म करके साधन सहकारी समिति को रुपया दे दीजिये। यह गलत है। जबतक एक कन्ट्रोलिंग एजेंसी नहीं रखेंगे जो यह देखे कि रुपया ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं, उस समय तक काम ठीक से नहीं होगा और न उसके ऊपर नियन्त्रण रख सकेंगे।

कहा जाता है कि खाद लगाइये और अधिक पैदा कीजिये। बी० एल० डबलू गांव में जाता है और यह भी नहीं देखता कि इस किस्म की किसी जमीन में गुर्र भी लगती है या नहीं, खाद की आवश्यकता है या नहीं। वे अपनी जिद करके कि उनको यह प्लान पूरा करना है, गांव में काम करते हैं। उनको गांव के कामों का कोई अनुभव नहीं है जिससे कार्य नहीं हो पाता। अनुभव तो उस किसान को है जो वहां की जमीन से, वहां की जलवायु से जानकार है, जो यह जानता है कि हमारे यहां कितनी बारिश होती है और कैसे उत्पादन बढ़ सकता है। किसान को आवश्यकता है पानी की, परन्तु सिंचाई विभाग का मामला हमारे प्रदेश में दिन पर दिन जटिल होता चला जाता है। कहा जाता है कि हम उत्पादन बढ़ावेंगे। उत्पादन के लिये सरकार अच्छा बीज, खाद और पानी देगी तभी तो वह बढ़ सकेगा। नहीं तो यदि पानी समय से नहीं मिला तो बीज, खाद और किसान की मेहनत सब बेकार हो जायगी। जब तक नहर विभाग और प्लानिंव विभाग एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक इस प्रदेश की खाद्यान्न की समस्या हल नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि ब्लाक्स में सोशल बी० एल० डब्लू० और ए० डी० ओ० भी काम करती हैं। मैंने देखा कि हर ब्लाक में वीमन ऐ० डी० ओ० होने की वजह से पार्टीबन्दी हो गई है। वहां पर काम धन्धा तो कुछ नहीं रहा, परन्तु यह औरतें विभाग की, लिपस्टिक लगा कर जाती हैं और गांव की औरतों को बताती हैं कि तुम इस तरह से काम करो। वे कण्डा पाथने वाली और अपने पति को मेहनत के बाद कलेऊ कराने वाली उन ग्रामीण औरतों के सामने लिपस्टिक लगा कर जाती हैं, उसका प्रदर्शन करती हैं, तो गांव की औरतें चुप-चाप उनकी बातों को सुनती रहती हैं और कुछ नहीं कहती हैं। बाद में उन को भला बुरा कहती हैं, काम कुछ नहीं होता। अगर आपको महिलाओं में काम बढ़ाना है तो आप अलग ही ब्लाक बना कर देखें कि वास्तव में उससे कोई सफलता हो सकती है या नहीं। ए० डी० ओ० (वीमेंन) आदमियों के साथ मिलकर औरतों में काम करेंगी तो इससे क्षति होती है।

श्रीमन्, इस बजट में पी० आर० डी० का बजट भी शामिल है। यह दल नवयुवकों का संगठन करके देश के भावी निर्माताओं का काम करता रहा है। बजट में देखने से मालूम

[श्री मलिखानसिंह]

होता है कि सरकार इसको इधर-उधर करके किसी तरह से खत्म करना चाहती है। इस सरकार ने जो इकोनामी का एक दौर-दौरा चलाया है उसके अन्तर्गत विभागों को खत्म करके यह दिखाना चाहती है कि हमने इतनी इकोनामी करदी। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार बड़ी अच्छी इकोनामी कर सकती है अगर यह सभी डिपार्टमेन्ट्स को खत्म करके सारा रुपया इकट्ठा करके कह दे कि हमने इतने रुपये की इकोनामी करदी। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे देश का कुछ भी बने किन्तु जहां पर इकोनामी करने की आवश्यकता हो वहां पर इकोनामी की जाय। जो विभाग बिलकुल बेकार हैं, जनता पर एक भार-स्वरूप हैं उनको अगर यह सरकार खत्म करदे तो उसमें कोई मतभेद की बात नहीं होगी लेकिन एक ऐसा विभाग जिसकी एजेंसी के द्वारा पब्लिक में काम होता है वह यदि समाप्त किया जाता है तो बहुत ही हानि होगी, यदि कोई व्यक्ति मार्शल का शासन करना चाहे। तो इस विभाग की ऐजेंसी के द्वारा पब्लिक में संघटन स्थापित किया जा सकता है और करना चाहिये ताकि जनता अपनी रक्षा स्वयं कर सके।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जब आप देहात में चलेंगे तभी आप की प्लानिंग सफल होगी। गांवों में ट्यूबवेल खोदे। वहां पर जहां पहले तीन आदमी रहट पर काम करते थे अब अकेला आदमी काम करता है। आज देहात में बे पढ़े-लिखे आदमी कितने बेकार हो गये हैं क्या उनके आंकड़े आपने इकट्ठा किये? क्या अपने गांवों में कटेज इन्डस्ट्रीज कायम कीं जिसमें वह पढ़े लिखे लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग देकर लगाया जा सके। जहां तक मैं समझता हूं, सरकार ने इस तरह की कोई योजना नहीं बनाई है। आज बे पढ़े-लिखे लोग शहर में रिक्शा चलाकर अपना पेट भरते हैं और दोपहर में तपते हैं जिससे टी० बी० हो जाती है उनके लिये आपने कोई योजना नहीं बनाई। आपकी सारी योजनायें पढ़ लिखे लोगों के लिये हैं।

आपके केवल यह कह देने से कि गांव की पर-कैपिटा आमदनी इसलिये कम होती जा रही है कि आबादी बढ़ती जा रही है, काम नहीं चलेगा। हमारे यहां जबतक लोगों का चारित्रिक बल नहीं बढ़ेगा तब तक किसी तरह से कन्ट्रोल नहीं हो सकता। हमारे यहां बहू के बच्चे होने पर कहीं सास के भी बच्चा हो जाता था तो वह शर्म के मारे मर जाती थी और सोचती थी कि अब बहू के बच्चे होने लगे हैं इसलिये हमको अलग ही रहना चाहिये। लेकिन आज क्या होता है कि बहू के अलग लड़का हो रहा है और सास के अलग! कोई चिन्ता नहीं है। तो जब तक चारित्रिक बल नहीं आयेगा, जब तक इस तरह की शिक्षा नहीं दी जायगी तब तक खाली योजनायें बनाने से कि आपरेशन किये जांय जिसमें आबादी कम हो जाय, कुछ नहीं हो सकता। इसलिये संयम होना चाहिये। स्त्री हो या पुरुष हो, जब तक संयम नहीं रखेंगे और चरित्र बल को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक प्रदेश और देश की आबादी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जायगी।

इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करते हुये मन्त्राणी जी से निवेदन करूंगा कि वह गांवों की स्थिति का सर्वेक्षण कराके कार्य करें।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण अनुदान पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

इस सदन में जिस तरह से नियोजन के सम्बन्ध में तबर्रा पढ़ा गया है उसे सुनकर मुझे एक अजीब तकलीफ होती है और ऐसा लगता है कि यह तबर्रा पढ़ने वाले चाहते हैं किसी तरह की कोई योजना न बनाई जाय, सारा काम अनियन्त्रित तरीके से चले और अगर कोई गवर्नमेन्ट किसी तरह का नियोजन करती है तो अपराध करती है। नियोजन तो एक खयाल है कि हमको किस तरह काम करना है, कैसे आमदनी बढ़े और कैसे खर्च किया जाय। उसमें गलती भी हो सकती है। कहीं कामयाबी हो सकती है और कहीं नाकामयाबी भी

हो सकती है । लेकिन उसकी हमेशा बुराई ही की जाय तो कैसे भला होगा इस देश का, कैसे योजना चलेगी, कैसे बेकारी दूर होगी, कैसे गरीबी दूर होगी और कैसे समस्या का हल होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

यह कहा गया कि नियोजन के जो ब्लाक बना रखे हैं और वहां जो ब्लाक आफिसर्स हैं उनके लिये जीपें दीं और तहसीलदार जो सारी तहसील का काम करता है उसको कुछ नहीं दिया। बी० डी० ओ० को जीप दी तो ए० डी० ओ० झगड़ते हैं, वी० एल० डब्लू०, भी चाहता है कि वह भी मोटर पर जाय। अजीब बात है कि अगर आपने बड़े अफसर को सवारी दी तो उसका अर्दली भी कहे कि मुझे भी सवारी चाहिये। ब्लाक में जो जीपें दी गई हैं तो काम के लिए दी गई है और वह इसलिये हैं कि ब्लाक के अफसर का कंटेक्ट रहे उन गांवों से जो उसके क्षेत्र में पड़ते हैं।

हर जिले की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन कानपुर जिले के बारे में कह सकता हूं कि जितने ब्लाक खुले हैं उनके कार्य से उस क्षेत्र के गांवों का नक्शा बदल गया है। जिन्हें जरा भी शंका हो उन्हें मैं दावत देता हूं कि वह आकर देखें। २० वर्ष पहले अगर वह गांव देखा गया था तो आज वह पहचाना नहीं जा सकता। जिन्होंने सिवाय बुराई करने के, लोगों के दिल तोड़ने के, और नीची बात करने के कुछ नहीं किया वह कैसे ऊंची बात करेंगे और कैसे उनको सन्तोष होगा ? लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे-ऐसे गांव हैं जिनकी उपज पिछले २० वर्ष के मुकाबले में आज करीब-करीब दुगनी हो गई है। जिन क्षेत्रों में धान बोया ही नहीं जाता था और अगर बोया भी जाता था तो उसकी उपज ६—७—८ मन फी बीघा थी और धान में किसी तरह की खाद देना खाद को बरबाद करना समझा जाता था, वहां आज धान की खेती की जाती है।

हमारा जिला नहर की टेल पर पड़ता है, पानी बहुत नहीं मिल पाता है, शायद वक्त पर भी नहीं मिलता है, लेकिन जो कुछ मिलता भी है इन ब्लाकों की योजनाओं की बदौलत और कृषि अभियान की बदौलत लोगों ने सीखा है कि धान भी है जिसमें खाद की जरूरत होती है और जब से उसमें खाद दिया जाने लगा तो १६—१८—२० मन फी बीघा होता है। जापानी धान के लिये कहा जाता है कि ३० मन फी एकड़ होता है। मैं समझता हूं कि हम भी काफी आगे बढ़े हैं। जहां इस तरह के अभियान चले वहां उपज बढ़ी है। धान की उपज करीब-करीब २० मन फी बीघे होती है। फिर उसी खेत में किसान मटर और चना बो देता है और वह भी १२, १३ और १४ मन तक फी बीघे उपज होती है। तो इस तरह से एक खेत में जहां वह ६ और ७ मन उपज लेता था अब ३०, ३० और ३५, ३५ मन उठा लेता है। अगर अब भी उसके बाद आप यह कहें कि यह ब्लाकों और योजनाओं की सारी कोशिशें व्यर्थ हैं तो आपकी अपनी अक्ल मुबारक। मैं कह सकता हूं कि खेती की उपज में उन्नति हुई है देश आगे बढ़ा है। भले ही यह कहा जाय कि जिस लक्ष्य को हम चाहते थे वह उससे पूरा नहीं हुआ और राम राज्य की स्थापना नहीं हुई, लेकिन यह भी नहीं है कि हम बिलकुल ही आगे नहीं बढ़े हैं। और हमारी योजनाओं पर अमल करने के कारण फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ है, यह बिलकुल निश्चित बात है।

एक बात की तरफ मैं माननीय मंत्राणी जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस देश का निस्तार हो नहीं सकता जब तक कि खेती की उपज न बढ़े और उसे जितना बढ़ाया जा सके उतना बढ़ाया जाय, लेकिन पशुओं की कमी ने हमें आज एक बड़े संकट की स्थिति में में डाल दिया है। जिन क्षेत्रों में अच्छे बैल होते थे वहां अब अच्छे पशु मिलते ही नहीं। नतीजा यह हुआ है कि बैलों की जगह पर भैंसों से गुजारा करना पड़ रहा है। और अगर यही हालत रही और पशुओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे संकट आ सकता है। आज हम खेती के लिये तमाम जमीन तोड़ते चले जाते हैं, लेकिन जिन पशुओं की बदौलत खेती होती है उनके पालन की तरफ किसान का ध्यान बिलकुल

[श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा]

नहीं है । इसलिये मैं कहता हूं कि जहां हम रबी और खरीफ का अभियान चलाते, हैं वहां गोसंवर्धन के अभियान को भी अवश्य चलावें और लोगों के जहननशीन करावें कि जब तक पशुओं की नस्ल नहीं सुधारी जायगी तब तक यह जो खेती की उपज बढ़ रही है वह नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारा देश इस काबिल नहीं है कि ट्रैक्टरों से खेती की जा सके और जब ट्रैक्टरों का प्रयोग हम निर्धनता के कारण नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि गोसंवर्धन का अभियान खेती के लिये अत्यन्त आवश्यक है ।

जहां अच्छे बीज और अच्छे खाद की आवश्यकता खेती के लिये होती है वहां सिंचाई की की आवश्यकता भी लाजिमीतौर पर है । मेरे क्षेत्र में नलकूप नहीं बने । अकसर यह शिकायत की गई कि जहां पर नलकूप बने वहां कामयाब नहीं हुये, अगर बने भी हैं तो एनरजाइज नहीं किये जा सके और उनके करण बहुत सी जमीन नालियों में बेकार रुकी पड़ी हुई है । मैं कहता हूं कि अगर कुयें बनवाकर सिंचाई की जा सके तो उस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये । लेकिन जहां पानी का स्रोत बहुत गहरा है और जहां सौ और ९० फुट पानी निकलता है वहां सरकार बांधियां बनवाने का इंतिजाम करे जहां बरसात का पानी रोकने की व्यवस्था हो । इसके अलावा जो पुराने तालाब पुरने पर आ गये हैं और पचासों सालों से जिनको गहरा करने की योजना नहीं की गई अब उनको गहरा करने की योजना होनी चाहिये । जब तक स्थानीय सींच के साधनों को नहीं पैदा किया जायगा तब तक भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा, इसलिये कि अभी पूरा और वक्त पर पानी मिलने की आशा नहीं की जा सकती ।

कानपुर जिले की एक और सिंचाई की बात की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गंगा और यमुना के अलावा उस जिले में ६ और छोटी छोटी नदियां बहती हैं और उनमें करीब साल भर पानी रहता है और नहरों के खारिजे का पानी भी इन नदियों में आ जाता है और उसका उपयोग पूरा नहीं हो पाता। सिंचाई की योजनाओं को अगर इन नदियों से युक्त करके सिंचाई का कोई इंतिजाम हो सके तो मैं समझता हूं कि हमारे जिले की सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है । एक बात और, हमारे जो कृषि अभियान चलते हैं उसमें एक इस योजना को भी जोड़ना चाहता हूं कि जब हारवेस्टिंग यानी कटनी और मड़ौनी होती है तो अक्सर फसल को उड़ाने के लिये किसान को हवा के इंतिजार में दो दो, चार चार दिन बीत जाते हैं । तो हमें इस तरह के यंत्र, जो मानव द्वारा आसानी से चलाये जा सकें और जिनसे पंखे के द्वारा उसौनी की जा सके, बनाने चाहिये । उनकी हमें व्यवस्था करनी चाहिये । किसान को या तो वे किराये पर मिल सकें या वैसे ही आप उनको मुहैया करें । इससे किसान का अन्न ठीक समय से उनके घरों पर पहुंच जायगा ।

इस ब्लाकों में एक और बड़ी दिक्कत बीज गोदामों के बारे में है । कृषि विभाग की ओर से भी बीज गोदाम हैं और दूसरे विभागों की तरफ से भी हैं । ये बीज गोदाम केवल बीज देने का काम करते हैं । उनके अतिरिक्त अगर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी बनाई जायं तो ज्यादा किसानों को सुविधा हो सकती है । जब किसानों को रुपये की आवश्यकता हो तो ये सोसाइटीज उनको उनका अनाज बंधक रखकर रुपया एडवान्स कर दें और जब अनाज का भाव ठीक हो, किसान उनसे लेकर अपना नाज बेच सके और उनको पैसा अदा कर सके । ऐसी सोसाइटीज कई स्थानों पर कायम भी हुई और उनका बहुत अच्छा नतीजा निकला है । मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की मार्केटिंग सोसाइटीज और स्थानों में भी ज्यादा से ज्यादा खोली जायंगी ।

हमारे यहां कुछ नौजवानों ने साधन सहकारी समितियों के निर्माण में बड़ी दिलचस्पी ली है और पूरी कोशिश की है । हमारे जिले में करीब करीब ८०० साधन सहकारी समितियां बन गई हैं । यह जरूर है कि उनका उपयोग किसानों को जितना करना चाहिये था उतना नहीं किया है । मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये समितियां बन गई हैं तो निश्चित रूप से उनसे वे साधन किसानों को प्राप्त हो सकेंगे जिनसे वे खेती में उन्नति कर सकेंगे ।

इन ब्लाकों के अन्तर्गत आपने हेल्थ सेंटर्स भी खोले हैं। उनके अन्तर्गत आपने वे साधन उपलब्ध किये हैं जिनके द्वारा वहां के लोग रोगो से संघर्ष कर सकते हैं। आपने लोगों को दवाइयां भी दी हैं और जहां डाक्टर गये हैं वहां लोगों की बड़ी सेवा हो रही है। ब्लाकों में डाक्टर लोग दिलचस्पी से काम कर रहे हैं। वहां पर आपने जो दवाइयां रखी हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत है उनको १०-१५ गांवों में जाना पड़ता है, लेकिन उनके साथ जाने के लिये कोई नहीं दिया गया है। न उनको इतना अलाउन्स ही दिया जाता कि वे अपने साथ चौकीदार को ले जा सकें। जब आपने नर्सों का इन्तजाम किया है तो आप उनके साथ दूर दूर तक जाने वाले का भी इन्तजाम कर दें तो बहुत अच्छा होगा। उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। कहा जाता है कि इस योजना में उसके लिये गुंजायश नहीं है, लेकिन मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनके लिये कुछ अवश्य करें। साथ ही जब वे जच्चा बच्चा के लिये दूर दूर जायं तो चौकीदार इत्यादि उनके संरक्षण के लिये दिया जा सके तो अच्छा है।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार की ओर से जो मांग प्रस्तुत की गई है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं समझता हूं अब समय १० मिनट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---१० मिनट का समय ठीक रहेगा, विशेष अवस्थाओं में १५ मिनट तक दिये जा सकते हैं। सजीवनलाल जी को अभी १५ मिनट ही मिलेंगे।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह अनुदान ९,५२,६६,००० रुपये का सदन के सामने प्रस्तुत है और उसी अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव श्री गेंदासिंह जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सदन में बार-बार इस बात की चर्चा सरकार की ओर से की गई है कि हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। हमारी कृषि व्यवस्था इतनी सुधरी हुई नहीं है कि हम उसमें आत्म-निर्भर हो सकें। अभी माननीय मेहरोत्रा जी बोल रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीच में २, ३ बातें ऐसी कहीं जिनसे मालूम ऐसा होता था कि इनका सम्बन्ध गांवों से नहीं है। उन्होंने कहा हमारे ब्लाक में तो गांवों के नक्शे बदल गय, पहचानना मुश्किल हो गया। पता नहीं वह कौन से उनके गांव हैं। और यह भी कहा कि कोई भी आकर देख सकते हैं। मैं इनको चैलेन्ज दे रहा हूं कि हमारे यहां वह आकर देखें और बतायें कि किन गांवों के नक्शे बदल गये हैं, कहां तरक्की हुई है? उसके आगे वह कहते हैं कि पैदावार बढ़ गई है, दुगनी पैदावार हो गई है। और फिर उसके आगे जा करके कहते हैं कि किसान के बैल कमजोर हैं। जब उसकी पैदावार बढ़ गई, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है तो किसान और उसके बैल क्यों कमजोर हैं? इसलिये मैं समझता हूं मेहरोत्रा जी ने बात इसलिये कही कि कुछ अधिकारियों को खुश किया जाय। इनके घर के, परिवार के लोग ऊंची-ऊंची जगहों पर नौकर हैं, उनके ऊपर भी ऐसा प्रभाव पड़े। मैं कह सकता हूं जो-जो उनके परिवार के लोग नौकर हैं सूचना विभाग के अन्दर श्री टंडन जी हैं और अगर जिक्र करूं तो अच्छा नहीं होगा---तो हमारा कहना यह है कि ऐसे तथ्य रखे जायं जिनके आधार पर एक योजना निर्मित की जाय. . . . .

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि उन्हें मालूम होता है कि एक माननीय सदस्य के रिश्तेदार या सम्बन्धी किसी विभाग में हैं और कर्मचारियों को खुश करने के लिये ही ऐसी स्पीच कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुकूल नहीं है। इस पर आप व्यवस्था दें कि किसी माननीय सदस्य का नाम ले कर कहना कहां तक उचित है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---मैं तो नौकरी पर लानत भेजता हूं। मेरा कोई रिश्तेदार कहीं नौकर नहीं है। जो आदमी ऐसा कह रहा है वह अपनी जबान गन्दी कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसे मामलों में अगर किसी माननीय सदस्य का स्पेसिफिक नाम लिया जाय तो आपत्तिजनक समझता हूं । लेकिन आमतौर पर कह देने से कोई आपत्तिजनक प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इन्होंने कहा था कि मुझसे पहले जो वक्ता बोले थे I think this kind of reference is not justified.

श्री उपाध्यक्ष—अगर नाम लेकर ऐसा कहा है तो ठीक नहीं है ।

श्री सजीवनलाल—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना था कि जो योजना चल रही है, प्रथम और दूसरी समाप्त हो गई, तीसरी योजना प्रदेश के सामने है और सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि कृषि व्यवस्था हमारे प्रदेश की सुधरे । कृषि व्यवस्था के ही आधार पर हमारे उद्योग धंधे, और देश की तरक्की हर पहलू से हो सकती है । लेकिन कृषि व्यवस्था तीसरी योजना के आरम्भ होने तक नहीं सुधर पाई । उसके कुछ कारण हैं । कारण यह हैं । जो वस्तु किसान पैदा करता है उसका कोई मूल्य नियंत्रण नहीं हो सका है । कारखानों से उत्पादित वस्तुओं और खेती से उत्पादित वस्तुओं में कोई समानता लाने का प्रयास नहीं किया गया, कोई संतुलन नहीं है । जब तक इनमें संतुलन नहीं होगा तब तक किसान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी । किसान जो वस्तु पैदा करता है उसे उसके दाम बाजार में उचित मिलने चाहिये । सट्टेबाज उसकी पैदा की हुई चीजों को अधिक मुनाफे पर न उठा सकें इसलिये उस पर नियंत्रण होना जरूरी है, अनिवार्य है ।

इसी तरह से तकावी का जो तरीका है उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूं । तकावी के तरीके को भी अगर नहीं बदला जाता तो नतीजा यह होगा कि जिसके लिये तकावी सरकार की तरफ से दी जाती है उस तक पहुंचने में तमाम अड़चनें पड़ती हैं, किसान को तकलीफें उठानी पड़ती हैं, तहसील में जाना पड़ता है, तहसीलदार, लेखपाल या अन्य अधिकारियों के फैसलों में वह उलझे रहते हैं । ब्लाक की तरफ से कहा जाता है कि तुम्हें तकावी दी जा रही है खाद के सम्बन्ध में, बीज के सम्बन्ध में और जब तकावी लेने के लिये वह जाता है तो ब्लाक अधिकारी की सिफारिश के बावजूद भी तकावी उसे आसानी से नहीं मिल पाती है ।

मैं यह कहूंगा कि सिंचाई के जो छोटे-छोटे साधन थे वे धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं । गांव के तालाब, छोटी छोटी झोलें और ज्यादातर कुएं नष्ट हो रहे हैं । उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया । अगर उनकी तरफ सरकार का ध्यान पहले से गया होता तो कुछ न कुछ हमारे देश के अन्दर अन्न उत्पादन की समस्या हल होती । आज नहरों के जरिये से ही सिंचाई की जाती है और छोटे-छोटे साधन जो किसानों के लिये अनिवार्य हैं, जिनसे पैदावार बढ़ सकती है उनकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । सरकार का ध्यान उनकी तरफ जाना अनिवार्य है । जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं जैसे गंडक योजना, शारदा सागर योजना ये तो चलती ही रहेंगी, लेकिन जो छोटी सिंचाई की योजनायें हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये ।

गांव के अन्दर रास्ते दुरुस्त नहीं हैं और न वे सड़कें हैं जिनसे माल ढोकर शहर के अन्दर उचित मूल्य पर बेचा जा सके । इसलिये जरूरी यह है कि गांव के विकास के लिये गांव के अन्दर सड़कें हो जायं, रास्तें हो जायं जिससे पैदावार का उचित मूल्य पाने के लिये किसान शहर की मंडियों में आसानी से अपने सामान को बेच सकें । इसलिये जरूरी है कि गांव के वे रास्ते जिन से किसान अपने सामान को शहर में लाने के लिये तैयार हो, पक्के किये जायं और तीसरी योजनान्तर्गत उन्हें प्राथमिकता दी जाय ।

नियोजन का कार्य लगभग १० साल से चल रहा है, लेकिन ऐसे गांव पड़े हुये हैं जिनको पता तक नहीं है कि नियोजन कैसा है । इस नियोजन के आधार पर गांव के लोगों के हित के लिये क्या होगा, गांव के किसान के लिये क्या हो रहा है, गांव के मजदूर तथा मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये क्या हो रहा है इसे गांव की जनता नहीं समझ सकी है और जब तक गांव की

जनता उसे न समझ पाये तब तक वह योजना जनता की योजना नहीं है। मेरी समझ में यह योजना पूंजीपतियों की, सेठ व साहूकारों की तथा टाटा व बिरला की योजना है। अगर जनता की योजना होती तो जनता को पता होता कि उसके लिये कौन-कौन से कायदे कानून बनाये गये हैं, कौन-कौन सी सुविधायें सरकार की तरफ से उसे दी जा रही है। लेकिन क्या वह समझ पाई है? ११ साल के उपरान्त भी आज गांव का किसान आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है।

अभी तक ४०३ करोड़ रुपये प्लानिंग के ऊपर खर्च किये गये और इस खर्चे में भी यदि देखा जाय कि गांवों पर कितना खर्च किया गया तो यही पता चलेगा कि इन गांवों पर नहीं के बराबर खर्च हुआ है। जो खर्चा हुआ है वह या तो ब्लाक की इमारत बनाने में खर्च हुआ है या जीप के ऊपर खर्च हुआ है। ब्लाक की बिल्डिंग बने हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और उसका गिरना शुरू हो गया। जीपें दी गयीं जिन पर बैठ कर बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० गांव के किसानों की हालत देखने जाते हैं। जहां तक रास्ते ठीक हैं वहां तक जीप जाती है, फिर वापस लौट आती है और बहुत से गांव अछूते रह जाते है। जनता उन गांवों की आज तक नहीं समझ पाई है कि बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० और ग्राम सेवक हमारे कल्याण के लिये सरकार की ओर से भेजे गये हैं। इसलिये जरूरी है कि उन जीपों को ले लिया जाय और उन्हें साइकलें दी जायं, उनके जरिये वे गांव में पहुंच सकते हैं और साइकिलों के जरिये पहुंच कर वे जनता के अन्दर अपने आन्दोलन तथा प्रोग्राम को विकसित करें।

मेरा यह कहना है कि ये दोनों योजनायें जनता की योजनायें नहीं थीं, ये पूंजीपतियों की योजनायें थीं। अगर जनवादी और समाजवादी योजनायें होतीं तो जनता से पूछा जाता, लेकिन ऊपर से योजनायें आती हैं और ऊपर से लादी हुई योजनायें जनता का कल्याण नहीं कर सकती हैं।

अब कुछ दिन पहले यह हुआ है कि जनता के बीच में भी बैठ कर पूछा गया कि आपके गांव के विकास का कौन सा रास्ता हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे भी सही माने में हमारे गांवों का विकास नहीं हो सकता है। अगर गांवों का विकास करना है तो २०-२५ साल की एक निश्चित योजना होनी चाहिये और हर पांच साल के बाद उसका एक टारगेट मुकर्रर किया जाय और यह देखा जाय कि उतने दिनों में हमने कौन से काम पूरे किये और कौन कौन से काम अधूरे रह गये। हर पांच साल के बाद उसकी जांच होनी चाहिये तब हमें सफलता मिल सकती है।

सरकार के पास कोआपरेटिव, ऐग्रीकल्चर, इर्रीगेशन, ये सब विभाग हैं, लेकिन इन सब विभागों में आपस में कोई सहयोग नहीं है। नतीजा यह होता है कि इर्रीगेशन विभाग कुछ कहता है, कोआपरेटिव विभाग कुछ कहता है, ऐग्रीकल्चर विभाग कुछ कहता है। जबतक ये सब विभाग आपस में मिल कर सहयोग से काम नहीं करेंगे तबतक हमारे देश की खाद्यान्न समस्या हल नहीं हो सकती। कोआपरेटिव की हालत यह है कि मेरे जिले में कोआपरेटिव की तरफ से ९ ट्यूबवेल बनाये गये लेकिन ९ के ९ बेकार पड़े हुये हैं और सरकार ने इस सदन में यह मान भी लिया है। तब यह देखना चाहिये कि इन ९ ट्यूबवेलों पर जो रुपया खर्च किया गया वह बरबाद क्यों हो रहा है और उनको चलाने के लिये कोई न कोई रास्ता सरकार को निकालना चाहिये।

जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, किसानों के गिरते हुये स्वास्थ्य की तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये। जिन किसानों की मेहनत के ऊपर हमारे देश की तरक्की और अर्थ-स्थिति निर्भर करती है उन किसानों के स्वास्थ्य की सरकार को ज्यादा फिक्र होनी चाहिये। आज हालत यह है कि ऐसे भी अस्पताल हैं जहां न डाक्टर हैं, न कम्पाउन्डर हैं, न दवाइयां हैं, केवल बिल्डिंग बनी हुई हैं। तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये कि वहां डाक्टर हों, कम्पाउन्डर हों और दवाइयां भी आसानी से मिल सकें।

[श्री सजीवनलाल]

पंचायतों के विषय में मुझे यह कहना है कि पंचायत के सेक्रेटरी, ग्राम सेवक या जो और सरकारी कर्मचारी उनमें काम करते हैं वे गांव के लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाते। बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पिछले वर्ष लालटेनें लगवायी गयी थीं, लेकिन उनमें किसी में शीशा नहीं है, किसी में कल्ला नहीं है, केवल ढांचा ही ढांचा है। क्या यही विकास है कि जो लालटेनें लगवायी जांय उनमें तेल न हो, शीशे भी गायब हों और किसान उनमें अब अपने बैल बांध रहे हैं। अगर आत्मनिर्भरता की तरफ सरकार का प्रयास है तो यह जरूरी है कि उस किसान की तरक्की की जाय जो आज ७५ और ८० फी सदी गांवों में रहते हैं।

आज हालत यह है कि हमारी योजना के साथ साथ गरीबी भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये कागज और फाइलें भले ही चलती रहें, लेकिन जो मुख्यतया गांव की विकास योजना होनी चाहिये अगर उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया तो यह अरबों रुपया बरबाद होता रहेगा फिर भी गांव की तरक्की नहीं हो पायेगी। इसलिये यह जरूरी है कि योजना और शिक्षा, इन दोनों की तरफ ध्यान दिया जाय कि जिस योजना के आधार पर हमारा रुपया खर्च हो रहा है वह जनता के लिये खर्च हो रहा है या नहीं और ऐसी शिक्षा भी दी जाय जिससे हमारे युवक योजनाओं के आधार पर प्रदेश और देश को आगे ले चल सकें।

ब्लाकों के अन्दर साढ़े १२-१२ लाख रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन उस रुपये का अगर अनुपात लगाया जाय तो जितना रुपया खर्च किया जाता है उस हिसाब से हमारे प्रदेश की तरक्की नहीं हो रही है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि जो कर्मचारी हैं वे कहां से आते हैं? क्या वे जनता के अन्दर खप पाते हैं? अगर ऐसे अधिकारी हों जो जनता के अन्दर अपने को न खपा पायें तो वे जनता के लिये या गांव की तरक्की के लिये ज्यादा फायदेमन्द नहीं होंगे।

मुझे दो, तीन बातें और कहनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अब समय नहीं है, आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती कैलाशवती (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रगट करने का अवसर दिया है। मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आई हूं और मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वहां के लोग बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगते हैं, वे तो छोटे छोटे उद्योग मांगते हैं जिससे उनकी बेकारी दूर हो जाय। हमारी ग्रामीण बहिनें जो गांवों में बेकार पड़ी हुई हैं, उनके पास न कोई काम है और न कोई धंधा ही है। उनके लिये कुछ न कुछ इंतजाम किया जाय। हमारा क्षेत्र बाढ़ एरिया में पड़ता है। आज हमारी सरकार कृषि उत्पादन की तरफ बहुत तेजी से जा रही है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जहां यातायात के साधन नहीं हैं, पानी नहीं है, लोग बेकार हैं, ऐसी जगह तभी उत्पादन बढ़ सकता है जब वहां पर यातायात के साधन, सिंचाई के साधन और लोगों को काम देने का इन्तजाम किया जाय।

कछार एरिया में बाढ़ के खत्म होने पर स्त्री, पुरुष और बच्चे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं और उसको अपनी जीविका चलाने के लिये कोई काम नहीं मिलता। उनको न तो मजदूरी मिलती है और न वहां कोई उद्योग धंधा ही है। इसलिये ऐसी दशा में उनके लिये वहां पर कोई ठोस उद्योग-धंधा कायम होना चाहिये। हमारे क्षेत्र से लेकर गनेश जी के क्षेत्र तक हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। हमारी समझ में नहीं आया कि देखने वाले और जांच करने वालों ने इसको बेकार क्यों छोड़ रखा है यदि वहां पानी की व्यवस्था कर दी जाय तो लाखों मन अन्न पैदा हो सकता है। आज बाग वगैरह खत्म करके तो खेती हो रही है लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। हमारी सरकार की काम करने की प्रवृत्ति रही है और आगे भी रहेगी।

गांवों की काफी पटाई हुई है, लेकिन कहीं-कहीं छोड़ दिये गये हैं जिससे एक गांव से दूसरे गांव में जाने के साधन नहीं रह जाते हैं। छोटे छोटे नाले और पुलिया हैं और हमारे भाई उग्रसेन जी का गांव हमारे क्षेत्र में पड़ता है, वहां एक सड़क बनी है उससे उनका गांव कट गया है। बाढ़ की वजह से हम वहां नहीं जा सकते हैं। इसलिये ऐसे मार्गों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। गांवों के स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिये स्थान नहीं है। गिरी हालत में उनके मकान हैं। यह कहने का मतलब नहीं है कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अगर सरकार के पास सुझाव ही न आयें तो सरकार उन पर क्या विचार करेगी ?

एक बात यह है कि गांव में एक स्कूल चलता था, उसमें गांव के बच्चे, हरिजन बच्चे सब पढ़ते थे, गांव की स्त्रियां काम सीखती थीं। यकायक वह स्कूल टूट जाने की वजह से गांव में हाहाकार मच गया है। मैं, मान्यवर, आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान फिर दिलाना चाहूंगी कि गांव के अन्दर कोई ऐसी चीज लायी जाय जिससे स्त्रियों की बेकारी दूर हो जाय। गांव की स्त्रियां और बच्चे खेत में काम करते हैं. लेकिन खेत में जब काम करने को हो तब तो। बाढ़ में सारे खेत ४–६ महीने तक डूबे रहते हैं और ४–६ महीने तक वह बेकार रहते हैं। इसलिये उनके पास कोई काम होना चाहिये ताकि वह बेकार न रहें और अपनी रोटी का जरिया निकाल लें। इसलिये वहां कोई ऐसा उद्योग कायम करना चाहिये जिससे उनको काम मिल सके।

दूसरी बात हमें यह कहनी है कि जहां पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, गांवों में झगड़ा हो जाता है, ट्यूबवेल का पानी एक खेत से दूसरे खेत में ले जाना होता है। कहते हैं कि यह तो हमारा खेत है, हम इससे पानी नहीं ले जाने देंगे, वहां पर झगड़ा हो जाता है। कहीं-कहीं पर लोग मिल जुल कर चलते हैं। वहां पर नाली नहीं है। थोड़ी दूर बना कर नाली बन्द कर दी। कहते हैं कि जब सरकार ने नाली नहीं बनायी है तो हम नयी नाली खेत में क्यों बनाने दें ? उस तरफ भी मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये कि गांव के लोगों को आसानी से पानी मिल जाया करे, आपस में लड़ाई-झगड़ा न हो। गांव में मौके पर पानी नहीं मिलता। जब पानी की आवश्यकता होती है तब पानी नहीं मिलता और जब आवश्यकता नहीं होती है तो पानी मिलता है। अगर उनको पानी की सुविधा हो जाय तो बीच में एक फसल काट सकते हैं, जैसे मक्का की फसल है। मक्का थोड़े दिनों में हो जाती है। अगर उनको पानी की थोड़ी-सी सुविधा कर दी जाय तो वह बीच से एक फसल काट सकते हैं।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जहां-जहां गांव के अन्दर पानी की कमी है वहां पर पानी की कमी दूर करना चाहिये। जहां स्कूल नहीं हैं वहां स्कूल का प्रबन्ध होना चाहिये और गांव की स्त्रियों के ऊपर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर मैं अपने विचार प्रगट करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, दो योजनाएं समाप्त हो गयीं। योजनाओं की मियाद पूरी हुई, लक्ष्य पूरे नहीं हुए, यह सरकारी रिपोर्ट से ही साबित हो रहा है। माननीय गेंदासिंह ने जो तथ्य रखे उनसे भी यह साबित होता है कि योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। जब लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और देहात की फी कस आमदनी घटी है तो यह देखना होगा कि हमारे कार्यक्रम में कौन-सी कमी है।

जो योजना बनती है वह बड़े-बड़े सरकारी अफसरों द्वारा बनायी जाती है। वह केन्द्रीयकरण के आधार पर बनती है। उसमें कोई राय जनता की नहीं ली जाती। जो अनुभवी गांव के लोग हैं, जो अपनी योजना के बारे में सही राय दे सकते हैं, उनकी राय नहीं ली जाती। इसलिये मैं यह महसूस करता हूं कि यह जो अफसरशाही की योजना है इसमें नौकरशाही का बोलबाला रहता है और सही मानी में योजना नहीं बनायी जाती। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, योजना पूरी हो गई। श्रीमन्, प्रधान मंत्री नेहरू जी के भी बयान से यह साबित

[श्री बुद्धीसिंह]

है कि यह जो आमदनी है मुल्क की वह बढ़ी, राष्ट्रीय आय बढ़ी, लेकिन वह आमदनी गई कहां ? उन्होंने यह भी कहा कि जखीरेबाज जो लोग ह, जो आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके हाथ में, उन दस प्रतिशत आदमियों के हाथ में सिमटकर पहुंच रहा है, उसको रोकना होगा। तो प्रान्तीय सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कभी इस बात पर भी ध्यान दिया है कि यह जो हमारी योजना में कमी है वह कहां पर है, उसको देखें जिससे कि उसको पूरा किया जा सके ।

श्रीमन्, मैं कह सकता हूं कि गांवों के अन्दर आज से २५,३० वर्ष पहले कपास की एक बहुत बड़ी पैदावार होती थी। इन आंकड़ों से तो यह साबित होता है कि कपास की पैदावार इन वर्षों में बहुत ज्यादा घटी है । यह इस किताब में दिखलाया गया है । कपास की पैदावार पहले इन गांवों में इतनी होती थी कि उससे बहुत से गांव वाले अपने कपड़े, और रजाई की रुई इत्यादि का काम चला लेते थे और छोटे-छोटे किसानों को उसमें काम मिल जाता था । मैं जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूं । मैं जानता हूं कि पीपल साड़ा, भोजपुर, सहसपुर, बिलारी, सम्भल, स्यौडरा, बेरनी, खनूपुरा, छाबड़ा, धूमनगर, सौंधन, पमासा, किसौली आदि जगहों में पहले कपड़े का और दस्तकारी का बहुत-सा काम हुआ करता था । आज वह सब खत्म हो गया है। यदि योजना बनाने वालों ने कभी उनसे मशविरा किया होता तो जनता उन चीजों को उन्हें बताती जो कि आज खत्म हो गए हैं । यह एक बहुत बड़ी खराबी की बात है । कहा जाता है कि वह रकबा जिसमें कपास होती थी पाकिस्तान में चला गया और यह अनुसन्धान जो हो रहा है कपास के ऊपर जैसे कि अमेरिका की किस्म की कई तरह की कपासें बोयी जा रही हैं, उन पर जितना खर्चा हो रहा है उतना उससे फायदा नहीं हो रहा है । पहले जो हमारे सूबे के छोटे-छोटे किसान थे वह खाने लायक गल्ला पैदा कर लेते थे और बाकी खर्चा अपनी दस्तकारी से निकाल लेते थे, चरखे चला कर या कपड़े वगैरह बना कर गुजर करते थे, आज वह सब चौपट हो गया है, ऐसा मैं महसूस करता हूं और गांवों में देखता हूं ।

पंचायतें स्वावलम्बी नहीं बनीं । मैं निवेदन करूं कि यह जो आपका तारतम्य है योजना का इसमें आपके जो अधिकारी हैं और गांव का जो प्रधान है इनका आपस में एकीकरण होना चाहिये । दोनों को एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिये । यह तारतम्य नहीं मिल सका है । दूसरे तहसील और नये विकास खंड जो खुल रहे हैं इनका तहसीलों और विकास खंडों के कर्मचारियों का एकीकरण नहीं हो पाया है, यह मैं आपको इत्तिला दे रहा हूं और इस चीज को आपको देखना होगा कि एक-एक दरख्वास्त पर बी० डी० ओ० के लिख देने के बाद भी तीस-तीस, चालीस-चालीस रुपया एक गांव के किसान के तकावी लेने में खर्च हो जाते हैं ।

पंडित नेहरू जी यह भी कहते हैं कि खाना, कपड़ा, पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि की सुविधाएं हम बहुत कुछ दे चुके हैं और जो बाकी है वह भी देने जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जो यह दावा किया जाता है कि हम समाजवादी समाज बना कर छोड़ेंगे और वह हम बना रहे हैं तो उसमें जरा यह अनुपात तो देखा जाय कि कितनी सुविधायें आपने छोटे छोटे उद्योग करने वालों को दी हैं और कितनी आपने दस या पन्द्रह फीसदी बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दी हैं ? पं० नेहरू जी को भी यह कहना पड़ा कि आज दस या पन्द्रह फीसदी के हाथ में हमारी ज्यादा से ज्यादा आमदनी इकट्ठा होती जा रही है और ज्यादा लोगों के हाथों में यह नहीं पहुंच रही है । सच्ची लगन से अगर आपको काम करना है और गान्धी जी के मार्ग पर चलना है तो मैं आपके निवेदन करूंगा कि आप अपनी योजना की खराबियों को देखें । सबसे बड़ी खराबी उसमें यह है कि वह एक केन्द्रीकरण के तरीके की, एक केन्द्रित योजना होती है और यह भी मैं जिक्र कर दूं कि यह ब्लाकों में जो काम होता है, अव्वल तो यह ब्लाक जो बनते हैं वह आपकी जो शासक पार्टी है, जो आपकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, इसके लोगों ने अधिकारियों से मिलकर और उन पर जोर डालकर गलत ढंग से विकास खंड बनवाये हैं और स्वार्थ की दृष्टि से बनवाये हैं। (श्रीमती सुचेता कृपलानी से) श्रीमती जी, आप जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी

में रही हैं, हमको आपसे बड़ी आशा थी कि आप उन बातों को देखेंगी जो गलत हुई हैं। देहातों के अन्दर जो विकास खंड बनाये गये हैं वह बहुत गलत तरीके पर बनाये गये हैं। मेरे यहां ४ विकास खंड बनाये गये हैं। मेरी सर्किल में दो गांव एक विकास खंड में पड़ते हैं और ४ विकास खंडों के लिये तमाम हलका गलत तौर से डाल दिया गया है। सन् १९५८ में यह रखा गया। इसके पीछे जो भावना छिपी थी उसके आधार पर ऐसा कर दिया। बनियाखेड़ा में एक विकास खंड उस गांव के नाम से था, लेकिन वह विकास खंड खोला गया चन्दौसी में। वहां के एक रईस हैं उन्होंने कहा कि हम ५ हजार रुपया देंगे। उसके विकास खंड के अस्पताल को उनके गांव में खोल दिया जाय।

मेरा निवेदन यह है कि जो लम्बे हलके हैं और पिछड़े हुये इलाके हैं वह पीछे रह जाते हैं और उनके लिये गौर नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदया इसकी जांच कराने की कृपा करें तब उनको मालूम होगा कि कितनी गड़बड़ होती है। पिछले साल ऐसे लोगों के लिये मैंने बताया था जो अंग्रेजी जमाने में साम्राज्यवादी अधिकार रखते थे और पुलिस से मिलेरहते थे। भूतपूर्व गृह मंत्री माननीय कमलापति जी त्रिपाठी १७-१२-५९ को जब स्यौंहारा में पधारे थे तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी कांग्रेस पार्टी में कुछ डाकू हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो डाकुओं को रखते हैं। ऐसे लोग वहां कुछ बैठे हुये थे। मैंने कहा था कि आपके जाने के बाद वहां पर डकैती होगी। तो फिर धर्मपुरा, खानपुरा और नंगला में डकैती हुई। उसके बारे में मैंने चिट्ठी लिखी, लेकिन आज तक कोई बात नहीं हुई है और न कोई उत्तर मिला। आपको गृह मंत्री से मिलकर इन बातों को देखना चाहिये और हमारी भावनाओं का आदर आपको करना चाहिये। जो हमने सरकार के पास चिट्ठी भेजी है उन पर गौर करना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि और लघु उद्योग-धंधे जो गांव में बहुत दिनों तक पनपे रहे, वे अब लुप्त हो गये हैं। होशियार और अच्छे पेशे वाले लोग अपने काम में बेकार हो गये हैं। श्रीमती जी, आप फौरन ऐसे लोगों की भावना का आदर करें जो गांव में रहते हैं और जिनके रोजगार बुरी तरीके से ठप्प हो गये हैं। आज वह गरीब हो गये हैं और उनकी गुजर नहीं हो रही है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ब्लाक खंड सही तरीके से फिर दोबारा बनाने के लिये एक कमेटी मुकर्रर की जाय। इसी के साथ किसान की जो पैदावार है, उसकी जांच का कोई आधार होना चाहिये ....

श्री उपाध्यक्ष—आपको यह जानना चाहिये कि किसी मंत्री को संबोधित करके आप भाषण नहीं कर सकते।

श्री बुद्धीसिंह—मैं आपके द्वारा ही कहना चाहता हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि ब्लाक-खण्ड आप सही तरीके से खोलें और फिर यह देखें कि किस तरीके से वे बनाये गये हैं। उनमें सही तरीके से गांवों का विभाजन होना चाहिये।

किसान की पैदावार का कोई आधार होना चाहिये। एक कुम्हार भी जब बाजार में अपनी हंडिया को बेचने जाता है तो उसका दाम सही तरीके से जांचा जाता है। किसान अपनी पैदावार का दाम नहीं मांग सकता है लेकिन उसका कुछ औचित्य जरूर होना चाहिये। अभी जब चीनी मिलों के अन्दर चीनी का स्टाक इकट्ठा हो गया तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इतना स्टाक जमां होना शुरू हो गया है। इसके पहले भी उन्होंने अपनी कीमत की बाबत हल्ला मचाया था। इसी तरीके से किसान की पैदावार की कीमत का सही नाप होना चाहिये। इस पर आज तक १४ वर्ष हो गये, सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया कि किसान की पैदावार की कीमत जांचने का क्या आधार होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं; कि सरकार इस बात पर विचार करे।

[श्री बुद्धीसिंह]

ग्राम सभा और ग्राम समाज का एकीकरण होना चाहिये, क्योंकि इनमें आपस में कोई सामञ्जस्य नहीं है। पैदावार की जांच के बारे में गलत आंकड़े मिलते हैं, यह बहुत गलत बात है। मैं निवेदन करूंगा कि अव्वल, दोयम और सोयम तीन तरह के खेत होते हैं और उनकी मिट्टी भी तीन तरह की होती है। एक कांग्रेसी सदस्य ने बतलाया कि एक बीघा में ३० मन धान पैदा हुआ। वे बूढ़े आदमी हैं और ८० वर्ष का अनुभव है। इन लोगों से मंत्री जी को मिलना चाहिये कि यह कैसे पैदा हुआ। पैदावार की जांच का तरीका दो-दो डेसिमल रकबा काटकर अपनाया जाय। हर किस्म की जमीन में दो दो डेसिमल काट कर निकाला जाय। वह अफसर जा कर किसी खेत से दो चार बालें काट लेते हैं और आप के पास आंकड़े भेज देते हैं, मेरा निवेदन है कि इस किस्म की जांच में सुधार होना चाहिये।

मैं एक निवेदन और करूं कि आपके स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक हर इलाके में मौजूद हैं। मुझसे उन्होंने बार-बार कहा है कि यह जो राजनीतिक पीड़ित के नाम पर लूट सरकार करा रही है यह क्यों? आज भी इसके बारे में सदन में एक प्रश्न था कि सूची जिलेवार दिखायी जाय। लोहा, सीमेंट और कोयले का परमिट कौन-कौन लिये हैं। हमारी भी एक पेंशन थी, एम०एल० ए० बनने के बाद वह खत्म हो गयी, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कोयले के परमिट लिये हैं और अपने को पोलिटिकल सफरर कह कर के लिखा रखा है उन के लिये कोई कानून कायदा है या नहीं? इस के लिये मेरी मांग है कि हर जिले में जांच होनी चाहिये। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों से आपको मिलना चाहिये। वे हर स्थान पर आपका काम सार्वजनिक रूप से, अवैतनिक रूप से करने के लिये तैयार हैं। लेकिन आप तो लोगों से मिलने महलों म जाते हैं, उनके यहां जाते हैं जो सन् ४२ में हम को जूते मरवाते थे, पिटवाते थे।

श्रीमन्,

सन् बयालीस में जो रहे अंग्रेज हुकूमत के गुलाम,
सन् बयालीस में जिन्हें मिला अंग्रेज हुकूमत से इनाम।
जो कभी जिन्दगी में अपनी आ सके देश के काम नहीं,
जो कभी जिन्दगी में अपनी ले सके राष्ट्र का नाम नहीं।
यूं गधी के भी लिये हाय जिन के दरवाजे बन्द रहे,
जो जीवन भर बने हुये भारत के जयचन्द रहे।
उन जयचन्दों को ढूंढ़-ढूंढ़ खद्दर पहनाये जाते हैं,
अब जिम्मेदारी के पद पर गद्दार बिठाये जाते हैं।
हम समझ न पाये थे पहले अपने स्वराज्य की परिभाषा,
हम को न ज्ञात हो सकी यह नेताओं की अभिलाषा।
बापू होते तो क्या कहते इसका तुमने कुछ किया ध्यान,
बापू के यह मजदूर प्राण बापू के यह जीवन किसान।
था बापू का परिवार यही जिस पर तुमने अन्याय किया,
तुमसे तो यह उम्मीद न थी तुम ने क्या से क्या हाय किया।
हम कह सकते कुछ नहीं किन्तु रह जाते हैं मन ही मन बस,
अब रोज मनाये जाते हैं श्रीमान्, आप के जन्म दिवस।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, नियोजन ऐसे महत्वपूर्ण विभाग पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, मुझे इस बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि इस विभाग ने गांवों का कायाकल्प करना शुरू कर दिया है। भले ही एक तरफ के भाई हठ-पूर्वक इस बात को न मानें, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं तर्क से यह बात साबित करूंगा कि किस तरह से गांवों में कार्य की ज्योति पहुंची है, और यह विभाग अपना कार्य कर रहा है।

श्रीमन्, विभाग जिन के मातहत हैं उनके विषय में भी मुझे एक लफ्ज कह देना है। हिन्दुस्तान की परंपरा के अनुसार महिलायें नियोजन का कार्य स्वयं ही अच्छी तरह से जानती हैं और उनके सुपुर्द अगर यह नियोजन विभाग किया गया है तो यह भी परंपरागत एक अच्छी विचारधारा है। जिस प्रकार हम घर में अपना नियोजन करते हैं उसी प्रकार समाज में भी यदि हम नियोजन करें तो वह 'सोने में सुहागा' वाली कहावत चरितार्थ करेगा।

श्रीमन्, मुझे कुछ सदस्यों के भाषण सुनकर एक पुरानी उक्ति याद आ गयी। मेरठ कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उसमें मैं शामिल हुआ था। उस समय राजे और महाराजाओं से संबंधित प्रोवीपर्स का एक प्रश्न कांग्रेस की मीटिंग में प्रस्तुत था और उस संबंध में बड़े-बड़े बोलने वालों ने आलोचनायें और प्रत्यालोचनायें कीं। वह समय था जब सरदार पटेल उस सेशन में मौजूद थे और सरदार साहब जब जवाब देने खड़े हुये तो उनकी एक उक्ति मुझे इस समय याद आ रही है। उन्होंने कहा कि "जिनको चूल्हे में लकड़ी देने की तमीज नहीं, जिनको चूल्हे में लकड़ी लगाकर खाना पकाने की अकल नहीं वे आज हमको यह शिक्षा देते हैं कि हम क्रांति करना नहीं जानते, हम नियोजन करना नहीं जानते, हम देश को बनाना नहीं जानते।" और इस के बाद जो उन्होंने मिसाल दी वह भले ही कड़वी हो, लेकिन बड़ी ही सत्य मिसाल थी। उन्होंने कहा कि "एक बैलगाड़ी के नीचे एक कुतिया चल रही थी और जहां पर बैलगाड़ी खड़ी हुई तो उस कुतिया को यह अनुभव हुआ कि हम ही इस बैलगाड़ी को खींच कर यहां तक ले आये हैं।" कुछ सदस्यों को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे क्या कह रहे हैं। भले ही वह बेलजियम हो आये हों, विदेश हो आये हों, लेकिन शायद उन्हें अपने देश का, अपने क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं है। वे दारुल शफा छोड़ कर शायद कहीं जाना नहीं चाहते, जानते भी नहीं, नहीं तो इस तरह की निराधार बात कह कर सदन का समय नष्ट न करते।

श्रीमन्, कहा जाता है कि नियोजन का विकेन्द्रीकरण नहीं किया जा रहा है। श्रीमन्, मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण तो इस हद तक कर दिया गया है कि मुझे डर लगने लगा है कि कहीं यह असफलता को न प्राप्त हो जाय।

मैं बहुत नम्रतापूर्वक अपने सरकारी कर्मचारियों के प्रति भी एक शब्द कह देना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारियों की आलोचना जब इस सदन में होती है तो ऐसी योजना प्रस्तुत करते हैं मंत्रिमंडल के सामने कि जिसके आधार पर सारा बजट गांव सभाओं में केंद्रित हो गया है और उसे पूर्ण रूपेण अपनी जगह स्वतंत्र कर दिया है। उनको उसके लिये पूरा अधिकार दे दिया है कि वे अपने बजट को जिस तरह चाहें खर्च करें। यह जनसंख्या के हिसाब से बजट का बंटवारा है। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी गांव सभायें इस काबिल नहीं हैं कि वे अपने बजट के अनुसार अपने यहां नियोजन कर सकें। अगर सरकारी कर्मचारियों ने उसमें सहयोग नहीं दिया तो योजना सफल नहीं होगी, इसलिये उनको उसको देखना चाहिये। हमने बजट उनको देकर पूरी शक्ति उनके हाथ में दे दी है। उन्होंने इस तरह से मंत्रिमंडल के सामने इस योजना को रख दिया जिसके आधार पर पूरा विकेन्द्रीकरण कर दिया। मुझे भय है कि इसकी असफलता से नौकरशाही, या जो कुछ भी आप कहें, कहीं लागू न हो जाय।

आज श्रीमन्, एक भावना नियोजन के अन्दर काम कर रही है। हमने आज अपना केवल स्पीच देना ही एक कर्तव्य बना रखा है और हम यहां पर आकर यह कहते हैं कि सरकार को यह करना चाहिये, वह करना चाहिये, सरकार यह नहीं कर रही है, इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ग्रामों में नियोजन के प्रति कोई उत्साह नहीं है। ग्रामों में उत्साह लाने का काम हमारा ही नहीं है, हम और आप, सभी का है। इसके लिये हमारा आपका मिला-जुला प्रयास हो सकता है। लेकिन हम और आप तो ग्रामों की समस्याओं को देखते तक नहीं। तो हम उन्हें नियोजन के प्रति उत्साहित न करें, हम उनकी कोई सहायता न करें, और फिर हम यह कहें कि उनमें उत्साह नहीं है, ग्रामों की योजना सफल नहीं हो रही है,

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

तो यह गलत बात होगी और इस तरह से मैं समझता हूं कि हम अपने कर्त्तव्यों का पूर्णरूपेण पालन नहीं करते हैं ।

एक भाई ने सामाजिक एजूकेशन के विषय में भी कहा । श्रीमन्, मैं भी समझता हूं कि अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि ब्लाकों के अन्दर सामाजिक शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान होना चाहिये । उसका होना बहुत आवश्यक है । मैं यह बात क्यों कहता हूं ? यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि आज हमारी कुछ पुरानी मान्यतायें हैं, पुरानी परम्परायें हैं जो आज हमारे कार्य में रुकावट पैदा कर रही हैं । यह चाहे सौभाग्य हो या दुर्भाग्य हो, जब भी हम कोई नयी पद्धति को लेकर ग्रामों में जाते हैं, उनको वहां लागू करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो अपनी पुरानी मान्यताओं एवं परम्पराओं को परिवर्तित करना नहीं चाहते । गांव वाले उनको बदलना नहीं चाहते । यदि हम यहां पर सामाजिक शिक्षा का प्रचार करें, वहां पर सामाजिक शिक्षा काफी तादाद में लोगों को दें, तो हम अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं, जो उनके दिमागों में पुरानी मान्यतायें भरी हुई हैं उनको काफी हद तक निकाल सकते हैं और अपनी योजनाओं को सफल बना सकते हैं ।

आज जब हमारे कर्मचारी गांव में जाते हैं और किसानों से कहते हैं कि भाई तुम १५ सेर के स्थान पर ६ सेर अनाज एक बीघे में बोओ, तो वह उस पर विश्वास नहीं करता, उसको नहीं मानता, वह किसी भी तरह ६ सेर अनाज को बोने के लिये तैयार नहीं होता । अगर ६ सेर गेहूं बोया जाय १५ सेर की जगह तो ६ सेर में भी उतनी ही उपज हो सकती है जितनी कि १५ सेर बोने से, मगर वह उसको मानने के तैयार नहीं होता । वह कहता है कि किसनई तो हम लोग जानते हैं, तुम लोग कोट-पेन्ट पहनने वाले इसको क्या समझो, हम तो इसके पंडित हैं । तो आप देखें कि सामाजिक शिक्षा की किस कदर आवश्यकता है । अगर सामाजिक शिक्षा बढ़ायी जाय तो ५०–६० वर्ष के लोगों को शिक्षित करने से हमारी हर क्षेत्र में कामयाबी हो सकती है । इसलिये मैं अतीकुल रहमान साहब का समर्थन करता हूं कि सामाजिक शिक्षा को प्रधानता मिलनी चाहिये ।

हमारे जन संघ के साथी ने कुछ पुरानी संस्कृति के आधार पर बातें कहीं और कहां लड़का हुआ है, इस तरह की बातें कहीं । इसी तरह से महिलाओं और पुरुषों के साथ काम करने के प्रश्न पर उनकी अपनी राय है । मैं पूछना चाहता हूं कि यदि महिलाएं और पुरुष एक साथ काम न करें, यह उनकी राय है तो चुनाव के विषय में क्या राय है, एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, उस पर उन्होंने कोई रायजनी नहीं की है । मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में क्या महिलाओं को घर की कठपुतली बनाकर रखा जाता था ?

भारतीय नारी की एक परम्परा रही है कि वह तलवार लेकर पुरुषों के लड़ाई के मैदान में छक्के छुड़ा दिया करती थी । झांसी की रानी की कहानी सर्व विदित है । सीता, सावित्री के उदाहरण खूब प्रचलित हैं । इस तरह की नारियां हमारे देश और प्रदेश में जन्म लेती रही हैं । तो क्या आप इन नारियों को गुड़िया बना कर घरों के अन्दर रखना चाहते हैं और अपने मनुष्य के स्वभाव में जो एक पाप छिपा हुआ है उस वृत्ति से नारियों पर आज से ५० वर्ष पहले जैसे शासन करना चाहते हैं ? क्या उनको विषय-वासना की तृप्ति की मशीन बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं ? भारतीय संस्कृति को हमने भी समझा है, हम भी उसके पुजारी रहे हैं । भारतीय संस्कृति का दायरा बड़ा चौड़ा रहा है । वह कहीं ताले में बन्द नहीं हुई । भारतीय संस्कृति की यही तो सब से बड़ी विशेषता है कि हजारों ठोकरें खाने पर आज भी कायम है । वह विशेषता यह है कि वह हर अच्छी चीज ग्रहण करना जानती है और हर निकम्मी चीज को निकाल देना चाहती है । अगर इस आधुनिक युग में नारी को घर में बन्द कर के रख दिया गया तो समाज में इतनी गन्दगी और बदबू फैलेगी कि नाक सड़ जायगी और देश का भला नहीं होगा ।

श्रीमन्, अब मैं यह कह देना चाहता हूं कि प्रायमरी हेल्थ यूनिट प्रदेश के ब्लाकों में खोले जा रहे हैं। मैं बहुत नम्रता-पूर्वक मंत्राणी जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सिधौली में ब्लाक खुले बहुत वर्ष हो गये और यह मुझे मालूम है कि जो ब्लाक बाद में खुले हैं उनमें प्राइमरी हेल्थ यूनिट कायम हो गये। इसमें क्यों नहीं हुआ? मुमकिन है कि कोई वैधानिक आपत्ति हो, कृपया उसको देख लिया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं जिस पर मैंने अपना कटमोशन दिया था और मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जहां सब सरकारी कर्मचारियों को न निकम्मा समझता हूं, न बेईमान और न सबको मैं अच्छा समझता हूं, न नेक, तो इसी वसूल के तहत में मैंने बी० डी० ओ० रामपुर, मथुरा, के विरुद्ध डेढ़ वर्ष से खत लिखने शुरू किये और सब से पहले २४-१०-५९ को मुख्य मंत्री जी की सेवा में पत्र लिखा। उसके बाद से क्या कार्यवाही हुई, मैं नहीं कह सकता। मैंने उनके काम और कार्यवाहियां नोट की हैं और अधिकारियों को अवगत कराया है। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं और मुझे बताया जरूर जाय कि जब हम स्पेसिफिक एग्जाम्पिल देते हैं तब क्यों सरकारी कर्मचारी से प्यार और मुहब्बत की जाती है? एक आध पर अगर एक्शन लीजये तो आपकी धाक जमेगी और शासन के प्रति जनता में संतोष पैदा होगा।

अन्त में मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, यह जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है गेंदासिंह जी के द्वारा, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता तो नहीं था कि इस वाद-विवाद में हिस्सा लूं, लेकिन चूंकि ऐसी बातें हुई और सुचेता कृपालानी जी ने इस अनुदान को पेश किया, इसलिये मेरी इच्छा हुई कि इस विवाद में हिस्सा जरूर लिया जाय।

मैं यह प्रथम वाक्य कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो पंचवर्षीय योजनायें यहां कार्यान्वित हो रही हैं उनमें दो बातों का सम्मिश्रण है। एक ओर तो गांधी जी की पाखंडपूर्ण स्तुति है और दूसरी ओर पाश्चात्य सभ्यता की नकल है, पश्चिम की उत्पादन प्रणाली की नकल है। तो जो योजना गांधी जी की पाखंडपूर्ण स्तुति लेकर चलेगी और जो योजना पश्चिमी उत्पादन प्रणाली पर नियोजित होगी, निश्चित रूप से वह भारत की योजना नहीं हो सकती।

श्रीमन्, मैं ऐसी योजना का विरोधी हूं। पहले मैं उन कारणों को बता देना चाहता हूं कि जो योजनायें कांग्रेस सरकार की तरफ से चल रही हैं उसका विरोधी क्यों हूं। पहली बात तो यह है कि यह योजना ग़रीब लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कर लगा कर उनके रक्त को चूस रही है और दूसरी ओर पूंजीपतियों को पूंजी संचय के नाम पर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की छूट दे रही है।

दूसरा कारण यह है कि बेकारी को दूर करने के लिये आय में वर्तमान विषमता को मिटाने का प्रयत्न इस कांग्रेसी सरकार द्वारा संचालित योजना में नहीं हो रहा है। ये योजनायें जमीन जोतने वाले किसानों के हक की हिफाजत मौखिक रूप से कर रही हैं, व्यावहारिक रूप से नहीं। ये योजनायें कम कीमत के मकानों को बनाने की जरूरत पर ध्यान नहीं दे रही हैं जब कि कीमती और आलीशान मकानों के बनाने में धन का अपव्यय किया जा रहा है। ये योजनायें विदेशी शिक्षा और विशुद्ध विज्ञान की शिक्षा पर अधिक खर्च कर रही हैं जब कि चाहिये प्रारम्भिक, साधारण और टेक्निकल शिक्षा पर ध्यान देना। ये योजनायें शहरों को गांवों की कीमत पर बढ़ने का मौका दे रही हैं जब कि पिछड़े हुये क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये योजनायें एक भ्रष्ट नौकरशाही पर भरोसा कर चलाई जा रही हैं जब कि जनता पर अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। ये योजनायें बड़े-बड़े उद्योगों को लेकर चलती हैं जिससे धन और सत्ता का कन्द्रीयकरण कुछ बड़ पूंजीपतियों और ठेकदारों के हाथों में होता जा रहा है जब कि उनके

[श्री राजनारायण]

छोटे-छोटे प्रतिद्वन्दी होड़ में पिसते और मिटते चले जा रहे हैं। ये हमारे कारण हैं जिनसे हम सुचेता जी द्वारा प्रस्तुत नियोजन की योजना के विरोधी हैं।

अब हम चाहते क्या हैं, वह भी सुना दूं। हम चाहते हैं कि प्रमुख उद्योग-धंधों, कम्पनियों, खानों, विदशी, आंतरिक और थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो, जमीन का बटवारा हो। बड़ी और छोटी जोत का अनुपात एक और तीन का हो। बेदखली तथा इस्तीफे पर पूर्णतः रोक लगाई जाय। श्रीमती सुचेता जो अभी नई आई हैं इसलिये उन को शायद इस्तीफे के बारे में जानकारी न हो और बेदखली के बारे में भी शायद जानकारी न हो जब कि सरकार कहती है कि बेदखली कहां हो रही है, हम ने तो सीरदार बना दिया। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सारे आंकड़े देखे जायं तो आज आधे से ज्यादा सीरदार बेदखल हो गये हैं। आज भी जबर्दस्ती इस्तीफे दिलाये जा रहे हैं। मैंने नम्रतापूर्वक कई गांवों के आंकड़े माल मन्त्री जी के की सेवा में भेज दिये हैं स्वतः। तो श्रीमती सुचेता जी को बताना चाहता हूं कि इस्तीफे का मतलब यह है कि जबर्दस्ती अंगूठे का निशान लगवा कर उन सीरदारों का, जो कि जमीन पर काबिज हैं इस्तीफा पुराने जमींदार या दूसरे बाअसर लोग ले रहे हैं। इस पर पूर्णतया रोक लगाई जानी चाहिये।

हम चाहते हैं कि आय में समानता हो और आमदनी और खर्च को इस ढंग से नियोजित किया जाय कि बड़े और छोटे की आमदनी और खर्च में दस और एक का अनुपात हो और विकास और नियोजन में जो उत्पादन के छोटे-छोटे यंत्र हैं उन को जहां तक सम्भव हो वहां तक लगाया जाय। और बड़े उद्योग जहां नितान्त आवश्यक हो वहां लगाये जायं। इन दोनों दृष्टिकोणों को समझ लेना चाहिये और मैं समझता हूं श्रीमती सुचेता जी समझती भी होंगी। हमारा प्रयत्न होना चाहिए, अगर हम भारतीय योजना बना रहे हैं, कि छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को अधिक विकसित करें, जितने संभव हो सकें लगावें और जहां नितांत आवश्यकता हो, जिसके बिना काम का चलना दूभर हो जाय, मुश्किल हो जाय वहीं बड़े उद्योग-धंधे लगाये जायं।

चौथी बात है कि सब को काम मिले और जिन्हें काम न मिले उन्हें सरकार बेकारी का भत्ता दे। जब तक यह योजना नहीं बनती तब तक जितनी भी योजनायें बनेंगी वह थोथी होंगी, काल्पनिक होंगी और स्वप्नवत् होंगी। सभी स्तर पर जनता से सम्पर्क और प्रबंध तथा प्रशासन का पूर्ण विकेन्द्रीकरण हो, जिसका आधार चौखम्भा राज्य हो। चौखम्भा राज्य के बारे में श्रीमती सुचेता कृपालानी जो को जानकारी होनी चाहिए। चौखम्भा राज्य मूर्तिमान स्वरूप है जो गांधी जी का स्वप्न था, लेनिन का स्वप्न था और मार्क्स का स्वप्न था।

गांधी जी ने कहा कि एक गरीब किसान का बेटा प्रधान मन्त्री हो। हम कहते हैं, अगर वह प्रधान मन्त्री नहीं बन पा रहा है इस कांग्रेस शासन में तो कम से कम गांव का सभापति तो हो जाय। तो गांव पंचायत राज, जिला पंचायत राज, सूबा पंचायत राज और केन्द्र पंचायत राज हो और सारे अर्थ का नियोजन हो, एक बटे चार का सब में बटवारा हो और उनको प्रशासन में पूरा,पूरा हिस्सा दिया जाय।

हमने मार्क्स और लेनिन का नाम भी लिया है। लेनिन ने कहा है कि "एवरी कुक मस्ट लर्न हाउ टु रूल दि स्टेट"। प्रत्येक गृहणी को यह योग्यता होनी चाहिये कि राज्य शासन किस प्रकार से चलाया जा सकता है। मार्क्स ने कहा है कि "स्टेट विल विदर अवे"। यानी जब हमारा स्वप्न पूरा होगा तो राज्य शासन पतझड़ की तरह मुरझा कर गिर जाएगा। इन सभी को हमने मूर्तिमान स्वरूप प्रदान कर दिया है चौखम्भा राज्य में और अगर यह चौखम्भा राज्य बना दिया जाय तो आज के युग के जितने मनीषी हुए हैं, जितने दार्शनिक हुए हैं, उन सब का स्वप्न साकार हो जाएगा।

गांवों और शहरों के छोटे उत्पादकों के ऋण की माफी और आगे कर्ज का सरकार की तरफ से इंतजाम हो। आज ऋण से लोग लदे हुए हैं और बारबार इस प्रकार से कहा गया है

कि ये छोटे-छोटे जो उत्पादक हैं, जो गरीब किसान हैं इनके ऋण को माफ करें और आगे कर्जे का इंतजाम करे।

श्रीमती कृपालानी जी कहती हैं कि हमारा कोआपरेटिव । जरा अपने कोआपरेटिव में हाथ तो डालें। बिच्छू का मन्त्र न जाने और सांप के बिल में हाथ घुसेड़े। यह उत्तर प्रदेश है। यहां अब भी साढ़े १० प्रतिशत सूद लिया जाता है कोआपरेटिव के जरिये जबकि दूसरी स्टेट्स में कहीं साढ़े ४, कहीं ५, कहीं ६ और कहीं ८ प्रतिशत है। यहां साढ़े १० से कम नहीं लिया जाता और १२ तक लिया जाता है। जितनी भी सरकारी समितियां बनी हैं उन सभी ने यह सिफारिश की है कि किसानों को कर्ज देने की ऐसी व्यवस्था की जाय कि लम्बे अर्से के लिये ४॥ प्रतिशत और छोटे अर्से के लिये साढ़े ६ प्रतिशत सूद हो। सन् १९५२ से लेकर आज तक जनतांत्रिक पद्धति से सरकार बन रही है और हम इस विषय पर बार-बार जोर दे रहे हैं और बार-बार सदन में आश्वासन दिया जाता है लेकिन सक्रिय कदम नहीं उठाया जाता है।

औद्योगिक और कृषि पैदावार की कीमतों में न्यायपूर्ण संतुलन हो। मैं सुचेता जी से कहता हूं कि जब हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कीमतों में संतुलन हो तो उनके पास क्या तर्क है कि ऐसा न हो। सिर्फ एक उत्तर है अशोक मेहता का कि कैपिटल फार्मेशन कैसे होगा। (पूंजी कैसे बनेगी) ? इसका उत्तर सुचेता जी दे दें। यदि यह समाजवादी व्यवस्था के प्रति सचेष्ट हैं तो इनका उत्तर आना चाहिये कि कैपिटल फार्मेशन कैसे होगा। पूंजीवादी व्यवस्था में निश्चित रूप में पूंजीपति को छूट रहती है, कि वह कीमत बढ़ा कर, अनावश्यक मुनाफा कमा कर, उपभोक्ताओं के ऊपर भार बढ़ाकर पूंजी बढ़ाएं मगर यह समाजवादी व्यवस्था का नियोजन नहीं होगा। समाजवादी व्यवस्था का जो नियोजन होगा उसमें सर्वांगीण विकास होगा, चतुर्दिक विकास होगा और यह होगा कि जो जितना ही पिछड़ा क्षेत्र हो, जितना ही पिछड़ा समुदाय हो उसकी तरक्की में उतना ही अधिक धन खर्च हो और उसकी तरक्की के लिये उतना ही अधिक दत्तचित्त होकर नियोजन किया जाय। क्या यह नियोजन यह करता है ?

इसके साथ-साथ बड़े-बड़े महलों का निर्माण बन्द हो, उनके निर्माण पर रोक लगा दी जाय। आज अपने प्रदेश में देखा जाय तो बड़े-बड़े महल बनाये जा रहे हैं। कहेंगे तो यह कि कृषि विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में खोलने जा रहे हैं लेकिन जरा उनके भवनों और सड़कों को देखें। नाम लिया जायगा भारतीय संस्कृति का, प्राचीन संस्कृति और परम्परा का और अनुकरण करेंगे ब्रिटेन, रूस और अमेरिका का। इसके बारे में तो सुचेता जी को हमसे ज्यादा जानकारी होगी लेकिन कारणवश कह नहीं पातीं। हमें तो उनके ऊपर तरस आता है। क्या उन्हें नहीं मालूम है कि श्री पंडित नेहरू जी जब अमेरिका गये थे तो जिस रेल के डिब्बे में उन्हें बैठाया गया था उसकी कीमत ८ लाख थी। जब हिन्दुस्तान में आये थे तब उन्होंने उसी वक्त हुकुम दिया और स्विट्जरलैंड को उतना रुपया दिया गया था और रेल का डिब्बा उसी तरह का बनवाया गया था क्योंकि जब आइसनहावर आयेंगे तो उन्होंने जवाहरलाल जी को जिस तरह के डिब्बे में बैठाया था जवाहरलाल जी आइसनहावर को उसी तरह के डिब्बे में क्यों न बैठावें। तो हिन्दुस्तान में नकल करना चाहते हैं अमेरिका की जहां प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष की औसत आमदनी १० हजार रुपये हैं और हिन्दुस्तान में ३ सौ रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति । नकल ये करेंगे इंगलैंड की जहां कि औसत आमदनी ५ हजार रुपये प्रति व्यक्ति है ।

अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई नियोजन करना है तो निःशुल्क कामधंधों की शिक्षा और कम आय वालों की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये, दवा की मुफ्त व्यवस्था होनी चाहिये। और अगर यह व्यवस्था इसमें नहीं है तो यह कुनियोजन है, अनियोजन है और इसको हम नियोजन की संज्ञा दे नहीं सकते। माननीया सुचेता जी कृपया आंकड़े देकर बतावें कि कितनी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, कितनी मुफ्त दवादारू का प्रबन्ध किया गया और

[श्री राजनारायण]

कितने दबे, अकिंचनों, हरिजनों, पिछड़ी जातियों, आदिवासियों औरतों, दबे हुये मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने में सरकार कितना धन व्यय करने जा रही है। नाम बड़े दर्शन थोड़े। अगर करना है तो चौतरफा विकास करो वरना विकास का नाम लेकर लोगों को फंसाना व्यर्थ है।

चन्द आंकड़े अपने प्रदेश के रखता हूं। हमारे प्रदेश में ५ लाख परिवार ऐसे हैं जिनके लिये आज यह योजना है। सिर्फ ५ लाख परिवार के लिये यह योजना है जब कि ७ करोड़ जनता के लिये यह सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ है और यहां कह रहे हैं कि यह योजना करते हैं। केवल मौखिक और शाब्दिक जाल में अब प्रदेश के गरीबों को नहीं फंसाया जा सकता श्रीमती कृपलानी जी इसको आप अच्छी तरह से समझें।

इसी तरह से मोटी-मोटी बातें बताऊं। यह जो योजना की पुस्तिका सरकार द्वारा बंटी है श्रीमन्, इसके चौथे पेज को श्रीमती कृपलानी जी खोल लें। "कृषि—इस क्षेत्र में ५६ से ६० के लिये जितने धन की व्यवस्था की गयी थी उसमें ९२ प्रतिशत का उपयोग किया गया।" यह प्रमाण है कि कृषि में पिछड़े हुये प्रदेश की योजना में ४ वर्ष व्यतीत हो गये जितना व्यय उस पर करने की व्यवस्था की गयी थी वह नहीं खर्च हुआ।

आगे सामुदायिक विकास देखिये। "द्वितीय योजना के काल में ४ प्रथम वर्षों में अनुमानित व्यय जो किया गया है वह कुल धनराशि का ८२ प्रतिशत है।" 'आखिर यह योजना क्या है? क्या कोई भूलभुलैया है, क्या किसानों को रोचक शब्दों में फांसकर उनका अत्यधिक शोषण करने की प्रणाली नहीं है? बड़े और मध्य श्रेणी के उद्योगों के अधीन तीन वर्षों में ४४९.१०२ लाख रुपया निर्धारित किया गया था जिसमें १९५.५९० लाख रुपया व्यय हुआ। अब बतायें श्रीमती कृपालानी जी।

श्री उपध्यक्ष—मैं पहले भी एक माननीय सदस्य को रोक चुकी हूं उनको डायरेक्टली संबोधित करने के लिये। आप मेरे द्वारा ही उनको संबोधित करें।

श्री राजनारायण—मैं आप के द्वारा ही सरकार से यह पूछना चाहता हूं, मस्तक पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा, जरा निष्ठा के साथ, जरा भक्ति के साथ वे सोचें कि बेकारों के लिये, मजलूमों के लिये महरूमों के लिये जो यह ४४९.१०२ लाख रुपया रखा गया था उसमें से केवल १९५.५९० लाख ही क्यों खर्च किया गया। करीब साढ़े तीन सौ लाख रुपया खर्च नहीं किया गया। यह योजना है या चों चों का मुरब्बा। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा।

माननीया सुचेता जी लघु कुटीर उद्योगों की बहुत समर्थक हैं। चाहती हैं कि लघु कुटीर उद्योग पनपें और फूलें।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)।

अच्छा हुआ हमारे माननीय अध्यक्ष, सर्वोदय के नेता भी आ गये।

मैं अब बताना चाहता हूं कि सन् ५३ तक तो चरखा संघ चला। उसके बाद खादी तथा ग्रामोद्योग मंडल हुआ। सन् ५८–५९ तक ६ वर्षों में जो रुपया केंद्रीय सरकार द्वारा इसको दिया गया उसका ब्योरा दिया हुआ है। यानी मैं पूछना चाहता हूं कि जो खादी और ग्रामोद्योग का काम चल रहा है क्या वह स्वतः पूर्ण है। जब तक वह स्वतः पूर्ण नहीं होगा, जब तक वह सरकार के ऊपर आश्रित रहेगा, सरकार की कृपा पर आश्रित रहेगा और अगर यह सरकार पूंजीपति सरकार होगी तो वह ग्रामोद्योग को समाप्त करने की ही चेष्टा करेगी।

केन्द्रीय सरकार ने इस मंडल को कितनी छूट दी है? ७८० लाख कीमतों की कमी की पूर्ति में दिया, प्रशिक्षण में ५३ लाख दिया, संस्था को अनुदान २२९ लाख दिया, अनुसंधान के लिये १९५ लाख दिया, प्रशासन के लिये १४२ लाख दिया। इस प्रकार कुल १,७९९ लाख रुपया खादी तथा ग्रामोद्योग मंडल को मिला। १८ करोड़ रुपया उसको बैंकों मिला और

१८ करोड़ अनुदान के रूप में मिला। इस प्रकार से ३६ करोड़ रुपया उसको मिला, तब जाकर ग्रामोद्योग का नाम चला। अगर यह ३६ करोड़ रुपया न मिलता तो लघु कुटीर की क्या शक्ल होती ? आज किसका नाम होता ? इसीलिये मैंने पहले ही कहा था कि गांधी जी की पाखंड-पूर्ण स्तुति से पूर्ण यह है इस सरकार की योजना। नाम तो लिया जायगा खादी मंडल का और दूसरी तरफ से उसका गला काटने का प्रयत्न किया जायगा और प्रयत्न किया जायगा कि पूंजीवादी व्यवस्था खड़ी हो।

अब जरा आगे चलिये। मैं कम से कम इतनी तारीफ तो जरूर करूंगा सुचेता जी की कि एक बिगड़े घर को सजाने की जो कला एक कुशल महिला में होती है वह कला उनमें है।

श्री अध्यक्ष—आप महिला वगैरह कह कर उनको संबोधित न करें।

श्री राजनारायण—मैंने ऐसा कोई असम्मान के लिये नहीं किया।

श्री अध्यक्ष —जी नहीं, आप उसको वापस लीजिये।

श्री राजनारायण—मैं उसको वापस लेता हूं। इस बारे में आपकी आज्ञा शिरोधार्य है क्योंकि मैं महिलाओं का सम्मान बहुत हद तक करता हूं। अगर कोई मंत्री महिला हैं तो मैं उनको पुरुष कैसे बना दूं ?

अब बिजली को ले लीजिये। यह सरकार कहती है कि हम सब को बिजली देंगे। केन्द्रीय सरकार के आंकड़े को मैं प्रस्तुत करूंगा जो इस सरकार से सम्बन्धित हैं उसको देखा जाय। इस सरकार का सम्बन्ध रिहन्द योजना से है। यह योजना १९५२ में बनी, ४५ करोड़ रुपये का खर्चा था। सिंचाई कितनी होगी ? अज्ञात। हमारी आखिरी जानकारी है जो अकाट्य है, क्योंकि जो कृषि प्रदर्शनी हुई थी उसमें जितने आंकड़े आये हैं वे सब विद्यमान हैं। कितने मिलियन एकड़ की सिंचाई होगी ? अज्ञात। आज तक कोई आंकड़े सरकार नहीं दे पायी। बिजली मिलियन वाट में २५० उत्पादन करने की क्षमता है और लागत प्रति किलोवाट में १,८१० रुपया है। मगर देख लिया जाय आज तक रिहन्द की स्कीम से कितने गांवों को बिजली मिल पायी है ? और जो बिड़ला से समझौता किया गया वह किस शर्तनामे के अनुसार समझौता हुआ है ? क्या किसी माने में कहा जा सकता है कि यह योजना गांवों के किसानों के लिये है ? बिल्कुल पूंजीपतियों के लिये है।

(लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, थोड़ा समय और दें।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं २० मिनट आप बोल चुके हैं।

श्री राजनारायण—नलकूपों का पूरे जिलेवार आंकड़ा न दे करके मोटी-मोटी बातें कहना चाहता हूं। ४० जिलों में नलकूप हैं। दूसरी योजना में १,५०० नलकूप बनाने की योजना थी जिसमें से १,०२० बन पाये। ४८० जो दूसरी योजना में बनने चाहिये थे उनको तृतीय योजना में डाल दिया गया। यानी ७५० और ४८०, इस प्रकार १,२३० नलकूप तीसरी योजना में बनेंगे।

एक आंकड़ा जो ग्राम उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको भी रख देना चाहता हूं। वह खाद से सम्बन्धित है। इटली में १ टन खाद १८ एकड़ में पड़ती है। ब्रिटेन में ६४ एकड़ में, जापान में २२ एकड़ में, अमरीका में ७० एकड़ में पड़ती है और भारत में २,६०० एकड़ में पड़ती है। यह खाद का उत्पादन है। हमारे यहां जो अनुसंधान कर्ता हैं विशिष्ट, उन्होंने सुझाव क्या दिया है ? उनकी जानकारी है कि अगर १ एकड़ गेहूं में ठीक तरह से खाद दें तो नाइट्रोजन ४० पाउन्ड, फासफोरस ५० पाउन्ड और पोटास ५० पाउन्ड। लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा है। कहीं आधा, कहीं चौथाई पाउन्ड है।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो योजना सम्बन्धी अनुदान प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसके ऊपर जो १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है, मुझे खेद है कि मैं उसका विरोध कर रहा हूं।

मान्यवर, माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में बहुत बातें कही हैं। मैं उनसे यहां तक तो सहमत हूं कि जो हमारा नियोजन है इसके ऊपर हमारे सारे देश का आर्थिक ढांचा, देश की उन्नति तथा प्रगति आधारित है। यह भी सही है कि जो हम समाजवाद का ढांचा बनाना चाहते हैं उसकी कामयाबी नियोजन पर बहुत कुछ निर्भर है और एक कदम आगे बढ़कर मैं यह भी मानता हूं कि हमारे देश का जनतन्त्र, उसकी कामयाबी भी नियोजन पर ही निर्भर है। लेकिन मैं उनसे इस बात में सहमत नहीं हूं, जैसा कि उन्होंने कहा, कि हमारे दोनों प्लान्स नाकामयाब हुए। मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं, कि यदि हम किसी भी क्षेत्र को देखें, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का हो या दूसरी सर्विसेज का हो, सबमें ही, प्रगति हुई है, इन पिछले १० सालों में कृषि के अन्दर १५ फीसदी, कामर्स ट्रांसपोर्ट में १७ फीसदी से कुछ ज्यादा और कुछ अन्य सर्विसेज में १७.६ फीसदी तरक्की हुई है, राष्ट्रीय आय में भी करीब २२२ करोड़ की वृद्धि हुई।

जहां तक उद्योगीकरण का वास्ता है हमारे प्रदेश में पिछले १० सालों में जो कुछ हुआ है वह हमारी आवश्यकताओं और आबादी के हिसाब से न के बराबर है, क्योंकि उसकी केवल बढ़ोत्तरी .९ परसेंट है, यानी १ फीसदी से भी कम है। लेकिन अगर माननीय गेंदासिंह जी यह कहते कि जितनी आशायें इन दो योजनाओं से थीं उतनी आशायें पूरी नहीं हुई तो मैं उनसे पूरा पूरा इत्तिफाक करता लेकिन उन्होंने जो एक दम से व्हाइट वाश किया कि कुछ भी नहीं हुआ और नाकामयाब हुए तो ऐसी बात नहीं है। यह बात सही है कि दो योजनाओं के अन्दर हमने जितना पैसा खर्च किया मैं भी उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि उस पैसे को खर्च करने के बाद जो परिणाम मिलने चाहिये थे वे परिणाम हमको प्राप्त नहीं हो सके और उसके कुछ कारण भी थे।

एक कारण यह भी था कि हमारे देश ने जनतांत्रिक ढंग से प्रजातांत्रिक शासन के अन्तर्गत इतने व्यापक रूप से नियोजन का कार्य शुरू किया यह सारे विश्व के अन्दर पहला एक्सपेरीमेंट है। दुनिया के किसी देश ने ऐसा नहीं किया। इतनी कोशिश के बाद भी आज हमारे यहां जो पढ़े लिखे आदमी हैं वे मुश्किल से १७ फीसदी हैं जिनमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो केवल अपने हस्ताक्षर करना जानते हैं। फिर अंग्रेज जो मशीनरी हमको छोड़ कर गये, जो शासन का ढांचा दे गये, जो नौकरशाही छोड़ कर गये उसका अनुभव जनतन्त्र से था और न नियोजन से था। किसी तरीके से उनसे काम लिया गया। कुछ हद तक कामयाब हुए और कुछ हद तक नाकामयाब भी हुए।

माननीय, इस महत्वपूर्ण अनुदान को जो हमारे सामने है इसको इस दृष्टिकोण से देखना है। पिछली जो हमारी योजनायें हैं उनकी कामयाबी हमारे सामने है और नाकामयाबी भी हमारे सामने है। मैं यह भी मानता हूं कि हमने अनुभवहीनता के कारण बहुत काफी करोड़ों की तादाद में पैसे का अपव्यय किया, बरबाद किया। वह सब अनुभव हमारे सामने है। जब हम अब तीसरी योजना के अन्दर पदार्पण कर रहे हैं तो मुनासिब यह है कि चाहे इस तरफ के बैठने वाले हों या उस तरफ के बैठने वाले हों वे इस बात पर सोचें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो जो हमारी कमियां थीं, बाधायें थीं जो स्टेज था, जो लीकेज था उसको हम कैसे बन्द करें।

इस सम्बन्ध में दो चार बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह मैं महसूस करता हूं और कहता था कि यह जो नियोजन है यह कोई विभाग नहीं है, यह एक कोआर्डिनेटिंग एजेंसी है जो हमारे

भिन्न भिन्न विभाग हैं, जो भिन्न भिन्न काम हैं उनमें कोआर्डिनेशन करने का इसका काम है और इसको इसलिये रखा गया था कि सबका एक संतुलन होकर एक इंटेग्रेटेड पिक्चर हमारे सामने आये। मुझे यह महसूस होता है कि इस प्रदेशीय सरकार की भी अपनी सीमायें हैं यद्यपि हम तीसरे प्लान के पहले साल में ७१ करोड़ रुपया प्लान पर खर्च करने जा रहे हैं इसमें प्रदेशीय सरकार को कहां तक स्वतंत्रता है उस ७१ करोड़ रुपये को खर्च करने के लिये एक पैटर्न बना दिय गया है, आल इंडिया पैटर्न से वह बंधी हुई है। मैं स्वयं इस बात को पसन्द नहीं करता। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का यह फर्ज है कि हमको एक बार धन का एलोकेशन कर दे, हमारे टार्गेट्स फिक्स कर दे और प्रान्तीय सरकार को आजादी हो कि वह जिस तरह के ढांचे को बना कर उन टार्गेट्स को हासिल करना चाहे वह करे। लेकिन वह बात हमारे सामने नहीं है हम पर भी बंदिश है।

आज हालत यह है प्लानिंग विभाग जिसका हर दिन विकास हो रहा है एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरियट बनता जा रहा है। एक बात मैंने यह महसूस की कि जो हमारे टैक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन पर जितना ट्रस्ट होना चाहिये उतना ट्रस्ट उन पर नहीं है। जो एक्जिक्यूटिव सर्विसेज हैं उन पर ट्रस्ट हमारा ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री जी की खिदमत में एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। ऐग्रिकल्चर में हमारे पास ८ डिप्टी डायरेक्टर थे और अब बढ़ कर १७ डिप्टी डायरेक्टर हो गये। हर जोन के अन्दर एक-एक हो गये। कमिश्नर्स की पोस्ट बीच में काट दी थी लेकिन फिर शुरू हो गयी। डेवलपमेन्ट को देखने के लिये ७-८ ज्वाइंट डेवलपमेन्ट कमिश्नर्स को नियुक्त करना पड़ा। जब डिप्टी डायरेक्टर्स मौजूद हैं एग्रिकल्चर के तो उनको अपने क्षेत्र में वही पावर्स आप क्यों नहीं देते जो ज्वाइंट डेवलपमेन्ट कमिश्नर्स को आप देना चाहते हैं जब कि हम जानते हैं कि खेती पर सबसे अधिक हमारा एम्फेसिस है और अन्य बातों पर एम्फेसिस बाद की है। तो मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस बात की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं।

मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान इस समय बचत की ओर है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि ब्लाक लेविल पर ए०डी०ओज० की तादाद कम की जा रही है और कम कर भी दी गयी है। यह खुशी की बात है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि ब्लाक लेविल पर जो बहुत से आफिसर्स हैं, बी०एल०डब्लू०, पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल, इनका एक पूलिंग हो सकता है और पूलिंग होने के बाद हम इनको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि कम स्टाफ से काम चल सके। यही नहीं, जहां तक ब्लाक लेविल की बात है, पंचायतों का चुनाव हुआ और यह खुशी की बात है और सरकार को इस बात पर खुश होने का मौका भी है कि जहां ७८ हजार से ज्यादा प्रधानों के चुनाव हुये उसमें बहुत कम हिंसा हुई। परन्तु यह भी है कि कहीं कहीं भ्रष्टाचार भी हुआ और करप्शन भी हुआ और मुझे इस बात का दुःख है कि जो हमारा नियोजन विभाग था, जिस पर अभी तक आमतौर से करप्शन का चार्ज बहुत कम लगता था, अबकी पंचायतों के चुनाव में यह भी इस बात से अछूता नहीं बचा।

मैं एक ही उदाहरण दूंगा क्योंकि बहुत से केसेज अभी अपील में होंगे। एक गांव के अन्दर जहां चुनाव होना था उस गांव का कैंडिडेट आकर ए० डी० ओ० तथा एस०डी०एम० वगैरह से इस बात को कहता है कि मेरे नाम का परचा खारिज कर दिया जायगा। एस० डी० एम० और ए०डी०ओ० जाते हैं २ बजे तो मालूम होता है कि उनका नामजदगी का परचा आ गया और ३ बज कर ५ मिनट पर ए०डी०ओ० एनाउन्स करते हैं कि चंकि नामजदगी का परचा ३ बजे के बाद आया इस वास्ते खारिज किया जाता है। मैंने एक ही उदाहरण दिया, और भी ऐसे बहुत से केसेज हैं लेकिन चूंकि बहुत से मामले अभी अपील में होंगे इस वास्ते मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और चूंकि सरकार का इस बात का आश्वासन भी है कि जो इस तरह के स्पेसिफिक केसेज उनके सामने आयेंगे उनमें उचित दंड दिया जायगा।

औद्योगीकरण की बात मैंने पहले कही। मैं इस बात से सहमत हूं कि एम्प्लायमेन्ट पोटेन्शल स्माल इंडस्ट्रीज के अन्दर ज्यादा होती है और यह सही है कि हमको अपने प्रदेश के अन्दर स्माल इंडस्ट्रीज का एक नेट वर्क बनाना चाहिये। खुशी है कि उस तरफ सरकार का ध्यान इस

[श्री नवल किशोर]

वर्ष और सालों की अपेक्षा अधिक गया है। मेरे पास चार्ट है जिसमें पिछले कुछ सालों के अन्दर नयी नयी यूनिट्स के लिये काफी लायसेन्स मिले हैं लेकिन मैं उन आंकड़ों के अन्दर जाना नहीं चाहता। मैं एक और बात कहना चाहता हूं और वह यह कि हमारा जो प्लान पेपर पर चलता है वह तो सही रहता है परन्तु क्षेत्र में पहुंचते २ वह काफी शुष्क और निर्जीव सा हो जाता है। मेरा अपना अनुभव यह है, मैं उन सरकारी कर्मचारियों के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आदर प्रदर्शित करते हुये जो बहुत ही ईमानदार और कर्मनिष्ठ हैं यह बताना चाहता हूं कि काफी संख्या हमारे कर्मचारियों की ऐसी है जिनकी कोई विशेष आस्था हमारी इन स्कीम्स में नहीं है। एक बार मुझको एक आल इंडिया सेमिनार में जाने का मौका मिला। वहां यह सवाल था कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और खादी को कैसे प्रोत्साहन दिया जाय। उसके प्रेसीडेंट से मैंने एक सवाल पुट किया कि जितने भी डेवलपमेन्ट कमिश्नर्स, बी० डी० ओज० और दूसरे जितने डेवलपमेन्ट के आफिसर्स यहां मौजूद हैं अगर उनकी जेब में एक खादी का हैंडरकरचीफ हो तो मैं यह समझूंगा कि तीन आने की आस्था उनकी खादी के प्रति है। पता लगाने पर मालूम हुआ कि दो या तीन आफिसर्स से ज्यादा के पास खादी के रुमाल नहीं थे। तो जिनको खादी के प्रति आस्था न हो और हम उसका इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं के हाथों में दे दें तो यह सम्भव है कि फिजिकल टारगेट्स हम पूरे कर लें लेकिन बिना आस्था के जो एक मिशनरी स्पिरिट और जोश आनी चाहिये वह नहीं आ सकती।

दूसरी बात यह कि सरकार ने इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिये बहुत से ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर्स खोले हैं जिनमें हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग मिलती है और वे ट्रेनिंग पाते भी हैं। मेरा अपना अनुभव यह है कि बहुत से लोग तो इसलिये ट्रेनिंग सीखते हैं चूंकि हम उनको ट्रेनिंग पीरियड में स्कालरशिप देते हैं चाहे उस ट्रेड में उनका विश्वास हो या न हो। मैं उदाहरण देता हूं कि मऊ में, जो आजमगढ़ जिले में है, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर हैंडलूम इंडस्ट्रीज का है और वहां हमारे बीवर भाई बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। जिस साल में एस्टीमेट्स कमेटी की तरफ से वहां गया था मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि जितने लोग वहां ट्रेनिंग में थे उनमें बीवर क्लास का एक भी स्टूडेंट नहीं था। तो एक बात तो यह देखने की है कि हम इस बात की कोशिश करें कि जिन आर्टीजन्स का पुश्त दरपुश्त से एक पेशा है उनके बच्चों को हम एनकरेज करें और उनको आकर्षित करने की चेष्टा करें।

तीसरी बात यह है कि जो हमारे यहां ट्रेनीज हैं उनके लिये भी हमें इस बात की कोशिश करना है कि जब वह ट्रेनिंग पाकर बाहर निकलें तो इस बात के आंकड़े हमारे पास होने चाहिये कि वह प्रशिक्षित होकर क्या करते हैं, उनकी किसी तरह से कोआपरेटिव बन पाती है या नहीं और उनके लिये सरकार क्या सहायता दे सकती है और देना सम्भव है। जहां तक जीप का ताल्लुक है बजट लेविल पर उसके बारे में कहा जा चुका है इसलिये उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। दोनों पहलू हैं जीप के होने पर काम जल्दी और अच्छा हो सकता है और उसके साथ ही साथ यह भी है कि उसका दुरुपयोग भी होता है। यह तो सरकार के लिये अपनी जगह पर देखने की बात है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कहा गया कि योजनाओं में लोगों का उत्साह नहीं होता है, यह सही है और हमारे सामने ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनसे मालूम होता है कि लोगों में जितना उत्साह होना चाहिये वह नहीं हो पाया है। लेकिन आपने देखा कि अंतरिम जिला परिषद् विधेयक में तरमीम की गई। उसमें क्षेत्र समितियों का निर्माण भी है और गांव सभाओं की बात भी है। यह बात सही है कि विकेन्द्रीयकरण की तरफ सरकार का कदम बढ़ा है और मैं यह नहीं कहता कि वह पूर्ण विकेन्द्रीयकरण है। मुझे भी कुछ भय है और संशय भी है। मैं यह भी मानता हूं कि जनता के जो नुमायन्दे हैं, चाहे वे गांव सभा में हों, क्षेत्रीय समिति में हो या जिला परिषद् में हों उनके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिये। लेकिन एक कठिनाई जरूर है, जो हमारा अनुभव रहा है वह हमें मजबूर करता है कि विकेन्द्रीयकरण की तरफ बढ़ने का हमारा लक्ष्य

होना चाहिये और बिना उसके सही माने में जनतंत्र मजबूत नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे तो हमें डर है कि हम जो अपने यहां डेवलपमेन्ट के काम कर रहे हैं उनका बोझा वहां का नव–नेता उठा पायेंगे या नहीं गांव पंचायतों में बैलेट का तरीका इस्तेमाल किया गया है, कहीं शिकायतें हों, लेकिन अधिकांश रूप में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुये और उसके अन्दर अच्छाई की बात पैदा हुई है। यह भी आशा है कि नेतृत्व में सुधार होगा।

हमको बताया गया कि इंजीनियरिंग के अन्दर हमारे यहां काफी विकास हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि काफी विकास हुआ है और होना भी चाहिये था। लेकिन मेरा अपना खयाल यह है कि जहां तक ओवरसियरों के इंस्टीट्यूशनों का सम्बन्ध है बीच में ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो गये कि जिनसे पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई और हम सबको इम्प्लायमेंट नहीं दे पाये। हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो या टेक्निकल ट्रेनिंग हो उनका कुछ न कुछ समन्वय हमें अपने यहां के इम्प्लायमेंट के साधनों से जरूर जोड़ना होगा। अगर टेक्निकल हेंड्स की संख्या ज्यादा बढ़ गई और हम उनको इम्प्लायमेंट नहीं दे पाये तो वह भी हमारे लिये एक परेशानी होगी।

श्रीमन्, सब से बड़ी बात यह है कि इस नियोजन के समय में भी डिपार्डमेंटलिज्म अपनी जगह पर वैसा ही है। हम कोआर्डिनेशन की बात करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। अपने यहां एक शारदा पावर हाउस का कंस्ट्रक्शन हुआ था। अगर वहां पर पी० डब्ल्यू० डी० ने पुल बनवा दिया होता तो इसमें आयात में कई लाख रुपये की बचत हो जाती लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० से कोई समन्वय नहीं हो पाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि डिपार्टमेन्टलिज्म अपनी जगह पर तेजी से इन्टैक्ट है।

अन्त में मैं एक बात की दरख्वास्त करके अपनी बात खत्म करूंगा कि नियोजन का जो विषय है यह आलोचना और प्रत्यालोचना से हल होने वाला नहीं है। हम आप और सारा देश कमिट हो गया है कि हमें अपने देश में नियोजन करना है और मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिये बधाई के पात्र हैं। यह हो सकता है कि हमारे कामों में कुछ कमियां रही हों मगर सारे देश के अन्दर आज नियोजन के प्रति एक आस्था, एक विश्वास पैदा हुआ है और सारे प्रदेश के गांव के आदमी आजकल प्लानिंग माइंडेड होते चले जा रहे हैं उसका फायदा उठा कर हम सब को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिये।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—मान्यवर, हमारे प्रदेश में दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी हैं जिनमें लगभग ४१७ करोड़ रुपये की योजनायें बनायी गयीं। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना का आरम्भ है। देखना यह है कि इन दस वर्षों के समय में प्रदेश की दशा क्या हुई। मान्यवर, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का संक्षिप्त प्रारूप जो सितम्बर, १९६० में प्रकाशित हुआ है, मैं उसके आंकड़े आपके द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं।

कीमतों के आधार पर जो सूचनांक दिये गये हैं, उनमें १९५०–५१ में हमारे प्रदेश के सूचनांक १६.३ थे और १९५८–५९ में १८.६ प्रतिशत, १८.४ १९५०-५१ में और १९५८-५९ में १५.९। इससे यह साबित होता है कि प्रदेश ने कितनी तरक्की की। इसके बाद कृषि, उद्योग, वाणिज्य एवं परिवहन और अन्य सेवाओं के भी आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। कृषि में १९५०–५१ में १०० और १९५८–५९ में ११५। उद्योग में १९५०–५१ में १०० और १९५८–५९ में १००.९। वाणिज्य एवं परिवहन में १९५०–५१ में १०० और १९५८–५९ में ११७.६ अन्य सेवाओं में १९५०–५१ में १०० और १९५८–५९ में ११७.१। विभिन्न क्षेत्र में होने वाली आय में राज्य की आय का भाग १९५०–५१ में २० और १९५८–५९ में १७.९ कृषि में। उद्योग में १९५०–५१ में १५.५ और १९५८–५९ में १२.४ वाणिज्य एवं परिवहन में १५.८ १९५०–५१ में और १४ १९५८–५९ में। अन्य सेवाओं में १९५०–५१ में १९.६ और १९५८–५९ में १५.६ १९४८–४९ के मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत आय १९५०–५१ में २१८.२६

[स्वामी विश्वेश्वरानन्द]

और १९५८–५९ में २५९.०२ । उत्तर प्रदेश की आय के सूचनांक–१९५०–५१ में १०० और १९५८–५९ म १००.३ । उत्तर प्रदेश का प्रतिशत भाग १९५०–५१ में १०४.९ और १९५८–५९ में ८८.२ ।

इससे साबित होता है कि इन दस वर्षों में विकास योजनाओं पर जो धन और श्रम व्यय किया गया वह व्यर्थ हुआ। मैं इस बात को मानता हूं कि प्रदेश में नहरें बनीं, ट्यूब-वेल बने, छोटी सिंचाई की योजनायें बनीं, सड़कें बनीं, स्कूल बनें, लेकिन श्रीमन् । अंग्रेजी शासन काल के बाद इन चौदह वर्षों में कांग्रेसी शासन ने इस राज्य में जनता को क्या दिया है? इस राज्य ने दिया है आतंक, दिया है भय, दिया है निराशा और इस राज्य में जनता में पैदा की है घृणा । मुझे कुछ चित्र उपलब्ध हुये हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको पेश करना चाहता हूं । यह चित्र बताते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता कहां जा रही है ।

(फोटो दिखलाते हुये) यह श्रीमन, आतंक, है, यह आतंक, का रूप है । श्रीमन्, यह भय का रूप है, यह घृणा का रूप है और श्रीमन्, यह निराशा का रूप है जिसके बाद सिवाय मौत के दूसरी चीज बाकी नहीं रहती । (व्यवधान) फोटो मैं भेज दूंगा । तो श्रीमन्, यह दशा हो रही है । अब एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि यह क्यों हो रही है निराशा भय और आतन्क यह क्यों है । मैं गुप्ता जी की ही मिसाल दे रहा हूं ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी अभी आगरा गये हुये थे ग्राम सुरक्षा समितियों (Village defence Committees) का उद्घाटन करने के लिये । उस जगह पर पुलिस ने किया क्या श्रीमन्, कि चार पांच दिन पहले से गांव में ट्रकें और मोटरें दौड़ाईं लाउडस्पीकरों के साथ और जनता को यह धोका दिया कि तुमको लाइसेन्स दिये जायेंगे, एक-एक गांव में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह, तुम वहां चलो । जनता वहां पहुंची । उसके साथ-साथ पुलिस के ५०० नवजवान सादी वर्दी मे पता नहीं गुप्ता जी का स्वागत करने के लिये, या गुप्ता जी की हिफाजत करने के लिये या उनकी रिपोर्ट लेने के लिये कि जनता उनके बारे में क्या कहती है उस दिन किरावली तहसील में उपस्थित थे । श्रीमन्, बड़ा दुख है, मुझे जैसी कि सूचना मिली है १० हजार रुपये उस उद्घाटन में खर्च हुये । उसके बाद वहां क्या हुआ, डकैतों से किस प्रकार सुरक्षा की जाय, उसके लिये कुछ उपाय बताये गये जिनको सुनकर हंसी आती है और दुख होता है । उन्हें यह बताया गया कि जिस वक्त डकैत हमला करें उस वक्त पड़ोस के किसी घर मे आग लगा दी जाय । और क्या किया जाय कि रंग घोलकर तैयार रखा जाय ।

पंचायतों के चुनाव में जो मेहरबानी इस सरकार की हुई है आठ-आठ दस-दस कैंडी-डेट्स एक-एक जगह के लिये खड़े हो गये । उससे जो दुश्मनी पैदा हो गई है उसका इलाज भी तो फौरन होना चाहिये । तो वह इलाज क्या होगा? उनको उपाय यह बताया गया कि डकैत जिस वक्त डाका डालने आवें तो उनके ऊपर रंग डाल दिया जाय । अब मान लीजिये कि मदद इमदाद के लिये वहां कोई पहुंचता है और अगर पार्टी बन्दी के बिना पर किसी के ऊपर रंग डाल दिया जाता है तो वह बचने वाला नहीं है । चाहे बाद में वह किसी तरह से बच भी जांय लेकिन मिट जरूर जायेंगे । और श्रीमन्, क्या बताया गया? बताया गया कि जिस वक्त डकैत आ जायें तो कांटे रास्ते में बिखेर दिये जायं । यह कांटे किसको गड़ेंगे? यह नंगी पैर रहने वाली देहात की जनता को ही तो गड़ेंगे क्योंकि डकैत तो अब पुलिस की वर्दी में आते हैं और बूट पहन कर आते हैं । तो श्रीमन्, यह उपाय बताये गये । बड़ा दुख होता है और मैं समझता हूं कि सारे सदन को यह जानकर दुख होगा ।

वहां के एस० ओ० महोदय की तारीफ बताऊं । गुप्ता जी के पहुंचने के पहले वहां के एस० ओ० ने दूकानदारों को यह धौंस दी कि अगर दूकान नहीं बन्द करोगे और वहां गुप्ता जी के स्वागत में नहीं पहुंचोगे तो मैं तुम्हारे ताले तुड़वा दूंगा । और तुम्हारी दुकान लुटवा

दूंगा। उनकी शिकायत यहां आ चुकी है। सरकार के पास भी पहुंच चुकी है। और वह एस० ओ० कौन हैं कि जो फतेहाबाद के पुलिस थाने पर मौजूद थे कुछ अरसे पहले जहां कि बदमाशों ने पुलिस थाने पर हमला किया, उनके घर में घुस गये, उनको पीटा, उनकी स्त्री को पीटा और ऐसा बताया जाता है कि करीब ८० हजार का माल वह वहां से ले गये जबकि एक प्लाटून पी० ए० सी० का वहां मौजूद था। वही एस० ओ० साहब दूकानदारों से कहते हैं कि दूकानें बन्द करके गुप्ता जी के स्वागत में चलो नहीं तो तुम्हारे ताले तुड़वा दिये जायेंगे। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसकी जांच करवायें। अगर उनके पास शिकायत पहुंच गई है तो ठीक है और नहीं तो मेरी इस बात को शिकायत मानकर वह इसकी जांच करायें कि कैसे उस एस० ओ० को इतनी जुर्रत हुई।

अभी कुछ अरसे पहले एक थानेदार (एस० ओ०) ने एक जाटव के लड़के को जान से मार डाला। मैंने इन्तहा कोशिश की कि उसकी सही एन्क्वायरी की जाय और उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय लेकिन उस घटना को लगभग साल भर हो गया और उसकी कोई जांच नहीं हुई। डी० एम० भी मौजूद थे मैंने कहा कि इसकी जांच कराइये जिससे कि कुछ फैसला हो जाय, लेकिन जांच नहीं हुई।

श्रीमन्, मैं कहना नहीं चाहता हूं कि किन-किन अफसरान ने कितनी-कितनी रिश्वत उससे ली जिसने कि १ लाख रुपया चावल को स्मग्लिंग में उस थाने से कमाया। उस स्मग्लिंग के सिलसिले में मेरे ऊपर केस अभी भी चल रहा है क्योंकि मैंने उसे चेक किया। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है कि स्मग्लिंग की चेकिंग करने के कारण मेरे ऊपर या जनता के ऊपर केस चल रहा है, लेकिन यह दुख की बात जरूर है कि स्मग्लर्स के ऊपर कोई कार्यवाही न हो। उसके ऊपर सरकार कोई कार्यवाही करेगी इसकी हमें उम्मीद नहीं है। अब और ज्यादा खतरा हमें मालूम होता है, लेकिन चिन्ता नहीं है।

आज सब से बड़ी जरूरत इस बात की है कि शासन के द्वारा जनता में उत्साह पैदा किया जाय। उसके भीतर से डर निकाला जाय और कमजोरियों को निकाला जाय, लेकिन आज आपके विकास अधिकारी क्या करते हैं पक्षपात, जातीयता, दुश्चरित्रता, दलबन्दी, कागजों में दिखावटी कार्यवाही और पंचायत चुनावों में बी० डी० ओ० द्वारा भाग नम्बर १ व २ में तारीख पैदायश के बढ़ाने में ८०० रुपये वसूल करना। सरकारी जीपों का दुरुपयोग किया जाता है। झूठे कामों में अपना शेयर रखते हैं बुरी बातों को दबा दिया जाता है। जीप लेकर बाजार में घूमते हैं। जनता के नजदीक नहीं जाते हैं। मैं देहाती क्षेत्र में रहता हूं तो इन सब बातों को जानता हूं कि वे क्या करते हैं। बहुत सी शिकायतें यहां पर की गई हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल माननीय चौधरी साहब ने कृषि की ग्रान्ट के समय में कहा था। मैंने सरकार से पूछा था कि वाटर लागिंग और रेह से किरावली तहसील में कतनी जमीन मारी गई है। तो बताया गया कि लगभग १८०० एकड़ और कहा कि यह कोई विशेष नुकसान नहीं है। मैं समझता हूं प्रदेश में ६० लाख एकड़ से कम जमीन नहीं है जो रेह से मारी जा चुकी है और करीब ६० लाख एकड़ ही water logging से हरसाल तबाह होती है। जिस प्रदेश के अन्दर इतनी जमीन वाटर लागिंग और रेह से मारी जाय और सरकार कुछ न करे तो यह खेद की बात है। जो जमीन इस तरह से बरबाद हो रही है १० वर्ष से इस सरकार ने उसके लिये कुछ नहीं किया है और यदि किया है तो बहुत कम किया है। आज भी हमारे पच्छिमी जिलों के अन्दर वाटर लागिंग और रेह से काफी बरबादी हुई है। उन आंकड़ों के बारे में चौधरी साहब ने कहा था कि यह कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि १८०० एकड़ जमीन की पैदावार का आप कितना अनुमान लगाते हैं। चाहे गन्ना हो, चाहे गेहूं हो, और चाहे धान हो अगर १० मन फी एकड़ भी आप रखें तो श्रीमन् १८००० मन अन्न पैदा हो सकता है। लेकिन श्रीमन्, १८०० एकड़ जमीन उनके नजदीक कोई माने नहीं रखती। इसके लिये मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि सरकार उन

[स्वामी विश्वेश्वरानन्द]

गरीबों पर विश्वास नहीं करती। उनकी काश्त का जो नुकसान होता है उसको उतना नुकसान सरकार नहीं मानती है। वह जनता भी सरकार पर विश्वास नहीं करेगी। जब ८० फीसदी जनता, जो देहात में रहनेवाली है, आप के ऊपर विश्वास नहीं करती तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी सरकार इस जगह आये, चाहे सोशलिस्ट पार्टी की सरकार हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो, चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार हो और चाहें आप हों ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते। जनता आप पर विश्वास नहीं करती है भले ही झूठ, कपट, छल, धोखा, लालच से इन कुर्सियों पर यह सरकार विराजमान हो जाय लेकिन ईमानदारी से नहीं आ सकती है। यह बिल्कुल हमारा पक्का विश्वास है। इसमें जन सहयोग का सवाल है और बिना जन सहयोग के कोई सरकार टिक नहीं सकती।

बेकार लोग १९ लाख बतलाये गये। अगर १९ लाख आदमियों को प्रदेश में आप काम दें और उनको दो रुपया रोज ही मजदूरी दें तो साल भर में हमको १ अरब १४ करोड़ का लाभ हो सकता है, लेकिन यह सरकार उनको काम देना नहीं चाहती है। आप बेकारी बढ़ाने की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से सन् ४३ में बंगाल के अन्दर भुखमरी फैली थी और ३६ लाख आदमियों को भूख से मार डाला था उसी तरह से यह सरकार जनता को भूखों मारना चाहती है। आप चाहते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़ी बड़ी कोठियों में रहकर ऐशो आराम करें और दौलत इकट्ठा करें। मैं पूछना चाहता हूं कि इस विधान सभा के अन्दर कौन ऐसा आदमी है जिसके पास चुनाव के लिये खर्चा नहीं था। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था फिर भी चुनकर आगया। चाहे मैं यहां पर कुछ कर सकूं या नहीं। दूसरी तरफ गुप्ता जी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता और दूसरे मंत्री और एम० एल० ए० हैं जो २ हजार, ५ हजार, १० हजार, २० हजार, १ लाख और २ लाख चुनाव में खर्चा करते हैं। उनके पास कहां से रुपया आता है ? साफ जाहिर है कि यह सरकार पूंजीपतियों की हिमायती है और किसान, मजदूर और गरीबों की हिमायती नहीं है।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीया मंत्री जी द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, ९ करोड़ ५२ लाख ६६ हजार रुपये का यह अनुदान है और यह रकम इस कार्य के लिये थोड़ी है। माननीय गेंदासिंह जी अगर इसमें कुछ बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखते कि यह रकम जनहित के लिये कम है, इसे और बढ़ाना चाहिये तो मैं उनका समर्थन करता। परन्तु उन्होंने इस कार्य के लिये एक रुपया रखने की मांग की है और इस उसूल के मातहत उनकी भावनाओं का पता चलता है कि वे योजना के कार्य का कितना समर्थन करते हैं। अगर वे इसके समर्थक होते तो इस प्रकार की कटौती वे न करते और इस रकम को बढ़ाने की कोशिश करते।

श्रीमन्, यहां योजना का कार्य सन् १९५१ से शुरू हुआ और एक प्रकार से यह १९४२ से शुरू हुआ और बराबर उसके के बाद चल रहा है। प्रथम तो ग्रामीण जनता की समझ में ही यह नहीं आया कि यह क्या है। उस के बहुत दिनों बाद उसकी समझ में यह बात आयी कि यह क्या काम है और उसका प्रभाव हम को इस बात से समझ लेना चाहिये कि जिस प्रकार जनता ने ग्राम सभाओं के सभापति का चुनाव किया है, वह उसका एक नमूना है। वह समझ गये कि सभापति क्षेत्रीय समिति का सदस्य होगा और इसलिये उन में होड़ हुई। कहीं कहीं तो औरतों ने इतना दंगल मारा कि पुरुषों को खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हुई। इससे ज्यादा सबूत इस बात का है नहीं कि जितने सभापतियों का चुनाव हुआ वह बहुत ज्यादा दिलचस्पी से हुआ। जहां वह चुनाव सर्वसम्मति से हुआ वहां भी गांव भर ने बैठ कर निर्णय किया इसलिये कि सभापति ब्लाक समिति का सदस्य होगा। उसे जिम्मेदारी से अपना काम करना है इसलिये अच्छा आदमी ही भेजा जाय। यह ठीक है कि इस भावना के प्रलोभन में कहीं कहीं दूषित दृष्टि भी हुई, कहीं लाठियां चलीं, कहीं शायद कत्ल भी हुये, लेकिन यह इस बात का प्रतीक है कि जनता की रुचि अब ब्लाक के कार्य में अधिक है और उस ओर अग्रसर हो रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—वाह वाह।

श्री गुप्तारसिंह—मैं मोतीलाल जी को उनकी वाह वाह के लिये बधाई देता हूं। आप शहरों की मिलों में रह कर संभव है कि उनके मजदूरों में ही किसानों का दर्शन करते हों, लेकिन किसान तक पहुंचने का आपको समय नहीं मिलता होगा। मैं प्लानिंग की बैठकों में जाता हूं और देखता हूं। यह ठीक है कि जितना कार्य होना चाहिये था उतना नहीं हुआ, लेकिन जितना कार्य मुझे और माननीय अवस्थी जी को करना चाहिये था उतना तो हम ने भी नहीं किया। प्लान फरिश्ते तो पूरा करेंगे नहीं, योजना बाहर के आदमी आ कर नहीं बनायेंगे, जो लोग उन ब्लाक में बसते हैं, चाहे वे शैडो ब्लाक हों अथवा विकास खंड उनको ही उन कामों को पूरा करना है। हमने विकास के काम में, उत्पादन के काम में कितना कार्य किया है? हम को अपना लेखा जोखा भी तो रखना है। मनुष्य के कन्धे मे दो झोले होते हैं—एक में अपनी बुराई होती है और दूसरे में दूसरों की बुराई होती है। अपनी बुराई वाला झोला पीछे होता है उसमें वह अपनी बुराई देख नहीं पाता, दूसरे की बुराई वाला झोला सामने होता है इसलिये वह दूसरों की बुराई ही देखता है।

आज हम देखते हैं कि अधिकांश राजनैतिक पार्टियां हमारे विकास के कार्यों में अड़ंगा लगाती हैं। सभी को मैं नहीं कहता, लेकिन अधिकांश ऐसा करती हैं। अगर किसी हरिजन को कहीं कुंवां खोदना है तो लोग वहां जाकर कहने लगते हैं कि यह हमारे दादा की जगह है, फलाने की जगह है, और उसको कुंवां नहीं बनाने देते। तो इस तरह की बातें होती हैं।

इसके अलावा हरिजनों के विकास के लिये हमारी सरकार ने काफी काम किये हैं। सच्चे दिल से आप सोचिये, क्या सार्वजनिक क्षेत्र में हरिजनों के लिये कुंवें नहीं बने हैं? क्या हरिजनों को अपने गिरे हुये मकानों को बनाने के लिये अनुदान नहीं मिला है। क्या हरिजन लड़कों को पढ़ाने के लिये वजीफा नहीं मिला है? मिला है? अगर, अध्यक्ष महोदय, आप जांच करायें तो आपको पता चलेगा कि पंचायतों द्वारा बनवाये हुये ऐसे ऐसे पुल हैं जिनको पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के ओवरसीयर और इंजीनियर भी नहीं बनवा सकते हैं। आज जितनी कीमत में अपने श्रम द्वारा उन्होंने रास्ते, नालियां और पुल बनवायें हैं और जितने सुन्दर बने हैं, उनको सरकारी कर्मचारी नहीं बनवा सकते। तो गांव में काफी काम हुआ है। वह काम प्लानिंग द्वारा हुआ है।

एक माननीय सदस्य ने कुछ कहा था, उसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, माननीय मंत्री जी देंगे, किन्तु मैं अपने यहां के दो गांव के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे यहां दो गांव हैं—बर्रहा और हैबतपुर—इन गांव में पहले एक भी पक्का मकान नहीं था, लेकिन आज आपको वहां सभी मकान पक्के मिलेंगे, कच्चा मकान देखने को मुश्किल से मिलेगा। मैं अपने मित्रों को आमंत्रित करता हूं, वे वहां चल कर देखें कि कितनी प्रगति गांव में हुई है। और यह प्रगति प्लानिंग की देन है।

श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, यह दूसरी बात है कि सिंचाई के लिये जितने कुंवें आज देहातों में बने हैं, वे पर्याप्त न हों, लेकिन अगर वहां जाकर देखा जाये तो मालूम होगा कि वहां पर काफी कुंवें बने हैं। आप शहरों में लिफ्ट पर चढ़ना छोड़ दीजिये, गांव में जाइये, वहां की पगडन्डियों पर जाइये, तब आपको वहां की तरक्की देखने को मिलेगी। हजरतगंज में आपको किसान की पैदावार दिखाई नहीं देगी, उसके लिये तो आपको गांव में जाना होगा। उनकी खेती आपको गांव में ही देखने को मिलेगी। मैं किसान का लड़का हूं, मैं हल जोतने से लेकर सभी बातें किसानी की जानता हूं।

अब मैं कुछ सुझाव भी माननीय मंत्री जी की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक बात तो मैं फसल के कम्पीटीशन की कहता हूं जो आप इनाम देते हैं खेती करने वालों को न देकर ग्राम समाज को देते हैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। आज जो मेहनत करता है, वह जिस गांव में रहता है इनाम उस गांव को दिया जाना चाहिये, जिसकी खेती होती है, जो खाद डालता है, परिश्रम

[श्री गुप्तारसिंह]

करके अधिक उपज पैदा करता है, इनाम उसको अर्थात उसके ग्राम सभा को न मिल कर, इनाम दूसरे उस व्यक्ति के गांव को मिलता है जो दूसरे गांव का रहने वाला होता है और जिसकी वह जमीन होती है उस गांव को नहीं मिलता। यह मेरे ऐसे आदमी को कुछ खटकता है, इसका निर्णय हो जाना चाहिये कि जो किसान हो, उस जगह का रहने वाला हो जहां खेती होती है, उसकी आबोहवा में पला हो, उसने खेती में उत्पादन बढ़ाया हो तो उस ग्राम समाज को उसका श्रेय मिलना चाहिये जिस ग्राम समाज में किसान रहता हो।

दूसरी चीज है तकावी। इसमें बड़ी परेशानी होती है। ब्लाक से पास हुआ अनुदान या तकावी वाला बन तहसीलदार साहब के यहां गया। कानूनगो उसकी जांच करने के लिये गया, पटवारी का इन्तखाब हो, और यह तो हम मानते ही हैं कि देश में इतनी ईमानदारी नहीं है कि सच्चाई से काम हो सकेगा। तो यह हमको विश्वास नहीं करना चाहिये और आशा भी नहीं करनी चाहिये कि हमारे लड़के जिनको हम अपने घर में झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरे के खेत में जानवर चराना, दूसरे की पेंसिल चुरा कर लाना, हाई स्कूल में मिठाई के लड्डुओं को खा जाना और ढेले बांध कर रख देना और लड़कों का मजाक उड़ाना, कालिज में पढ़ते वक्त हाकी लेकर बिना किराये के सफर करना, ऐसा जब उनको सबक सिखाते हैं और ऐसे आदमी जो ताश खेलने के वक्त जब कि कोई पैसा भी नहीं मिलता लेकिन जोभ निकाल करके पत्ता साथी को बताते हैं तो ऐसे देश की जनता से ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिये कि वह एक दम से ठीक तौर से काम करने लगेगी। हमने तो भट्टा लगाया है और पाती से लगाया है और फोर्थ नम्बर की ईंट पकायी है तो लोना जरूर लगेगा। हमारी आदतों का असर बच्चों पर पड़ता ही है, तो क्या वह नौकरी करने पर हरिश्चन्द्र हो जायेंगे, अगर इसको दूर करना है तो योजना के भीतर जुट करके सब पार्टी के सदस्यों को सबको मिल करके ईमानदारी ग्रामों में लाना है, उनको राजनीति का साधन नहीं बनाना है। कहीं हड़ताल हुई लड़कों को और हम सभापति बन गये, चाहे लड़के घर फूंके या किसी को मारे पीटें। इस प्रकार से तो यदि कहीं डाकुओं के डेपुटेशन उनके पास आने लगें तो उनको भी यूनियन बना कर उसके सभापति बन बैठेंगे। इस प्रकार योजना कामयाब न होगी, इसकी तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है।

आप जानते हैं कि २८ हजार पटवारियों ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह पर, पटवारियों को, लेखपाल रखे गये और झंडे के सामने कसम खिला कर रखे गये और वह आपके घर के ही ठाकुर, ब्राह्मन, चमार, गड़रिया, पासी थे वह सब क्या देवता निकले? कोई देवता नहीं निकला, उन पटवारियों से कम नहीं निकले। तो हम तो सन्तान वैसी ही पैदा करते हैं। इसलिये एक दिन मुकर्रर कर दिया जाय तहसीलदार के यहां कि फलां दिन इनकी दरख्वास्तें आयेंगी और जितने तकावी वाले हैं उसका एक दिन में काम हो जाय। हर ब्लाक और तहसील में वह जाकर अपनी तकावी ले ले। उनको बार बार लौटना न पड़े जिसमें लोगों को रिश्वत देने का मौका न मिले।

एक बात जल्दी में कह कर समाप्त करूंगा चूंकि लाल-बत्ती हो गयी है। अभी बड़ी चर्चा हुई है जीप की। दरअसल जीप में चढ़ कर तो हमारा दिमाग घूम जाता है। तब अधिकारियों का भी घूमता ही होगा। तो वह घूम जाते हैं। लेकिन, अगर इसको बन्द कर देंगे तो वह काम नहीं करेंगे और कहेंगे कि हम क्या करें। फिर यह चक्कर पड़ेगा कि यह तो सब झूठा भत्ता बना रहे हैं। तो उसके लिये जो समिति है वह ब्लाक के भीतर उस प्रोग्राम को बनाये। सब पार्टी के सदस्य हैं वह इकट्ठे होकर सारा प्रोग्राम तय कर लें ताकि कोई गड़बड़ी न होने पाये।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा) —बहुत समय हो गया है श्रीमान् सुनते सुनते एक चीज बड़ी सुहावनी चल रही है सदन में जो आंकड़े होते हैं कि कितने टन गल्ला बढ़ा शाबाश लेकिन फिर खल का आटा क्यों खिलाया गया? एक तरफ है अनुमान और दूसरी तरफ है मनमाना। कहते हैं कि वर्षा होगी मालूम नहीं यह सरकार देश को कहां पहुंचावेगी। खेती कभी

जानते नहीं हैं, हल चलाना जानते नहीं है, बीज बोना जानते नहीं हैं, बैल हांकना जानते नहीं फिर बाहरी और भीतरी बैल की बात बता सकते नहीं। और नाम क्या रख दिया ? दो बैलों के नाम पर वोट दो। हैं तमाशे की चीज, श्रीमन् आपके द्वारा।

श्री अध्यक्ष---अब आप बजट पर आ जाइये।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं नकली बजट पर कभी नहीं बोलूंगा। मैं सच्चे बजट की बात कह रहा हूं। यह ढोंग है। सच्ची बात कहने वाला यही सदन है। कहता रहा है और कहता रहेगा।

एक मेरे भाई ने कहा था कि डाकुओं के भी प्रधान बन जावेंगे। तो मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि दो तरह के डाकू और दो तरह के चोर होते हैं, श्रीमन्, एक रात के और दूसरे दिन के। एक डाकू वे होते हैं जो डकैती डालकर माल मारते हैं पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है वे जेल जाते हैं। दूसरे प्रकार के डाकू वे होते हैं जो पहले जेल काट आते हैं, फिर डकैती डालते हैं लेकिन उनका कुछ भी दुनिया में नहीं होता है। आप विचारें श्रीमन्। जब तक यहां किसान का राज नहीं होगा तब तक उसकी हालत नहीं सुधर सकती है चाहे जितनी यह सरकार अपने को किसानों की और मजदूरों की सरकार कहती रहे।

श्रीमन्, कहा जाता है कि पानी, बीज, खाद और तकावी किसान के लिये दिया जाता है। लकिन जो मध्यम श्रेणी का किसान है उसे कुछ नहीं मिलता है। उसके लिये कुएं का भी प्रबन्ध नहीं है। इस सरकार ने दोनों चीजें हाथ में ले लीं, शासन भी और सेठगीरी भी। गांधीजी अंग्रेजों से कहा करते थे कि एक चीज लो। या तो शासन ले लो या बनिया बन जाओ। तो ये दोनों लिये हुए हैं और सवाये का भी लेते हैं और फिर हमारे ऊपर एहसान ! सरकार इस चीज को खत्म कर दे। सरकार ने हमारे साथ क्या किया ?

श्री अध्यक्ष---समय समाप्त।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, दस मिनट और दीजिये। कांग्रेसियों के तो महल बन गये और बेचारा गरीब मर गया। उनकी हालत पर भी तो गौर किया जाय।

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठें। समय हो गया।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
१४ अप्रैल, १९६१।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९९ पर)

स्वतंत्रता संग्राम इतिहास समिति के सदस्यों की सूची निम्नांकित है :

सरकारी सदस्य—

१ श्री मुजफ्फर हसन ।
२ श्री आदित्यनाथ झा, आई० सी० एस०
३ श्री गोविन्द नारायण, आई० सी० एस०
४ श्री केहर सिंह, आई० ए० एस०
५ श्री भगवतीशरण सिंह, आई० ए० एस०
६ डा० बी० एस० हैकरवाल ।
७ डा० एस० ए० रिजवी ।

गैर सरकारी सदस्य—

१ श्री मोहनलाल गौतम
२ डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ।
३ डा० बालेश्वरीप्रसाद सक्सेना ।
४ प्रो० मुहम्मद हबीब
५ डा० रामशंकर त्रिपाठी ।
६ श्री कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर ।

श्री कमलापति त्रिपाठी समिति के अध्यक्ष हैं ।

उक्त समिति ने स्वतंत्रता संग्राम इतिहास लिखने के लिए बहुत सामग्री एकत्रित की है व उसका संकलन करके ५ ग्रन्थ प्रकाशित कर चुकी है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९–३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०१–४०२ पर)

२९—बलरामपुर (जिला गोंडा) में अल्पकालीन महिला प्रौढ़ शिक्षा विद्यालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की देखरेख में १६ जनवरी, १९६० से चल रहा है। उक्त संस्था की प्रिंसिपल तथा अन्य लोगों द्वारा संस्था की कमेटी के विरुद्ध रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिसमें कहा गया था कि उनको निर्धारित वेतन से कम दिया जाता है तथा हस्ताक्षर निर्धारित वेतन पर कराये जाते हैं। राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने कमेटी के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच कराई। शिकायत की पुष्टि होने पर राज्य बोर्ड ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अगली किस्त उस समय तक न भेजने की सिफारिश की जब तक संस्था नई कार्य कारिणी समिति बना कर उसे कार्य क्षेत्र में पूर्ण अधिकार न दे दे। उक्त कारणवश केन्द्रीय बोर्ड ने अगली किश्त नवम्बर, १९६० से रोक दी है उक्त संस्था की ग्रान्ट रद्द नहीं की गई है।

३०—उक्त संस्था के ग्रान्ट के उपयोग के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड के कार्यालय के इन्सपेक्टर तथा वेलफेयर आफिसर के द्वारा राज्य बोर्ड ने जांच कराई तथा जो अनियमिततायें कमेटी के विरुद्ध रिपोर्ट में थीं वे ठीक पाई गईं इसके आधार पर ही ग्रान्ट रोक दी गई थी। उक्त संस्था राज्य बोर्ड के ही देख रेख में कार्य करती है। राज्य सरकार का इसके संचालन से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

'सत्यो ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०२ पर)

परिशिष्ट 'अ'

प्रदेश के प्रत्येक जिले में कार्य करने वाले प्रसार निदेशकों की संख्या

क्रम-संख्या	जिला	प्रसार निदेशकों की संख्या	क्रमांक	जिले का नाम	प्रसार निदेशकों की संख्या
१	देहरादून ..	२	२८	जालौन ..	२
२	सहारनपुर ..	४	२९	हमीरपुर ..	३
३	मुजफ्फरनगर ..	६	३०	बांदा ..	२
४	मेरठ ..	१०	३१	वाराणसी ..	८
५	बुलन्दशहर ..	५	३२	मिर्जापुर ..	४
६	अलीगढ़ ..	८	३३	जौनपुर ..	७
७	मथुरा ..	३	३४	गाजीपुर ..	५
८	आगरा ..	४	३५	बलिया ..	५
९	मैनपुरी ..	७	३६	गोरखपुर ..	६
१०	एटा ..	२	३७	देवरिया ..	७
११	बरेली ..	४	३८	बस्ती ..	५
१२	बिजनौर ..	२	३९	आजमगढ़ ..	७
१३	बदायूं ..	३	४	लखनऊ ..	३
१४	मुरादाबाद ..	४	४१	उन्नाव ..	४
१५	रामपुर ..	१	४२	रायबरेली ..	५
१६	शाहजहांपुर ..	३	४३	सीतापुर ..	४
१७	पीलीभीत ..	२	४४	हरदोई ..	३
१८	नैनीताल ..	१	४५	खीरी ..	२
१९	अल्मोड़ा ..	४	४६	फैजाबाद ..	५
२०	पौड़ी-गढ़वाल ..	४	४७	गोंडा ..	१
२१	टेहरी-गढ़वाल ..	३	४८	बहराइच ..	१
२२	फर्रुखाबाद ..	५	४९	सुल्तानपुर ..	४
२३	इटावा ..	४	५०	प्रतापगढ़ ..	२
२४	कानपुर ..	४	५१	बाराबंकी ..	३
२५	फतेहपुर ..	२	५२	उत्तरकाशी ..	*..
२६	इलाहाबाद ..	६	५३	पिथौरागढ़ ..	२
२७	झांसी ..	२	५४	चमौली ..	२
				योग ..	२०६

*This appointment of Extension Guide in this District is under consideration.

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४०५ पर)

प्रश्न संख्या	उत्तर
३५—क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज के गोरखपुर रीजन में प्रति वर्ष कहां-कहां मेले लगते हैं और उनसे कितनी आय रोडवेज को १९५७–५८, १९५८–५९ तथा १९५९–६० में हुई है ?	राजकीय रोडवेज के गोरखपुर रीजन में बस्ती, बलरामपुर, बड़हलगंज, लाहरा, फैजाबाद, आजमगढ़, बहराइच, अयोध्या, दोहरीघाट, गाजीपुर, उजियारघाट, बलिया, देवरिया, अकबरपुर, बहखारी, ककरीघाट, सीतादवन, सिकन्दरपुर, तरकुलहा, नामक स्थानों पर प्रति वर्ष मेले लगते हैं। इन मेलों से रोडवेज को निम्नलिखित आय हुई :

		रु०
१९५७–५८	..	१,५६,३८९.६६
१९५८–५९	..	१,७२,३००.०७
१९५९–६०	..	५,०९,४८६.६९

३६—क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर रीजन में मेले की आमदनी से रोडवेज के कर्मचारियों को भी कुछ इनाम दिया जाता है ? यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में कितना रुपया कर्मचारियों को इनाम के रूप में दिया जा चुका है ?	जी नहीं। मेले में अधिक परिश्रम करने वाले कर्मचारियों को सन् १९५८–५९ में १,५१० रु० २५ नये पैसे आनरेरियम दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा